R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

# अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 23
01 से 15 सितंबर 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

## मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की जमावट

सत्ता और संगठन में बदलाव करेगी भाजपा

कांग्रेस भी संगठन में कसावट की तैयारी में

# जब दिल में हो जज़्बात

## तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत

Scan to watch
our latest film

WONDER CEMENT
EK PERFECT SHURUAAT

Toll-free No.: 1800 31 31 31 | wondercement.com

## इस अंक में

### प्रशासनिक


9 | आरोप पत्र में अटकी अफसरों की पेंशन

*मप्र में सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि एक अदने से कर्मचारी से लेकर बड़े-बड़े अफसर भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं।*


### चर्चा में


10-11 | सस्ती बिजली से बढ़ रहा कर्ज

*देश में इस समय मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम आदमी के बीच बहस चल रही है कि आखिर मुफ्त की रेवड़ियों पर लगाम कैसे लगेगी। गौरतलब है कि मप्र सहित देशभर में...*


### इकोनॉमी


14 | औद्योगिक हब बनेगा भोपाल

*मालवा के पीथमपुर की तरह मध्यभारत के भोपाल को औद्योगिक हब बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल, देश-विदेश के कई बड़े निवेशक भोपाल के आसपास औद्योगिक इकाईयां स्थापित करना चाहते हैं।*


### जंगलनामा


19 | अतिक्रमण की चपेट में जंगल

*देश को सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर देने वाले मप्र में जंगलों की 54 हजार 173 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण का शिकार है। इसमें ज्यादातर पर कब्जेधारियों ने पट्टा हासिल कर लिया है। चौंकाने वाली यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव...*


### आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

*पंचायत और निकाय चुनाव निपटने के बाद मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चौसर बिछने लगी है। भाजपा और कांग्रेस की कोशिश है कि 2023 में उनकी सरकार बने। ऐसे में मिशन 2023 के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस में जमावट शुरू हो गई है। भाजपा में सत्ता और संगठन में बदलाव की तैयारी चल रही है, वहीं कांग्रेस भी संगठन में कसावट करने में जुटी हुई है। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मिशन 2023 की रणनीति पर काम कर रहे हैं।*

### राजनीति


30-31 | मोदी की टक्कर में कौन-कौन?

*बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने भाजपा खेमा छोड़कर महागठबंधन में एंट्री कर ली है। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। इस तरह मोदी के विकल्प के रूप...*


### उत्तरप्रदेश


34 | योगी से नाराजगी!

*योगी आदित्यनाथ उप्र के दो बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन दिल्ली का भरोसा अब तक नहीं जीत पाए। भाजपा संसदीय बोर्ड में योगी आदित्यनाथ को एंट्री न दिया जाना और उसके पीछे सामने आ रही दलील तो यही कहती है। योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड में शामिल न किए...*


### बिहार


36 | नीतीश के मुकाबले...

*तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बताने वाले सर्वे ने पिछली बार उनको मिले शादी के हजारों प्रस्तावों की याद दिला दी है। फिर से बिहार के उपमुख्यमंत्री बन चुके तेजस्वी यादव को एक सर्वे में लोगों ने नीतीश कुमार के मुकाबले अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री...*

6-7 अंदर की बात
39 महिला जगत
41 अध्यात्म
42 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

# वो क्या जाने कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द झेला है...

किसी शायर ने कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर लिखा है।

**नेताओं ने सिर्फ राजनीतिक खेल खेला है।**
**वो क्या जाने कश्मीरी पंडितों ने जो दर्द झेला है।।**

वाकई कश्मीरी पंडितों की त्रासदी की दास्तान सुनकर हर किसी की आंखें भर आती हैं। विडंबना यह है कि हर सरकार बेघर हुए कश्मीरी पंडितों को पूरी सुरक्षा के साथ कश्मीर में ही बसाने के सपने दिखाती है। लेकिन आज तक इनको सुरक्षा नहीं मिल पाई है। वर्तमान केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसके जवाब में आतंकियों ने खून बहाया है। वर्तमान में कश्मीर में गैर-मुस्लिमों पर अचानक बढ़े हमलों के पीछे आतंकियों की बौखलाहट छिपी है। इसकी वजह कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जे हटाने की मुहिम भी है। आतंकवाद के कारण घाटी से पलायन करने वाले पंडितों की संपत्तियों से अवैध कब्जे छुड़ाने का अभियान हाल ही में शुरू किया गया था। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कश्मीरी पंडितों की जमीनों पर कब्जे की 8 हजार शिकायतों पर कार्रवाई की है। 1990 में आतंकवाद के भय से पलायन करने वाले पंडितों की जमीनें उनके पड़ोसियों ने ही हड़प रखी थीं। 32 साल बाद ऐसी 2414 कनाल यानी 302 एकड़ जमीन कब्जामुक्त करा ली गई है। लेकिन, सरकार की परेशानी यह है कि इन जमीनों के असल मालिक कब्जा लेने नहीं आ रहे हैं। कब्जे की सबसे ज्यादा शिकायतें अनंतनाग, कुपवाड़ा, बारामूला और बडगाम जिलों से मिली थीं। इन जिलों में पंडित बड़े जमींदार थे। कुछ ने डर के मारे संपत्ति बेच दी थी। लेकिन, कई पंडितों ने जमीनें देख-रेख के लिए पड़ोसियों को सौंपी थी। वक्त के साथ इन जमीनों पर भी कब्जे कर लिए गए थे। कश्मीर से कोसों दूर बैठे पंडित परिवार शिकायतें तो दर्ज कराते रहे, लेकिन उनकी जमीनों से कब्जे नहीं हटाए गए। इसलिए सालभर पहले प्रशासन ने कब्जा छुड़ाने के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया। इस पर कुल 8 हजार शिकायतें मिलीं। सभी पर कार्रवाई हुई। इस दौरान सामने आया कि कब्जाधारी पड़ोसी ही थे। सरकार ने कब्जे हटाने की मुहिम एक साल पहले शुरू की थी। इसके विरोध में आतंकी संगठनों ने पंडितों की टारगेट किलिंग शुरू कर दहशत का माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सरकार ने कब्जे छुड़ाने की मुहिम जारी रखी। अत्याचार के चलते घर छोड़ने को मजबूर हुए पंडित तीन दशक से कब्जे छुड़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे। 1997 में उनकी संपत्ति के संरक्षण और सुरक्षा के लिए 'जम्मू और कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम 1997' भी पारित किया गया। लेकिन, यह प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो सका। गैर-मुस्लिमों पर हमलों के चलते अब कुछ ऐसे पंडित परिवार भी घाटी छोड़कर जा चुके हैं, जो 1990 में भी नहीं गए थे। 1990 के बाद यह पहला मौका है, जब घर छोड़ने को मजबूर हुए पंडितों की जमीनों-मकानों से कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार के सामने परेशानी यह है कि जमीन छोड़कर गए कश्मीरी पंडित वापस आने को तैयार नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें अभी भी डर सता रहा है कि अगर वे कश्मीर गए तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। इसलिए सरकार को सबसे पहले कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। कश्मीर में इस समय भी जिस तरह के हालात हैं, उसे देखते हुए कोई भी दोबारा वहां जाने की हिमाकत नहीं करेगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकार कश्मीरी पंडितों की जो जमीनें छुड़ा रही है, उसका वह क्या करेगी? अपनी जमीन पर कश्मीरी पंडित फिर से तभी बसेंगे जब उन्हें सरकार पर्याप्त सुरक्षा का विश्वास दिला पाएगी।

**- राजेन्द्र आगाल**


पाक्षिक अक्स

**वर्ष 20, अंक 23, पृष्ठ-48, 1 से 15 सितंबर, 2022**

**प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल**

**सम्पादकीय कार्यालय :**
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 ( म.प्र. ),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

**ब्यूरो**
**कोलकाता:**- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

**प्रदेश संवाददाता**
094251 25096 ( इंदौर ) विकास दुबे
098276 18400 ( जबलपुर ) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, ( उज्जैन ) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, ( गंजबासौदा ) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, ( रतलाम ) सुभाष सोमानी
075666 71111, ( विदिशा ) मोहित बंसल

**क्षेत्रीय कार्यालय**
**नई दिल्ली :** ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
**जयपुर :** सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर ( राजस्थान ) मोबाइल-09829 010331
**रायपुर :** एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
**भिलाई :** नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
**इंदौर :** नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
**देवास :** जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

**स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित**



**इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।**

# पत्र–संपादक के नाम

## चुनावी तैयारियां शुरू

हाल ही में हुए पंचायत और निकाय चुनाव के बाद अब प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के साथ अन्य पार्टियां अपने–अपने स्तर पर चुनाव जीतने की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसके लिए बैठकों का दौर चल रहा है।

● **प्रेम सिंह,** सीहोर (म.प्र.)

## किसानों को राहत कब?

प्रदेश सहित देशभर के किसान दिन–रात एक कर खेती कर रहे हैं, लेकिन आए दिन किसानों को किसी न किसी तकलीफ से जूझना पड़ रहा है। किसानों की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए सरकार को किसानों के बीच जाकर उनसे पूछताछ करनी चाहिए।

● **मोहसीन खान,** भोपाल (म.प्र.)

## बढ़ता जा रहा है भ्रष्टाचार

देश से भ्रष्टाचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई भ्रष्टाचारी लाखों-करोड़ों के साथ पकड़ा जा रहा है। और तो और जनता के खून–पसीने की कमाई को भ्रष्टाचारी निगल रहे हैं। सरकार को इन भ्रष्टों के खिलाफ और अधिक कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है।

● **राकेश बंसल,** इंदौर (म.प्र.)




## विपक्ष के पास मुद्दे नहीं

देश में इन दिनों राजनीति अलग स्तर पर पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों के पास सत्तापक्ष को घेरने के लिए कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं। इसका पूरा फायदा सत्तापक्ष उठा रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां आम जनता के मुद्दों पर आधारित राजनीति नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि वे अपनी आपसी लड़ाई को तूल दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियां समय की धारा को पहचानने में चूक कर रही हैं। विपक्षी पार्टियां समझ नहीं पा रही हैं कि क्यों सत्तापक्ष पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में जमी हुई है और निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। सत्तापक्ष के लोग ये सब देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। सत्तापक्ष जिस चक्रव्यूह में विपक्षियों को फंसाना चाहता है, वे उसमें फंस रहे हैं।

● **शिखा वर्मा,** जबलपुर (म.प्र.)

## भारत मजबूत कर सकता है आर्थिक स्थिति

वैसे तो भारत और चीन का विवाद काफी सालों पुराना है। लेकिन इन दिनों दोनों देश एक-दूसरे से भिड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि चीन से बड़ी संख्या में व्यापारियों का दूसरे देशों में पलायन हो रहा है। इसका फायदा भारत को उठाना चाहिए। वैसे भी अब भारत की सैन्य क्षमताओं को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके साथ ही आर्थिक स्तर पर भी भारत खुद को दिन पर दिन मजबूत कर रहा है। ऐसे में चीन से पलायन करने वाले व्यापारियों को भारत बुलावा देकर अपनी आर्थिक स्थिति और मजबूत कर सकता है।

● **मनोहर पांडे,** नई दिल्ली

## मप्र मजबूत स्थिति में

अर्थव्यवस्था के लिहाज से मप्र इस समय काफी मजबूत राज्य के रूप में उभर रहा है। मप्र में इस समय सरकार की कई नीतियों को लागू कर विकास किया जा रहा है। वहीं कई उद्योगपति इन दिनों मप्र में अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं। इस समय कई राज्यों के मुकाबले मप्र काफी मजबूत स्थिति में है। प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है।

● **प्रिया मिश्रा,** राजगढ़ (म.प्र.)

## पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

**अक्स**

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

## हाथ का साथ छोड़ेंगे चव्हान

महाराष्ट्र में सियासी हलचल कम होती नहीं दिख रही है। अब नए कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बीच हुई बैठक ने चर्चाएं बढ़ा दी हैं। हालांकि दोनों नेता इसे शिष्टाचार बैठक बता रहे हैं। खबर है कांग्रेस और शिवसेना नेता के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात होती रही। खास बात यह है कि विश्वास मत के दौरान भी चव्हाण की गैरमौजूदगी भी चर्चा में रही थी। इसके बाद से कई अटकलें लगने लगीं हैं। राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अशोक चव्हाण कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं। ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं कि मंत्री अब्दुल सत्तार समीक्षा बैठक में शामिल होने के तुरंत बाद अशोक चव्हाण से मिलने उनके आवास पर गए। उन्होंने लगभग आधे घंटे तक एक कमरे में बात की, जहां किसी भी पार्टी कार्यकर्ता को अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि चव्हाण ने इस बैठक को लेकर लगाई जा रहीं अटकलों पर जवाब देते हुए कहा कि यह सत्तार की केवल शिष्टाचार भेंट थी। दो दलों के नेताओं के बीच बैठक में कुछ भी गलत नहीं है। दरअसल, हाल ही में चव्हाण के अपने पार्टी नेतृत्व से नाराज होने की खबरें आई थीं, जिसने उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था क्योंकि वह नवगठित एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ विश्वास मत के दौरान अनुपस्थित थे।

## कर्नाटक में नेतृत्व बदलेगी भाजपा!

कर्नाटक में एक बार फिर मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चा शुरू हो गई है। पिछले दिनों इसकी चर्चा चली तो पार्टी नेताओं ने इसे सिरे से खारिज किया था। इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने मुख्यमंत्री पद के लिए ढाई हजार करोड़ रुपए की लेन-देन का एक शिगूफा छोड़ फिर नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा को हवा दे दी है। यह चर्चा प्रदेश के सबसे बड़े नेता और दशकों से लिंगायत जाति का चेहरा रहे बीएस येदियुरप्पा के भाजपा के संसदीय बोर्ड में शामिल होने के बाद शुरू हुई है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने सबसे बड़े लिंगायत नेता को अपनी सर्वोच्च ईकाई का सदस्य बना दिया तो फिर लिंगायत मुख्यमंत्री रखने की क्या जरूरत है? दरअसल मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से हैं और येदियुरप्पा की सहमति से उनको बनाया गया था। अब भाजपा प्रदेश में लिंगायत बनाम वोक्कालिगा और लिंगायत बनाम ओबीसी का संतुलन बनाने की संभावना तलाश रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी किसी वोक्कालिगा नेता को मुख्यमंत्री बनाकर दोनों बड़ी जातियों को साध सकती है। हालांकि इसमें समस्या यह भी बताई जा रही है कि विपक्ष की दोनों बड़ी पार्टियों के पास मजबूत वोक्कालिगा नेता हैं। जेडीएस तो वोक्कालिगा समुदाय की ही राजनीति करती है और देवगौड़ा परिवार उसी समुदाय से आता है। एचडी देवगौड़ा उस समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं।

## बदलने लगी पूर्वोत्तर की फिजा

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्वोत्तर में अभी से चुनावी फिजा बदलने लगी है। पूर्वोत्तर में जनता दल के जमाने से ही समाजवादियों का एक असर रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी कम से कम तीन राज्यों-मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अच्छी स्थिति में रही है। अरुणाचल प्रदेश के उसके 6 विधायकों को भाजपा ने तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। इस साल हुए चुनाव में नीतीश की पार्टी के 6 विधायक जीतकर आए थे उनके पाला बदलते ही पूर्वोत्तर में हवा बदलने लगी है। मणिपुर में ही पहले कांग्रेस के 5 और 1 निर्दलीय विधायक का विपक्ष था, जो अब 11 विधायक का हो गया है। इस बीच खबर है कि मेघालय और नागालैंड दोनों राज्यों में भाजपा की सहयोगी पार्टियां तेवर दिखाने लगी हैं। मेघालय में 5 पार्टियों की सरकार का नेतृत्व कर रहे एनपीपी के नेता कोनार्ड संगमा ने कहा है कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले चुनाव में भाजपा से गठबंधन नहीं करेगी। भाजपा अभी सरकार का हिस्सा है लेकिन संगमा ने साफ कर दिया है कि दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ेंगी। वहीं नागालैंड में भी भाजपा की सहयोगी एनडीपीपी ने भाजपा में विलय की खबरों को खारिज कर दिया है।

## खत्म होगा चिराग का वनवास

बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के चलते अटकलें लगाई जानी लगी हैं कि चिराग पासवान का वनवास खत्म हो गया है। नीतीश कुमार की चिंता में भाजपा ने उनको किनारे रखा था और दिल्ली में उनके पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगला भी खाली करा लिया था। 6 सांसदों वाली उनकी पार्टी भी टूट गई थी, जिसके तहत उनके चाचा 5 सांसदों को लेकर अलग हो गए थे और नीतीश कुमार की पैरवी से केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए थे। अगर चिराग पासवान का वनवास खत्म होता है और एनडीए में पुनर्वास होता है तो पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उनको तय करना होगा कि वे केंद्र में मंत्री बने रहते हैं या बिहार की राजनीति के लिहाज से पोजिशनिंग करते हैं। अगर वे केंद्र में मंत्री बने रहने की सोचते हैं तो फिर भतीजे के साथ समझौता करना होगा। खबर है कि बिहार में जैसे ही जदयू और भाजपा के बीच विवाद शुरू हुआ और नीतीश कुमार के यूटर्न के बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि चिराग भाजपा के साथ जाने के लिए सक्रिय हो गए हैं।

## संकट में गुजरात कांग्रेस

गुजरात विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बाकी है। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रही कांग्रेस को नया झटका लग सकता है। खबर है कि सौराष्ट्र में कुछ कांग्रेस विधायक जल्द ही भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता नरेश रावल और राजू परमार ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया था। खबर है कि गुजरात कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इन विधायकों के चुनाव के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की थी। फिलहाल कांग्रेस उनकी मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं है। कहा जा रहा है कि अब वह पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। इसके लिए भावेश कटारा, चिराग कलगरिया, ललित वसोया, संजय सोलंकी, महेश पटेल और हर्षद रिबादिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल से मुलाकात कर चुके हैं। खास बात है कि इन 6 नेताओं में से 4 पाटीदार हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर पार्टी छोड़ने से कांग्रेस खासी प्रभावित हो सकती है। इससे पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था।

## काम किसी और का... नाम साहब का

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में एक प्रमोटी आईएएस इन दिनों अफसरों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसकी वजह है साहब की कुछ किताबों का लेखन। दरअसल, पिछले कुछ सालों के दौरान साहब की कुछ किताबें प्रकाशित हुई हैं। इन किताबों के प्रकाशन के बाद साहब ने मीडिया से लेकर प्रशासनिक वीथिका में यह हवा उड़ाई कि उन्होंने रात-दिन मेहनत करके इन किताबों को लिखा है। साहब की लेखन कला पर उनके कई सहयोगी उनका लोहा मानने लगे। बात प्रशासनिक वीथिका से निकलते हुए जब राजधानी की गलियों में फैली तो एक दिन हकीकत सामने आ गई। सूत्रों का कहना है कि साहब की लेखन कला की हकीकत यह है कि काम किसी और का... नाम साहब का। यानी साहब की किताबें लिखता कोई और है और साहब उसे अपने नाम से छपवा लेते हैं। जब खबरचियों को यह बात पता लगी तो उन्होंने इसकी पड़ताल कराई तो यह तथ्य सामने आया कि राजधानी के एक लाइब्रेरियन से साहब किताबें लिखवाते हैं और उसे अपने नाम से प्रकाशित करवा देते हैं। बताया जाता हे कि साहब किताबों के लिखने वाले लाइब्रेरियन को बकायदा भुगतान भी करते हैं। यहां बता दें कि 2003 बैच के ये साहब अपने महिला प्रेम के लिए भी खासे ख्यात रहे हैं। साहब इन दिनों एक संभाग में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और बताया जाता है कि साहब वहां भी अपनी प्रेमलीला जारी रखे होंगे।

## ससुरा बना वसूली भाई

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक आईपीएस अधिकारी के ससुर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल, फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल के पात्र वसूली भाई की तरह साहब के ससुर भी वसूली अभियान में लगे हुए हैं। बताया जाता है कि साहब के ससुर ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए डीएसपी की नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया है। अभी चुनावी दाल गल नहीं पा रही है, इसलिए साहब के ससुर ने उनके जिले में वसूली का अभियान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि साहब निमाड़ के एक छोटे से जिले में पुलिस मुखिया हैं। बताया जाता है कि साहब जबसे जिले के पुलिस मुखिया बने हैं तब से ही उनके ससुर ने वसूली का काम शुरू कर दिया है। साहब के ससुर अपने पुराने अनुभवों के आधार पर इस छोटे से जिले में भी जमकर उगाही कर रहे हैं। यही नहीं सूत्रों का कहना है कि अपने दामाद को ऊर्जाधानी का एसपी बनाने के लिए ससुर साहब ने कमर कस ली है। इसके लिए वे साम-दाम-दंड-भेद की नीति का सहारा भी ले रहे हैं। अब देखना यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर जिले से संपन्न जिले का एसपी बनाने में वे सफल हो पाते हैं या नहीं।

## धमक और चमक

प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में यह माना जाता है कि प्रमोटी आईएएस में प्रशासनिक क्षमता कम रहती है। वे हमेशा सहमे रहते हैं, लेकिन इस मान्यता को एक प्रमोटी आईएएस ने आईना दिखाया है। प्रदेश के सबसे संपन्न और विकसित जिले में कलेक्टरी कर रहे साहब की चमक और धमक ऐसी है कि उनके इशारे पर ही सारा काम हो जाता है। 2009 बैच के प्रमोटी आईएएस अधिकारी ने जबसे जिले की कमान संभाली है, जिले की शक्ल-सूरत और सीरत पूरी तरह बदल गई है। साहब ने जिले की कानून व्यवस्था तो चुस्त-दुरुस्त की ही है, जिले को विकास की राह पर भी इस कदर दौड़ाया है कि आज जिला निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब साहब के सामने चुनौती के रूप में जनवरी में शुरू होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है। तिथियों की घोषणा होते ही साहब ने व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है और आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए गत दिनों साहब ने शहर के होटल वालों के लिए फरमान जारी कर दिया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में भूल जाएं कि होटल आप लोगों का है। इसी बीच एक नामचीन होटल के प्रबंधक ने बोला कि मैंने तो इस तिथि के बीच में शादी के लिए 50 लाख रुपए में बुकिंग कर ली है। साहब ने उसे सबक सिखाने के लिए कहा कि तो ऐसा है, तुम उस व्यक्ति को 1 करोड़ लौटा देना। अगर आगे बुकिंग की तो तुम्हारे मालिक को बता देना। यह मैसेज आते ही कोई होटल का प्रबंधक सवाल नहीं कर पाया।

## न खुदा मिला... न सनम

न खुदा मिला न विसाल-ए-सनम यह शेर तो आपने कई बार सुना होगा। वर्तमान में यह शेर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर सटीक बैठ रहा है। प्रमुख सचिव की कुर्सी पर बैठे साहब का हाल ही में तबादला कर दिया गया। जब इसकी वजह सामने आई तो हर कोई चौंक गया। बताया जाता है कि साहब का महिला प्रेम के कारण तबादला हुआ है। जानकारी के अनुसार साहब की छवि शुरू से महिला प्रेम की रही है। उन्होंने इस बार विभाग में पदस्थ कुछ महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनसे मनुहार भरी बातें की, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाई। उल्टे साहब को विभाग से जाना पड़ा। वैसे साहब के बारे में यह ख्यात है कि वे कहीं टिकते नहीं हैं। उन्हें जिस विभाग में भी पदस्थ किया जाता है, वे वहां कुछ ही दिन कार्य कर पाते हैं। यही नहीं साहब के बारे में यह भी कहा जाता है कि सरकार उन्हें सुस्त विभागों में ही पदस्थ करती है। यानी जो विभाग सरकार की प्राथमिकता में नहीं रहते साहब को उन्हीं विभागों में पदस्थ किया जाता है। लेकिन साहब अपने चरित्र के कारण किसी भी विभाग में अधिक दिन तक टिक नहीं पाते हैं।

## आखिर इशारा किस ओर?

प्रदेश में इन दिनों एक नेताजी की श्रीमती जी का ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। जिन मैडम ने यह ट्वीट किया है, वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। वे अलंकार और अनुप्रास का प्रयोग भलीभांति जानती हैं। विगत दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर दो पोस्ट डाले। एक में उन्होंने लिखा, *हर व्यक्ति जो निकट है जरूरी नहीं कि आपका हित...सोचे। और ना ये आवश्यक है कि वो आपकी खुशी में आनंद...दे।* शुभ-चिंतक वो नहीं हो सकता जो आपका शुभ होता देख चिंता में पड़ जाए। इस ट्वीट के बाद मैडम के पति की पार्टी में तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे। ट्वीट के शब्दों को जोड़कर लोग अर्थ-अनर्थ निकालने लगे हैं। फिर भी लोग अनजान बनकर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इशारा किस ओर किया जा रहा है। वहीं मैडम का एक और पोस्ट भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि *अगर क्षमा दे तो वो राम। अगर दंड दे तो परशुराम। अब हमें निसंदेह परशुराम हो जाना चाहिए। अब थोड़ा रक्त खौलना चाहिए।* इस पोस्ट के बाद लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिरकार मैडम क्या चाहती हैं।

घर वालों ने घर छोड़ने के लिए जबरन मजबूर किया। जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए, तो अकलमंदी खुद घर छोड़ने में है। जो शख्स अपनी स्पीच खत्म करने के बाद सदन में पीएम से गले मिले, तो बताइए वे मिले हैं या मैं मिला हूं।

● **गुलाम नबी आजाद**

मौजूदा केंद्र सरकार आजादी के 75 साल की सबसे भ्रष्ट सरकार है। 10 लाख करोड़ रुपए इनके दोस्त खा गए। 6300 करोड़ में इन्हें विधायक खरीदे और लाल किले से कहते हैं- मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। इन्होंने महाराष्ट्र, मप्र और गोवा में पैसे के दम पर ऑपरेशन लोटस चलाया है। अब झारखंड में भी कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में इनकी कोशिश फेल हो गई।

● **अरविंद केजरीवाल**

इस समय भारतीय क्रिकेट का स्वर्णकाल चल रहा है। भारत में हर किस्म के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की इतनी भरमार हो गई है कि चयनकर्ता के सामने टीम चुनने में कई अड़चने आ रही हैं। आज स्थिति यह है कि अगर एक-दो प्रमुख खिलाड़ी चोटिल होकर टीम से बाहर हो जाते हैं तो भी किसी के माथे पर शिकन नहीं आती, क्योंकि बेंच भी मजबूत होती है।

● **संजय मांजरेकर**

हमारी एकता और देशभक्ति ने रूस जैसे महाशक्ति को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि उससे उभरने में उसे कई साल लग जाएंगे। रूस ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन वह हमें झुकाने में कामयाब नहीं हो पाया है। यही उसकी हार है।

● **वोलोदिमीर जेलेंस्की**

इस देश में कुछ नया करना भी गुनाह जैसा हो जाता है। मैं भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच देखने क्या पहुंची, लोग उसके तरह-तरह के मायने निकालने लगे। मैं तो आज भी कहती हूं कि मैं क्रिकेट बिलकुल नहीं देखती। मैं किसी क्रिकेटर को भी नहीं जानती। हालांकि मैं सचिन तेंदुलकर सर और विराट कोहली सर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। अब मैं क्रिकेट को जानने और समझने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन लोग मेरी इस कोशिश को अलग नजरिए से देख रहे हैं। तो यहां बता दूं कि मैं किसी की परवाह नहीं करती, मुझे जो करना है वह मैं करके रहती हूं।

● **उर्वशी रौतेला**

# वाक्युद्ध

भ्रष्ट नेताओं के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार का गठन किया गया है। नई सरकार के गठन के साथ ही प्रदेश में अपराधियों के हौंसले बुलंद हो गए हैं। यह सब नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनने की लालसा के कारण हो रहा है। सुशासन बाबू के राज में अब विकास नहीं बिहार का विनाश होने जा रहा है।

● **सुशील मोदी**

मैं चाहता हूं कि हमारे पुराने साथी सुशील मोदी मेरे खिलाफ खूब बोलें और बोलते रहें, ताकि अगर गठबंधन फिर टूटे और भाजपा की सरकार बने तो उन्हें सरकार में जगह मिल जाए। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जब उनकी पार्टी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा तो मैंने उनकी निरंतर चिंता की है। शायद अब वह भूल गए हैं।

● **नीतीश कुमार**

# आरोप पत्र में अटकी अफसरों की पेंशन

## वी मधुकुमार, संजय माने, सुशोभन बनर्जी अधर में

मप्र में लोकसभा चुनाव के दौरान हुए काले धन के लेन-देन मामले में फंसे तीन आईपीएस अधिकारियों वी मधुकुमार, संजय माने और सुशोभन बनर्जी को भी सरकार ने आरोप पत्र देकर उनकी पेंशन और तनख्वाह आधी कर दी है। पोल कैश मामले में तीनों आईपीएस अधिकारियों पर मप्र में हुए साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान अपने निजी वाहनों से भोपाल से दिल्ली करोड़ों रुपए लेकर जाने के आरोप हैं। आयकर विभाग की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें साफ तौर पर आईपीएस अधिकारी सुशोभन बनर्जी के नाम के आगे 25 लाख रुपए की राशि लिखी हुई है। इसी तरह आईपीएस अधिकारी संजय माने के नाम के आगे 30 लाख रुपए की राशि लिखी हुई है। तो वहीं आईपीएस अफसर वी मधुकुमार के नाम के सामने 12.50 करोड़ और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा के नाम के आगे 7.5 करोड़ रुपए की राशि लिखी हुई है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी अधिकारियों ने भोपाल से दिल्ली यह रुपए पहुंचाए हैं। जब आयकर विभाग की शीर्ष संस्था ने इन पूरे दस्तावेजों की जांच की तो काले धन के लेन-देन के पुख्ता सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे, जिसके बाद आयकर विभाग ने एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंपी, जिस पर चुनाव आयोग ने ईओडब्ल्यू को इस मामले में प्राथमिक जांच दर्ज करने के आदेश दिए। चुनाव आयोग के आदेशों पर अब इस मामले में ईओडब्ल्यू ने प्राथमिक जांच दर्ज कर एसआईटी का गठन कर दिया है। लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई है।

मप्र में सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि एक अदने से कर्मचारी से लेकर बड़े-बड़े अफसर भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। प्रदेश में ऐसे ही कुछ आईपीएस अधिकारी हैं जिनके खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए हैं, जिससे उनको आधी पेंशन मिल रही है। वहीं कुछ ऐसे आईपीएस भी हैं, जिनके खिलाफ नौकरी में रहते आरोप पत्र दिया गया है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वरिष्ठ अफसरों की बाबूगिरी और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कुछ अफसरों के आरोप में निर्णय नहीं हो पा रहा है। इन अफसरों में कोई खरीदी, कोई सीबीडीटी जांच, तो कोई अव्यवहारिक लेन-देन के मामले में दोषी पाया गया है। हैरानी की बात यह है कि सरकार वर्षों से चल रहे इन मामलों में अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है।

इन अफसरों में 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी **महान भारत** का नाम भी शामिल है। महान भारत पर होमगार्ड में रहते हुए नीली कैप खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप है। सूत्रों के अनुसार इन पर 10 से 15 लाख रुपए के भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। इस आरोप के कारण जब ये 30 सितंबर 2020 को रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के बाद इनको आधी पेंशन ही दी जा रही है। इसी तरह **सीएस मालवीय** को भी आरोप पत्र भेजकर आधी पेंशन दी जा रही है। इन पर आरोप है कि कमांडेंट रहते इन्होंने अपनी डेयरी में जवानों से काम करवाया था। वहीं कमांडेंट रहते अनियमितता के मामले में **रघुवीर सिंह मीना** को भी आधी पेंशन दी जा रही है। मीना 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हुए थे। वहीं 2003 बैच के प्रमोटी आईपीएस अधिकारी **अखिलेश झा** जुलाई 2020 में रिटायर हो गए, लेकिन उनके खिलाफ बिना परमिशन अलीराजपुर में एसपी रहते हुए गुंडा स्क्वाड संचालित करने का जो मामला था, उसको लेकर उन्हें भी आधी पेंशन दी जा रही है। इस मामले में एडीजी विपिन माहेश्वरी ने कार्यवाही की थी। रिटायर्ड आईपीएस अफसर अखिलेश झा कुछ सालों पहले इंदौर पुलिस जोन के अलीराजपुर जिले में पुलिस अधीक्षक थे। इस दौरान इंदौर आईजी ने गुंडा स्क्वाड भंग करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी अलीराजपुर जिले में गुंडा स्क्वाड चलता रहा। गुंडा स्क्वाड ने पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने उस दौरान जांच की थी। जिसमें अखिलेश झा को आरोप पत्र दिया गया था।

1996 बैच के आईपीएस अधिकारी **पीके माथुर** भी 2016 में रिटायर हो गए हैं। लेकिन अभी भी उनको आधी पेंशन ही दी जा रही है। दरअसल, जब गृह विभाग ने इस साल रिटायर होने वाले आईपीएस अफसरों की सूची जारी की तो उसमें पीके माथुर का नाम नहीं था। दस्तावेज खंगालने पर गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय के सर्विस रिकॉर्ड के दस्तावेजों में माथुर की जन्मतिथि में हेराफेरी होना पाई गई थी। दस्तावेजों में पाया गया कि पीके माथुर ने ज्वाइनिंग के समय सरकारी दस्तावेजों में अपनी जन्मतिथि 4 जुलाई 1956 बताई थी, जिसे बाद में उन्होंने 4 जुलाई 1959 करवा ली। खुलासा होने के बाद मामले में विभागीय जांच के आदेश दिए, जिसमें माथुर पर लगे आरोप की पुष्टि हो गई।

मप्र की शिवराज सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सचिवालय से लेकर प्रदेश के अधिकांश मलाईदार पदों पर, ऐसे आईएएस अधिकारी काबिज हैं, जिनके खिलाफ लोकायुक्त से लेकर ईओडब्ल्यू तक में भ्रष्टाचार की जांच चल रही है। खास बात यह है कि यही वे अफसर हैं, जो न केवन नीति नियंता हैं, बल्कि उनके जिम्मे ही कानून का पालन कराना होता है। सरकार द्वारा दी गई अधिकृत जानकारी के अनुसार मप्र के कई दर्जनों आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों में जांच चल रही है। जांच के दायरे में आए अफसरों में सबसे ज्यादा संख्या आईएएस अफसरों की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अफसर रिटायर हो जाते हैं और उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी नहीं हो पाती है।

● **सुनील सिंह**

*देश में इस समय मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम आदमी के बीच बहस चल रही है कि आखिर मुफ्त की रेवड़ियों पर लगाम कैसे लगेगी। गौरतलब है कि मप्र सहित देशभर में सबसे अधिक छूट बिजली पर दी जा रही है। साल 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक 22,108 करोड़ की सब्सिडी दी। उसके बाद मप्र ने 19,595 करोड़, राजस्थान ने 6,545 करोड़, दिल्ली ने 3,149 करोड़ और मणिपुर ने 269 करोड़ की सब्सिडी दी है। ह*

# सस्ती बिजली से बढ़ रहा कर्ज

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली क्षेत्र की प्रगति को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ देश का ध्यान खींचा है। आर्थिक विकास में बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए, उन्होंने राज्य सरकारों से बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का बकाया भुगतान करने की अपील की है। डिस्कॉम का नुकसान और बकाया एक गंभीर समस्या है। पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 29 में डिस्कॉम घाटे में चल रही हैं।

2019-20 तक, डिस्कॉम का कुल घाटा 5 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, और उनकी उधारी वर्ष 2010-20 की तुलना में ढाई गुना बढ़ गई। कोरोना महामारी के दौरान डिस्कॉम के नुकसान और कर्ज में और बढ़ोतरी हो गई है। डिस्कॉम के संकट का एक प्रमुख कारण 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है, जिसमें सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से लंबित भुगतान/सब्सिडी की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत, और निजी उपभोक्ताओं (मुख्य रूप से घरेलू कनेक्शन) का बकाया 30 प्रतिशत है।

इसे हल करने के लिए राज्यों और डिस्कॉम को इन तीन प्रमुख उपायों पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पहला, छह राज्यों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन पर डिस्कॉम के लंबित भुगतान का तीन-चौथाई हिस्सा बकाया है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मप्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उप्र शामिल हैं। सरकारी विभागों से डिस्कॉम के बकाये का निपटान करने के लिए, संबंधित राज्य अपने बजटीय आवंटन में से चरणबद्ध रूप से अग्रिम कटौती करने के बारे में विचार कर सकते हैं।

दूसरा, राज्यों को अपने सीमित वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग और बिजली को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की संस्कृति बनाने के लिए बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और लक्षित करने की दिशा में काम करना चाहिए। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) के अध्ययन के अनुसार, 7 राज्यों को छोड़कर, 2016-20 के दौरान अधिकांश राज्यों में बिजली दर (टैरिफ) में सब्सिडी पर निर्भरता में बढ़ोतरी हुई है।

मप्र, बिहार, राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक उन शीर्ष राज्यों में शामिल हैं, जहां डिस्कॉम अपने कुल राजस्व के 30 प्रतिशत या उससे ज्यादा हिस्से के लिए टैरिफ सब्सिडी पर निर्भर हैं। बिजली पर सब्सिडी में बढ़ोतरी, राज्यों की पहले से तंग चल रही वित्तीय स्थिति और ज्यादा बिगाड़ रही है। इसलिए, राज्यों को केवल कमजोर और योग्य उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी देनी चाहिए। इसके अलावा, राज्यों को पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों के बीच सोलर पंप जैसे सिंचाई के साधनों को बढ़ावा देना चाहिए।

तीसरा, डिस्कॉम को हाल ही में शुरू की गई 'रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर' (आरडीएस) योजना के तहत उपलब्ध विभिन्न वित्तीय और तकनीकी मदद का पूरी सक्रियता के साथ लाभ उठाना चाहिए। तीन लाख करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2025 तक डिस्कॉम को अपना घाटा 12-15 प्रतिशत तक घटाने में मदद करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए डिस्कॉम को अपने सभी बिजली कनेक्शन के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत है।

## डिस्कॉम पर 60 हजार करोड़ का कर्ज

रिसर्च फर्म इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का खराब प्रदर्शन पिछले वित्तीय वर्ष (2021-22) में जारी रहा और उनका घाटा 2019-20 में 34,500 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर लगभग 59,000 करोड़ रुपए हो गया। घाटे के कारण डिस्कॉम बिजली पैदा करने वाली कंपनियों का पैसा समय से नहीं चुका पाती। इन्हें घाटे से उबारने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। बकाया बढ़ने के कारण बिजली कंपनियों का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा जाता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि विभिन्न राज्यों पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। उन्हें यह पैसा बिजली उत्पादन कंपनियों को देना है। डिस्कॉम्स पर कई सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों का 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। राज्यों में बिजली पर सब्सिडी के लिए जो पैसा दिया गया है, वह इन कंपनियों को समय पर और पूरा नहीं मिल पा रहा है। यह बकाया भी 75,000 करोड़ रुपए से अधिक है। बिजली उत्पादन से लेकर डोर-टू-डोर डिलीवरी की जिम्मेदार कंपनियों के करीब ढाई लाख करोड़ फंसे हैं।

भारत, पहले ही कई तरीकों से ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के मामले में अपने नेतृत्व को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर चुका है। इसमें रिकॉर्ड समय में गांवों और घरों का विद्युतीकरण, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक बनने जैसी उपलब्धियां शामिल हैं। अब हमारे पास और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। अब हम 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा की उत्पादन क्षमता स्थापित करना, और 2070 तक नेट-जीरो (कार्बन न्यूट्रल) अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। इन लक्ष्यों को पाने के लिए, राज्यों को निश्चित तौर पर केंद्र के साथ मिलकर बिजली क्षेत्र को स्वस्थ व मुश्किलों को सहने में सक्षम बनाना होगा।

फ्रीबीज के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इन फ्रीबीज में भारत में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा बिजली सब्सिडी का है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार मुफ्त बिजली देती है। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली का वादा किया था। कई अन्य राज्यों में भी बिजली पर सब्सिडी दी जाती है। उधर, देश में पूरा बिजली सेक्टर घाटे में है और ज्यादातर वितरण कंपनियों के कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सब्सिडी का इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर ही बिजली क्षेत्र में घाटे के लिए जिम्मेदार है? सरकारों का बिजली पर सब्सिडी देना सही है या नहीं? बिजली कंपनियों को हो रहे नुकसान से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? अगर ऐसे ही बिजली कंपनियों को नुकसान होता रहेगा तो भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होगा?

गौरतलब है कि किसी भी चीज पर सरकार की तरफ से दी जाने वाली छूट को सब्सिडी कहते हैं। यह सरकार के नॉन-प्लान्ड खर्चों का एक हिस्सा होता है। दुनियाभर में सरकारें अपने नागरिकों को अलग-अलग चीजों पर सब्सिडी देती है। भारत में प्रमुख सब्सिडी पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, फूड, इलेक्ट्रिसिटी पर मिलती है। कई अर्थशास्त्री कहते हैं, अगर सब्सिडी किसी देश की समग्र अर्थव्यवस्था में सुधार करने में विफल रहती है, तो सब्सिडी एक विफलता है।

बिजली सब्सिडी कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं के साथ पावर और हैंडलूम जैसे कुटीर उद्योगों और ग्राम पंचायतों को दी जाती है। इसके अलावा कई राज्यों में इंडस्ट्री और बिजनेस को भी बिजली सब्सिडी दी जा रही है। वसुधा फाउंडेशन के सीईओ श्रीनिवास कृष्णास्वामी कहते हैं कि जैसे-जैसे बिजली की खपत बढ़ती है वैसे-वैसे सब्सिडी कम होती जाती है और टैरिफ बढ़ता है। ऐसे में अधिक खपत वाले कई उपभोक्ताओं को बिजली ऊंची दर पर मिलती है।

पावर मिनिस्ट्री के आंकड़ों से पता चलता है कि 36 में से 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाली बिजली प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 1.32 लाख करोड़ रुपए देशभर में अकेले 2020-21 वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए हैं। मप्र, राजस्थान और कर्नाटक ने 36.4 प्रतिशत या 48,248 करोड़ की सबसे ज्यादा बिजली सब्सिडी दी। तीन साल के डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि दिल्ली ने 2018-19 और 2020-21 के बीच अपने सब्सिडी एक्सपेंडिचर में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी। ये 2018-19 में 1,699 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 3,149 करोड़ रुपए हो गई। ये सभी राज्यों में दूसरी सबसे अधिक है। मणिपुर ने इन तीन वर्षों में बिजली सब्सिडी में सबसे बड़ी 124 प्रतिशत की उछाल देखी गई। 120 करोड़ रुपए से बढ़कर ये 269 करोड़ पर पहुंच गई।

देश के अलग-अलग राज्यों में सब्सिडी के अलग-अलग ब्रैकेट हैं। दिल्ली और पंजाब में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, तो हरियाणा में 150 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। झारखंड में भी 200 यूनिट तक बिजली फ्री है और उसके बाद खर्च बढ़ने के साथ सब्सिडी के स्लैब तय किए गए हैं। राज्यों पर फरवरी 2022 में पावर जनरेटिंग कंपनियों का 1,00,931 करोड़ रुपए का बकाया था। मार्च 2021 में ये 67,917 करोड़ था। बिजली तीन स्टेज से होकर हम तक पहुंचती है। पहली स्टेज प्रोडक्शन, दूसरी ट्रांसमिशन और तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज होती है। बिजली का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को जेनकोज कहा जाता है। जेनकोज बिजली को ट्रांसमिशन करने वाली कंपनियों यानी ट्रांसकोज को भेजती है। फिर ट्रांसमिशन कंपनियां बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियों (डिस्कॉम्स) तक पहुंचाती हैं। यह कंपनियां ही आपके घरों तक बिजली पहुंचाती हैं।

● **कुमार राजेन्द्र**

## केंद्र की रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम मप्र में भी होगी लागू

प्रदेश में बिजली चोरी को रोकने के लिए अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की रिवेम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों की कार्ययोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें कंपनियां बिजली बिल की अग्रिम राशि पाने के लिए प्रीपेड मीटर को बढ़ावा देगी। फिलहाल कंपनियों को बिजली आपूर्ति के डेढ़ महीने बाद राशि का भुगतान प्राप्त होता है। वर्ष 2025 तक सभी उपभोक्ताओं के मीटर को प्रीपेड स्मार्ट मीटर में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए योजना तैयार की है। इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी और 40 प्रतिशत राशि राज्य को लगानी होगी। इसके आधार पर ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रोजेक्ट में 14,886 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कंपनियों द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मीटरिंग पर 8,736 करोड़, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम करने 9,265 करोड़ तथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आधुनिकीकरण पर 5,909 करोड़ खर्च होंगे। स्मार्ट मीटर लगने पर उपभोक्ता मोबाइल फोन, टीवी चैनल्स की तर्ज पर अब बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ता जितनी राशि जमा करेंगे, उतनी ही बिजली जला सकेंगे। राशि खत्म होने पर अपने आप बिजली बंद हो जाएगी। अगले तीन साल में यह प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इस योजना पर करीब 8,736 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। जिसमें केंद्र सरकार 1,462 करोड़ का अनुदान देगी। इसके तहत विद्युत वितरण कंपनियों की 24,170 करोड़ की कार्य योजना को स्वीकृति दी गई है।

# सोलंकी को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

मप्र में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में आदिवासी, ओबीसी और दलित वोट सत्ता के लिए सबसे जरूरी है। ऐसे में भाजपा आलाकमान मप्र के आदिवासी सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। गौरतलब है कि मप्र में आदिवासी बहुल करीब 100 विधानसभा सीटें हैं। इन सीटों को साधने के लिए पार्टी सोलंकी पर बड़ा दांव खेल सकती है।

गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों से प्रदेश की सियासत आदिवासी समुदाय के इर्द-गिर्द ही दिखाई दे रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जंबूरी मैदान में तेंदूपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल हुए थे उसी मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनजातीय गौरव दिवस में शिरकत कर चुके थे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार आदिवासियों पर फोकस किए हुए हैं। इन सबके बावजूद आलाकमान की कोशिश है कि प्रदेश में एक ऐसे आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाया जाए, जिससे इस वर्ग का वोट पार्टी को थोकबंद मिल सके। इसकी वजह यह है कि 2018 में भाजपा आदिवासी समाज के वोट न मिलने के कारण ही सत्ता से बाहर हुई थी।

प्रदेश में आदिवासियों को लेकर तीन बड़े कार्यक्रमों से निकले संकेतों को देखें तो साफ है कि आगामी 2023 के चुनाव में 22 प्रतिशत आदिवासी वोट बैंक को साध कर ही भाजपा सत्ता वापसी का दावा मजबूत करने के प्रयास में है। मप्र में आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) वर्ग की 47 सीटें हैं। साथ ही सामान्य वर्ग की 31 सीटें ऐसी हैं, जहां आदिवासी वोटर निर्णायक हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि भाजपा आदिवासी चेहरे पर मुख्यमंत्री पद का दांव खेलने की दिशा में आगे बढ़ने लगी है। यही कारण है कि आदिवासी सांसद सुमेर सिंह अचानक से सियासी सुर्खियों में आ गए हैं। सांसद सुमेर सिंह ने बीते दिनों सपरिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी।

डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी निमाड़ अंचल के बारेला आदिवासी हैं जो आबादी के लिहाज से आदिवासियों की बड़ी उपजाति में एक है। प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कमलनाथ सरकार को गिरा भाजपा में शामिल हुए थे तब उन्हें राज्यसभा सीट दिए जाने की बात तय हुई थी। उनके साथ दूसरी राज्यसभा सीट पर कई दिग्गज नामों की चर्चा के बीच भाजपा ने साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले 45 साल के सुमेर सिंह सोलंकी पर दांव खेल चौंका दिया था। इस तरह प्रोफेसर सुमेर सिंह नौकरी से इस्तीफा देकर पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। सुमेर सिंह सोलंकी को संघ की पसंद का भी माना जाता है। सांसद बनने से पहले सुमेर सिंह सोलंकी आदिवासी इलाके में आरएसएस के साथ जुड़कर सामाजिक स्तर पर सक्रिय रह चुके हैं। कमजोर परिस्थिति के बाद भी सुमेर सिंह सोलंकी ने संघर्षों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की और प्रोफेसर बने। कहा जाता है कि सुमेर सिंह सोलंकी अपने ब्लॉक के इकलौते पीएचडी होल्डर हैं। आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद के तहत ही आदिवासी बहुल सीट जोबट में चुनाव जीतीं सुलोचना रावत को भी कैबिनेट में शामिल किए जाने की चर्चाएं हैं। सुलोचना रावत उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा के साथ आ गईं थीं। तब सुलोचना रावत को दलबदल के समय मंत्री बनाए जाने का आश्वासन दिए जाने की बात भी सामने आई थी।

भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार सुमेर सिंह सोलंकी को आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है। यही कारण है कि उन्हें कई तरह की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। दरअसल, प्रदेश के आदिवासियों के बीच बढ़ी कांग्रेस की पैठ और जयस के बढ़ते रूप को देखते हुए भाजपा सुमेर सिंह सोलंकी को आगे लाना चाहती है, ताकि आदिवासी वोटबैंक भाजपा की ओर आ सके। हालांकि सोलंकी का कहना है कि जयस सामाजिक संगठन था। बाद में राजनीतिक रोटी सेंकने लगे। नेतृत्व करने वाले कांग्रेस से विधायक बन गए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी है कि जयस के हर व्यक्ति को सांसद, विधायक, सरपंच, मेयर बनना है। युवाओं की भावनाओं से खेल रहे हैं। जयस तो कांग्रेस की बी-टीम है। जनजातीय वर्ग को भ्रमित करने के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। केवल राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश है। वे कहते हैं कि जनजातीय समाज कांग्रेस के साथ है, ऐसी मानसिकता है। वर्ष 2003 से तीन बार भाजपा ऐतिहासिक जीतीं। 2018 के पहले आदिवासी वर्ग भाजपा के साथ रहा है। कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था। झूठे वादे किए, लेकिन पंचायत चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। चुनाव हारने में कर्जमाफी और बेरोजगारों को 5 हजार हर माह देने की झूठी घोषणा बड़ी वजह थी। राहुल गांधी ने यह घोषणा की थी। जनजातीय युवा भोले हैं। वे भ्रम में आ गए। अब यह वर्ग सबकुछ समझ गया है।

● **जितेंद्र तिवारी**

## डॉ. सुमेर सिंह बनाए गए केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्य

संसद भवन परिसर नई दिल्ली में 8 अगस्त को केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड, संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) के सदस्य का निर्वाचन संपन्न हुआ। जिसमें राज्यसभा के 101 सांसदों ने अपना मतदान किया। जिसमें मप्र के युवा आदिवासी सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी को इस बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। संभवतः यह पहला मौका होगा जब किसी आदिवासी सांसद को इस अति महत्वपूर्ण बोर्ड का सदस्य निर्वाचित किया गया है। डॉ. सोलंकी इस बोर्ड में तीन वर्ष के लिए निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचन में भाजपा (एनडीए) की तरफ से सदस्य हेतु प्रत्याशी थे। जिनको राज्यसभा के सांसदों ने 81 वोट देकर जिताया है। वहीं विपक्षी उम्मीदवार जवाहर सरकार (सांसद तृणमूल कांग्रेस) को मात्र 20 मत प्राप्त हुए। वहीं डॉ. सोलंकी सांसद बनने से पहले मप्र के बड़वानी के कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक थे। डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने इस बोर्ड के सदस्य चुने जाने पर विश्वास दिलाया कि वह भारतीय पुरातत्व अनुसंधान का संचालन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर काम करेंगे। साथ ही पुरातत्व सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित अध्ययनों को बढ़ावा दिलाने के लिए और प्रयास करेंगे। साथ ही विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में स्थित पुरातत्व धरोहर पर विशेष ध्यान देने की बात कही है।

# 5 साल में नहीं वसूल पाए 425 करोड़

छोटी-मोटी अनुमति, एनओसी या अनुज्ञा न होने पर बुलडोजर तानकर खड़े होने वाले अफसरों में कितना दम है, यह ग्वालियर में बिलौआ की खदानों की कहानी आपको बता देगी। पांच साल में पांच कलेक्टर बदल गए, लेकिन कोई भी नेता-मंत्री और रसूखदारों की खदानों से जुर्माना नहीं वसूल सका। फाइल तब भी चल रही थी, फाइल अब भी चल रही है। 24 खदान संचालकों ने लीज क्षेत्र के अलावा सरकारी जमीन से काले पत्थर को निकाल जमीन खोखली कर डाली। यहां डबरा सब डिवीजन में आने वाले बिलौआ क्षेत्र में 2017 में खदान संचालकों द्वारा सरकारी जमीन पर खनन करने की शिकायत हुई थी। जिसके बाद तत्कालीन एसडीएम अमनवीर सिंह ने जांच की तो शिकायत सही पाई गई। तत्कालीन कलेक्टर डॉ. संजय गोयल ने 425 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, बस तब से वसूली नहीं हो पाई।

2016-17 में बिलौआ क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत हुई थी, इसी शिकायत से शुरुआत हुई और तब डबरा एसडीएम अमनवीर सिंह थे। उस समय कलेक्टर संजय गोयल ने एसडीएम डबरा को जांच के निर्देश दिए। जांच में सामने आया कि बिलौआ-रफादपुर क्षेत्र में जो 24 खदानें हैं, वह अपने लीज क्षेत्र को छोड़कर सरकारी भूमि पर भी खनन कर रहीं हैं। इसके बाद जांच प्रतिवेदन के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने आंकलन के आधार पर 24 खदान संचालकों पर 425 करोड़ का जुर्माना प्रस्तावित किया। इसके खदान संचालकों में हड़कंप मच गया और सभी अपना-अपना पक्ष सामने रखने लगे। इसके बाद कलेक्टर गोयल का तबादला हो गया और इसके बाद अगले कलेक्टर राहुल जैन आए, इनके कार्यकाल में भी कार्रवाई चलती रही। इसके बाद अशोक वर्मा और भरत यादव आए लेकिन इनका कार्यकाल ज्यादा समय नहीं रहा था। इसके बाद कलेक्टर अनुराग चौधरी आए, जिन्होंने इस मामले की पड़ताल कराई। इनके कार्यकाल में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने खदानों के कारण प्रदूषण फैलने को लेकर आपत्ति की, जिसके बाद 23 खदानों को बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद इन्हें खोल दिया गया।

गौरतलब है कि बिलौआ में मुनेंद्र मंगल, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, राजेश नीखरा, सरदार सिंह गुर्जर, केके जैन, मनोहर भल्ला, रामनिवास शर्मा, आरसी जैन, प्रतीक खंडेलवाल, अशोक यादव, एसपी जैन, राजीव लोचन शर्मा, विनीता यादव पत्नी दिवंगत उत्तम सिंह, वीरेंद्र गुप्ता, मनोहरलाल गुप्ता, सुनील शर्मा, मनोरमा तोमर, वीरेंद्र सिंह, बच्चन सिंह, मनीष गुप्ता की खदानें हैं।

इस मामले में जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि छोटे-मोटे मामलों में तत्काल जोर-शोर से कार्रवाई करने वाले प्रशासन को खनन माफिया क्यों नहीं दिखता है। बिलौआ में सवा चार सौ करोड़ का जुर्माना पड़ा हुआ है, इसे वसूला नहीं जा रहा है, इतनी मेहरबानी आखिर क्यों की जा रही है। इससे यही माना जा रहा है कि यह बड़े लोगों, रसूखदारों व नेताओं की खदानें हैं इसलिए जुर्माना वसूलने की हिम्मत नहीं है।

हालांकि पांच साल से एक के बाद एक बदले कलेक्टरों के कोर्ट ने जिन बिलौआ-रफादपुर की फाइलों से धूल नहीं हटाई थी, गत दिनों कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कलेक्टर कोर्ट में चल रहीं 425 करोड़ के जुर्माने की फाइलों में छह केसों में 60 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना अधिरोपित कर आदेश जारी कर दिए। जिले के डबरा अनुविभाग के अंतर्गत रफादपुर बिलौआ क्षेत्र में इन क्रेशर आधारित खदान संचालकों ने स्वीकृत लीज के बाहर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन कराया था। यह जांच वर्ष 2017 में डबरा के तत्कालीन एसडीएम अमनवीर सिंह बैंस ने कराई थी। इस जांच रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि खदान संचालकों ने स्वीकृत लीज से बाहर खनन कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाई है। इस जांच के आधार पर खनिज विभाग ने कलेक्टर न्यायालय में मामले दायर किए थे। विधिवत सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद कलेक्टर न्यायालय ने यह आदेश जारी किए।

● **लोकेंद्र शर्मा**

## इंदौर में भूमाफियाओं के हौंसले बुलंद

शासन-प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद इंदौर में भूमाफियाओं के हौंसले बुलंद हैं। नया मामला भांग माफियाओं का सामने आया है। इसकी कड़ियां खुलना बाकी हैं। इंदौर में पिछले एक साल (अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक) में जिला प्रशासन ने 124 केस अलग-अलग तरह के माफियाओं के खिलाफ दर्ज करवाए हैं। इनमें 330 लोगों को आरोपी बनाया गया। कई जेल गए तो कई जेल से बाहर भी आ गए। इन सब कार्रवाई के बावजूद हर माह 300 से ज्यादा शिकायतें माफियाओं से ठगे जाने की सामने आ रही हैं। अवैध खनन, नकली दवाओं, राशन माफियाओं, मिलावट माफियाओं के अलावा सबसे ज्यादा संख्या भूमाफियाओं की है। जिन चंपू-चिराग के खिलाफ प्रशासन ने जमीन घोटालों की जांच शुरू की थी, उनमें से 53 प्रतिशत पीड़ितों को ही अब तक न्याय मिला है। दूसरी ओर राशन माफियाओं के घोटाले जरूर कम हुए हैं। हालांकि यह काम पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी नागरिक ठगे जा रहे हैं। अधिकारी मानते हैं कि हम अलर्ट कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कई माफिया हैं जो माल बेचकर बाहर हो गए, अब उन्हें जेल तो भेजा जा सकता है, लेकिन वास्तविक समाधान मिलना भी जरूरी है। जानकारी के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन पर जो हर महीने 15 से 17 हजार शिकायतें आती हैं, उनमें 300 से ज्यादा शिकायतें किसी न किसी माफिया से ठगे जाने की हैं। एडीएम डॉ. अभय बेड़ेकर के मुताबिक हमने खनन, मिलावट, राशन माफियाओं और भूमाफियाओं पर कार्रवाई की है। हमारा मकसद इन्हें एफआईआर करवाकर जेल भिजवाने के अलावा आम लोगों को राहत दिलवाना है। प्रशासनिक आंकड़ों को देखें तो भूमाफियाओं के बाद सबसे ज्यादा आरोपी राशन घोटालों में सामने आए हैं।

# औद्योगिक हब बनेगा भोपाल

मालवा के पीथमपुर की तरह मध्यभारत के भोपाल को औद्योगिक हब बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल, देश-विदेश के कई बड़े निवेशक भोपाल के आसपास औद्योगिक इकाईयां स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए सरकार ने राजधानी के आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में निवेश करने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जानकारी के अनुसार राजधानी के आसपास रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं। इसके लिए 4 हजार 601 करोड़ रुपए का निवेश विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में किया जा रहा है। अकेले बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में अगले साल कुल 440 इंडस्ट्री के लिए करीब 220 करोड़ रुपए का निवेश होगा।

उद्योग विभाग के सूत्रों का कहना है कि मप्र में भोपाल के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं है। इसको देखते हुए नई इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने जमीनें देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें लकड़ी, स्टील, उप्र के बुलंदशहर में संचालित खुर्जा की क्रॉकरी इंडस्ट्री, गारमेंट्स, बेकरी प्रोडक्ट में ब्रेड, पाव व अन्य खाद्य सामग्री की फैक्टरी और प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए करीब 500 एकड़ जमीन दी जा रही है। 230 एकड़ जमीन अचारपुरा और बांदीपुरा में दी जाएगी। जबकि गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित फर्नीचर और लकड़ी इंडस्ट्री को ही 198 एकड़ जमीन बांदीपुरा में दी जा रही है। इसमें सैकड़ों की संख्या में नई फैक्ट्री और प्लांट लगाए जाएंगे। हर तरह के प्लास्टिक उद्योग के लिए पांच एकड़ जमीन अचारपुरा में दी जा रही है।

प्रदेश में रोजगार के मद्देनजर उन उद्योगों को जल्द से जल्द स्थापित करने जमीनें आवंटित की जा रही हैं, जिनसे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। भोपाल ही नहीं आसपास जिलों के लोगों को भी यहां रोजगार मिलेगा। जिला उद्योग केंद्र के अफसरों के साथ मिलकर नए उद्योगों को जमीनें आवंटित करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले तीन साल के भीतर शहर के अलग-अलग इलाकों में नई इंडस्ट्री लग जाएंगी। नई इंडस्ट्री के लगने के बाद करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ग्राम अगरिया छापर में लगभग 200 एकड़ पर औद्योगिक क्लस्टर बनाया जा रहा है। इसमें 450 से अधिक इंडस्ट्री को जगह दी जाएगी। यहां पर करीब 950 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। करीब 12 हजार से ज्यादा लोगों को यहां रोजगार से जोड़ा जाएगा। 6 अन्य क्लस्टर जैसे फूड, प्लास्टिक, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मल्टी प्रोडक्ट एवं रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर स्थापित होंगे। इसमें 600 करोड़ का निवेश और 10 हजार लोगों को रोजगार दिया जाना है। वहीं आनंद नगर, रायसेन रोड में शमां फूड पार्क में 25 करोड़ का निवेश होगा, जिससे 600 को रोजगार मिलेगा। बैरसिया में चित्रांश सेल्स कॉर्पोरेशन द्वारा 6.004 एकड़ जमीन पर फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है।

बगरोदा में ही 147 एकड़ में व्हीकल इंडस्ट्री के लिए जगह दी जा रही है। यहां पर मार्शल लॉजिस्टिक 25 करोड़ रुपए, वीवा लॉजिस्टिर 25 करोड़ रुपए, सनमार्क फूड 25 करोड़ रुपए, सनफील्ड इंडस्ट्री 50 करोड़ रुपए, वेल मार्क इंडस्ट्रीज 25 करोड़ रुपए, ल्युमेक्स 25 करोड़ रुपए, महिन्द्रा लॉजिस्टिक 25 करोड़ रुपए निवेश करेगी। पहले चरण में यहां पर कमर्शियल 10 हजार गाड़ियों का प्रोडक्शन हर साल किया जाएगा। इसके लिए करीब 1450 करोड़ निवेश होगा। इससे करीब 5 हजार नए लोगों को रोजगार मिलेगा। भोपाल के आसपास ग्राम अगरिया में लगभग 100 एकड़, गोकलकुंडी एवं पातालपुर में 80 एकड़ पर एग्रो एंड फूड पार्क औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाना है। राधा शरण गोस्वामी द्वारा ग्राम आदमपुर में 18089 मीटर रकबे में मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट निर्माण के लिए बहुमंजिला औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना की जा रही है। इन प्रयासों से भोपाल में फार्मा इंडस्ट्री के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकेगी। वहीं ज्यादातर फैक्टरी और उद्योगों को चलाने के लिए जमीनें शहर से कुछ दूर दी जा रही हैं। इससे शहर में कम प्रदूषण होगा। गोविंदपुरा से लकड़ी और प्लास्टिक इंडस्ट्री शिफ्ट होने से ही प्रदूषण से काफी राहत मिलेगी। यहां से गंदे पानी की निकासी के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिजली कंपनी लाइटिंग के लिए लाइनें बिछाकर ट्रांसफार्मर लगाएगी।

● राजेश बोरकर

## अचारपुरा में लगेगी 161 इंडस्ट्री

भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में 161 इंडस्ट्री लगाने की योजना है। यहां करीब 300 करोड़ निवेश आएगा। यहां पर करीब 1656 लोगों को रोजगार से जोड़ने की योजना है। गोकुलदास एक्सपोर्टस द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स का निर्माण करने के लिए 40 करोड़ का निवेश किया गया है। यहां पर करीब 2 हजार स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं जेल रोड पर स्थित बड़वई के पास स्थित आईटी पार्क में 207 एकड़ में 119 इंडस्ट्री में करीब 250 करोड़ का निवेश होगा। 15 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां पर प्रमुख आईटी कंपनियां जैसे टेक्नो टास्क द्वारा 100 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अन्य आईटी कंपनी जैसे एचएलबीएस आरटेक, गोल्ड डस्ट, सदर लैंड की प्रमुख इकाइयां निवेश करेंगी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में गोविंदपुरा, कालीपरेड इंडस्ट्रियल एरिया में 42 नई इंडस्ट्री लगेंगी। इसमें करीब 36 करोड़ का निवेश होगा। लगभग नए 600 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बगरोदा में कुल 440 इंडस्ट्री को जगह दी जाएगी। यहां पर करीब 220 करोड़ निवेश होगा। यहां पर 4155 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सूखी सेवनिया के पास स्वस्तिक लॉजिस्टिक 50 करोड़ रुपए, आकांक्षा इंडस्ट्रीज 50 करोड़ रुपए, कोचर इंडस्ट्रीज 50 करोड़ रुपए, काकडा ग्रुप 250 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। बीनापुर औद्योगिक क्षेत्र में 50 एकड़ पर बी फाक इंडस्ट्री द्वारा पोट्री निर्माण शुरू किया जा रहा है, यहां पर 150 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है।

> मप्र वन संपदा से परिपूर्ण प्रदेश है। प्रदेश के वनों में कई प्रकार की वन औषधियां पाई जाती हैं। जिनसे बनी दवाईयां देश-विदेश में सप्लाई की जाती हैं। अब मप्र लघु वनोपन संघ वनों में मिलने वाले फलों से पेय पदार्थ बनाने की तैयारी कर रहा है। संघ का मानना है कि स्वास्थ्यवर्धक ये पेय पदार्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों को चुनौती देंगे।

# कोकाकोला को टक्कर देगा जम्बूकोला

देश-विदेश में शीतल पेयपदार्थ के रूप में इस्तेमाल होने वाले कोकाकोला और पेप्सी जैसे उत्पादों को टक्कर देने के लिए मप्र लघु वनोपज संघ ऐसे पेयपदार्थ बना रहा है जिसमें स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा। मप्र राज्य लघु वनोपज संघ शहद, जामुन सहित अन्य फलों आदि से कोल्ड ड्रिंक बनाने की तैयारी कर रहा है। इसे ब्रांड विंध्या वैली के तहत जम्बूकोला, मधुकोला, बेलकोला सहित छह तरह के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। बच्चों से लेकर वृद्धों तक की पसंद को देखते हुए इसे बनाया जाएगा। यह कोला संघ की औषधीय उत्पाद बनाने वाली एजेंसी तैयार करेगी। इसमें औषधीय गुण भी होंगे।

वनोपज संघ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से भी इसकी अनुमति लेगा। इन पेय पदार्थों को शुरू में छोटे स्तर पर मार्केट में उतारा जाएगा। प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। साथ ही एफएसएसएआई का पंजीयन लिया जाएगा। विंध्या हर्बल के तहत करीब 300 से ज्यादा आयुर्वेदिक उत्पाद का निर्माण कर बेचा जाता है। वनोपज संघ मौसम के अनुसार, अलग-अलग तरह के फ्लेवर का कोला तैयार करेगा, ताकि इनका उपयोग सेहत को दुरुस्त करने में भी हो। जम्बूकोला पेट और शुगर के मरीजों के लिए कामयाब रहेगा। प्रत्येक कोला का अपना औषधीय गुण होगा। यह ढाई किलो से लेकर आधा किलो तक की बॉटल में आएगा।

विटामिन से भरपूर फलों और शहद को आयुर्वेद में गुणकारी माना गया है। कोला के लिए बेल, शहद, जामुन, तेंदू और आंवला सहित अन्य फलों का संग्रहण जंगलों में रहने वाली आदिवासियों की समितियां करेंगी। आयुर्वेदिक विशेषज्ञों की मदद से लघु वनोपज संघ इन जामुन और शहद से कोल्ड ड्रिंक बनाने में जुटा है। जामुन के गूदे को निकालकर इसमें जरूरी सामग्री मिलाकर इसकी कोल्ड ड्रिंक तैयार की जाएगी। वहीं शहद से भी इसी तरह कोल्ड ड्रिंक बनाई जाएगी। दोनों ड्रिंक लंबे वक्त तक खराब न हों इसके लिए फर्टिलाइज किया जाएगा। बताया जा रहा पेयपदार्थों का शुरुआती परीक्षण पूरा हो चुका है। मप्र लघु वनोपज संघ के एमडी पुष्कर सिंह का कहना है कि कोला की वैराइटी तैयार की जा रही है। यह वैराइटी अभी टेस्टिंग कोल पर है। जल्द ही बाजार में आएगी। इसमें सेहत और स्वाद का बराबर ध्यान रखा जा रहा है।

आजकल के युवा कोल्ड ड्रिंक पीने के गजब के शौकीन हैं। गर्मियों में तो सभी कोल्ड ड्रिंक पीते नजर आते हैं, यहां तक कि सर्दियों में भी खूब शीतल पेय पीते हैं। यही कारण है कि कोला कंपनियां खासा लाभ कमा रहीं हैं। हालांकि अब जल्द ही एक हर्बल पेय आने वाला है जो कि मप्र राज्य लघु वनोपज संघ के ब्रांड विंध्य द्वारा बनाया जा रहा है। ये कोला जहां युवाओं का गला तर करने के साथ उन्हें शीतलता पहुंचाएगा वहीं उनकी ताकत भी बढ़ाएगा। वनोपज संघ के वैद्य लंबे अर्से से इस पर काम कर रहे थे। पहले चरण में करीब 50 लीटर शीतल पेय बनाया गया था, जिसका विभिन्न स्तर पर परीक्षण किया गया। खुद वनमंत्री और अधिकारियों ने भी पेय के फ्लेवर की काफी तारीफ की। इस पर संघ ने जामुन खरीदने की तैयारी शुरू कर दी और पेय के लिए अतिरिक्त शहद भी मंगाया। इन दोनों पेय को निषेचन यानि फर्टिलाइज कर तैयार किया जा रहा है जिससे ये लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। अधिकारियों का तो दावा है कि ये पेय 18 महीने तक सुरक्षित रह सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षणों में दोनों पेय पास हो चुके हैं। अब मांग के अनुसार उत्पाद तैयार होगा। ये पेय फिलहाल 200 मिलीलीटर की पैकिंग में लाया जा रहा है। गौरतलब है कि मप्र लघु वनोपन संघ कई प्रकार की औषधियों का निर्माण करता है, जिसका चिकित्सा में उपयोग होता है।

● **राकेश ग्रोवर**

## आदिवासी होंगे मालामाल

जंगल से संग्रहित फलों को सुरक्षित लाने और उसे प्रोसेसिंग करने का काम लघु वनोपज संघ के भोपाल के बरखेड़ा पठानी सहित औषधीय प्रोसेसिंग केंद्रों पर किया जाएगा। इससे मिलने वाले लाभांश में आदिवासी समितियों को भी शामिल किया जाएगा। ये, कोला कम लागत में तैयार होंगे, क्योंकि जितने तरह के कोला बनाए जा रहे हैं, उनका कच्चा माल जंगलों में पर्याप्त मात्रा में है। जिस मौसम में ये फल होते हैं, उस समय आदिवासी जंगलों से इसे संग्रहित करेंगे और उसे समितियों के जरिए वन विभाग को बेच देंगे। वन विभाग आदिवासियों को आत्मनिर्भर बना रहा है। उनसे जंगलों में व जड़ी-बूटियों, औषधीय उत्पादों और फलों का वन ग्राम समितियों के माध्यम से संग्रहण कराया जा रहा है। इसके लिए विभाग ने सभी औषधियों और फलों की दरें तैयार की हैं, ताकि निजी कंपनियां आदिवासियों से औने पौने दामों में इन्हें खरीदकर बाजार में महंगे दामों न बेच सकें।

# मप्र में रोजगार की बहार

**कोरोना संक्रमण के बाद से देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मप्र सरकार ने संक्रमणकाल के दौरान ही बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास शुरू कर दिया था। इससे प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी समस्या नहीं बन पाई। फिर भी प्रदेश सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त प्रदेश बनाने का प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत मप्र को तीन साल में बेरोजगारी मुक्त प्रदेश बनाना है।**

मप्र देश का ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। आज जहां देश में बेरोजगारी का प्रतिशत 8.3 फीसदी है, वहीं मप्र में 2 फीसदी है। अब प्रदेश सरकार का फोकस है कि प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा कर हर बेरोजगार को काम मुहैया कराया जाए। वहीं सरकार ने सरकारी नौकरियों के द्वार भी खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लक्ष्य है कि प्रदेश में हर साल ढाई लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमारा प्रयास है कि धीरे-धीरे प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त बनाया जाए। किसी भी युवा को मप्र की धरती पर निराश होने की आवश्यकता नहीं हैं, यहां शिक्षा भी मिलेगी और रोजगार भी।

सरकार द्वारा मप्र को बेरोजगारी मुक्त प्रदेश बनाने का जो प्लान तैयार किया गया है उसके तहत गत दिनों प्रदेशभर में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के अमरदास हॉल में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में स्व-रोजगार योजनाओं में हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत एवं वितरित किए। साथ ही 75 हजार से अधिक हितग्राहियों को स्व-रोजगार के लिए 466 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को लाभ के प्रमाण-पत्र का वितरण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इंदौर में 2 करोड़ 84 लाख की लागत के मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए ई-लर्निंग मॉड्यूल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व पटल पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में मप्र सरकार भी अपने युवाओं को स्व-रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

## रोजगार और स्वरोजगार शासन की प्राथमिकता

मप्र में रोजगार और स्वरोजगार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में शुरू होने वाले 17 कलस्टर्स निर्माण की प्रक्रिया 1 महीने के अंदर शुरू की जाए। रोजगार और स्व-रोजगार राज्य शासन की प्राथमिकता है। फार्मा, फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट, फूड-प्रोसेसिंग और खिलौना निर्माण में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इन कलस्टर्स का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करें। औद्योगिक पार्कों के निर्माण की प्रक्रिया को भी गति दी जाए। साथ ही केवल रोजगार ही नहीं स्व-रोजगार के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से युवाओं को जोड़ने के लिए सुविधाजनक वातावरण और युवाओं को आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्व-रोजगार योजनाओं में अनुदान की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित करने के लिए पोर्टल अपग्रेडेशन का कार्य जल्द पूरा करें। ह्य

मप्र सरकार प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त प्रदेश बनाने पर किस तेजी से काम कर रही है इसका आंकलन इसी से लगाया जा सकता है कि इस साल सरकार ने अभी तक 13 हजार करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत किए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व पटल पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में मप्र सरकार भी अपने युवाओं को स्व-रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में पहला रोजगार दिवस 12 जनवरी 2022 को 5 लाख से अधिक प्रदेशवासियों को अलग-अलग योजनाओं में रोजगार प्रदान कर मनाया गया। इसी क्रम में 31 मार्च तक लगभग 13 लाख हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर 7 हजार करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। एक अप्रैल से 22 अगस्त 2022 तक लगभग 9 लाख 52 हजार लोगों को 6 हजार करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि पथ विक्रेताओं से लेकर स्टार्टअप इंडस्ट्री तक हम प्रदेश के हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है। आत्मनिर्भर मप्र के निर्माण में रोजगार दिवस न केवल एक मील का पत्थर है बल्कि महायज्ञ है।

प्रदेश की स्व-सहायता समूह की महिलाएं चमत्कार कर रही हैं। वे न केवल ग्रामीण क्षेत्र में

बल्कि शहरी क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। वर्तमान में समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे व्यवसाय का टर्नओवर 20 हजार करोड़ रुपए है। समूह द्वारा किए जा रहे उत्पादों के निर्माण के लिए हर माह बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका केवल 2 प्रतिशत ब्याज समूह को देना होता है। शेष ब्याज राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। समूह की महिलाओं द्वारा प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में पोषण आहार की फैक्ट्रियां भी संचालित की जा रही हैं। शासन का लक्ष्य है कि समूह की हर महिला अपने घरेलू कामकाज के साथ न्यूनतम 10 हजार रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त आमदनी कमा सके। मुख्यमंत्री का कहना है कि वे प्रतिमाह बैंकर्स के साथ बैठक कर लोन स्वीकृति के संबंध में चर्चा करते हैं। उन्होंने सभी बैंकर्स को उनके द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और उनसे आग्रह किया कि किसी भी पात्र हितग्राही को लोन स्वीकृति में परेशानी न आए। प्रदेश के हर व्यक्ति को स्व-रोजगार एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रदेशवासी रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे।

एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा का कहना है कि प्रदेश में सरकार ने तीन साल में सभी युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में मप्र ही एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 10 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं। अभी तक 42 क्लस्टर बना चुके हैं। क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बनेंगे। इनमें से 22 क्लस्टर का भूमिपूजन कर शुरू करेंगे। इनसे अगले तीन सालों में चार लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलना शुरू होगा। क्लस्टर के अनुरूप हम युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप नीति के माध्यम से 2500 से ज्यादा स्टार्टअप पिछले तीन महीने में बनाए हैं। पहले एमएसएमई में पूंजी, तकनीकी की कमी के कारण बंद होते थे। टाय क्लस्टर में 22 फैक्टरी साढ़े तीन हेक्टेयर में शुरू। एक फैक्टरी में 2100 के करीब रोजगार मिलेगा। हमारा उद्देश्य प्रदेश से बेरोजगारी के कलंक को पूरी तरह से खत्म करना है। अगले तीन सालों में हम इसे हासिल कर लेंगे। इससे पहले विभाग के सचिव पी नरहरि ने कहा कि हर माह रोजगार दिवस आयोजित होंगे। बैंकों में पहुंचने वाले आवेदनों का एकीकृत निराकरण करने से लेकर उनके खातों में राशि पहुंचाने तक को शासन अपनी निगरानी कर रहा है। मप्र टॉय क्लस्टर की नीति बनाने वाला पहला राज्य है।

वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि मप्र सरकार हर महीने ढाई लाख लोगों को रोजगार देगी। रोजगार दिवस पर इंदौर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जीने के लिए रोटी और रोटी के लिए रोजगार चाहिए। जनवरी 2022 में पहला रोजगार दिवस मनाया था। पहले दिन ही 5 लाख युवाओं को लोन दिलवाया। 13 लाख लोगों को मार्च तक लोन दे चुके हैं। अब सरकारी नौकरी भी ऐसे आयोजनों के साथ दी जाएगी। गुरु अमरदास हाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रंगवासा-राऊ में प्रस्तावित खिलौना (टाय) क्लस्टर की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग माड्यूल भी लांच किया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश के युवाओं को नौकरियों के काफी अवसर हैं। अभी पुलिस भर्तियां चालू हैं। हम एक लाख सरकारी नौकरी एक साल में देंगे। स्व-सहायता समूहों का टर्नओवर 20 हजार करोड़ रुपए है। ये समूह महिलाएं चला रही हैं। उद्यम क्रांति योजना इसलिए बनाई है कि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। जो युवा काम करना चाहते हैं वे इसका लाभ लें। मैं हर महीने बैंकर्स की बैठक भी ले रहा हूं। रोजगार का आयोजन यज्ञ से कम नहीं। हम हर महीने ढाई लाख लोगों को रोजगार से लगाएंगे। मप्र ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम हैं। अगले वर्ष इंदौर में 7, 8 और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आयोजन के उद्घाटन के लिए आमंत्रण भी दिया है।

स्वरोजगार योजना के तहत तमाम हितग्राहियों को मुख्यमंत्री ने ऋण के चेक दिए। इनमें स्वयं सहायता समूहों के अलावा ज्यादातर युवा थे। पशु आहार उत्पादन, ड्रेगन फ्रूट की उन्नत खेती से लेकर फैशन डिजाइन, किराना दुकान और विभिन्न तरह के उद्यमों के लिए ऋण दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर के खिलौना क्लस्टर की फैक्ट्रियां सालभर में उत्पादन शुरू कर देंगी। प्रदेश सरकार ने उद्यम क्रांति योजना इसलिए बनाई है, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकतीं। एक साल में एक लाख सरकारी नौकरियां देंगे और ऐसे समारोह के जरिए चुने गए युवाओं को नौकरी पर भेजेंगे। मप्र ऐसा राज्य है, जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही भोपाल में 4 सितंबर को विशाल कार्यक्रम में लगभग 16 हजार शिक्षकों को नियुक्ति-पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में भी भर्ती नियमित रूप से की जा रही है। राज्य शासन का लक्ष्य है कि एक साल में लगभग एक लाख सरकारी नौकरी प्रदेशवासियों को दी जाए।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

## 21 विभागों में भर्ती की तैयारी

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा को अमल में लाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि उन्हें 21 बड़े विभागों में 93,681 रिक्त पदों की आधिकारिक जानकारी प्राप्त हो गई है। इन पदों पर नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन ने बताया कि 21 बड़े विभाग में 93 हजार 681 पद रिक्त हैं। इनकी पूर्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया संचालित की जाएगी। बताया गया कि स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में विभिन्न श्रेणी के लगभग 30 हजार रिक्त पद हैं, साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों को मिलाकर लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती का कार्य हो सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने यहां वैकेंसी की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। जानकारी के मुताबिक जल्द ही प्रदेश में भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे।

# नए चेहरों पर भरोसा

## आजमाया 8 साल पुराना फॉर्मूला

भाजपा ने अपनी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति गठन में 8 साल पुराने फॉर्मूले को आजमाया है। 2014 में अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को संसदीय बोर्ड से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में रखा था। इसी तरह से दोनों ही कमेटियों से पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को हटाकर नए चेहरों को भरोसा जताया है। भाजपा संसदीय बोर्ड में फेरबदल में शिवराज सिंह चौहान नितिन गडकरी को हटा दिया गया है। ऐसे ही केंद्रीय चुनाव समिति से शाहनवाज हुसैन और जोएल ओराम की छुट्टी हो गई है। इस बार भाजपा ने मार्गदर्शक मंडल समिति को लेकर कोई एलान नहीं किया है। नए चेहरे को तौर पर गडकरी की जगह देवेंद्र फडणवीस को लाया गया है तो थावरचंद गहलोत की जगह दलित चेहरे के तौर पर सत्यनारायण जटिया को जगह मिली है। इसके अलावा संसदीय बोर्ड में बीएस येदयुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा और सुधा यादव को पहली बार जगह मिली है। ऐसे ही चुनाव समिति में भूपेंद्र यादव, ओम माथुर और वनथी श्रीनिवास को शामिल किया गया है। इस तरह भाजपा ने पुराने चेहरों की जगह नए नेताओं को हाई प्रोफाइल कमेटी में जगह देकर बड़ा सियासी संदेश दिया है। भाजपा ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय समिति का गठन में चुनावी राज्यों का खास ध्यान रखा गया है। 2024 लोकसभा चुनाव के साथ या फिर उससे पहले होने वाले राज्यों के नेताओं को पार्टी ने तवज्जो दी है।

देश की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज होने को बेताब भाजपा ने अभी से मिशन-2024 की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनावी समिति की घोषणा कर दी है। पार्टी की सबसे पावरफुल माने जानी वाली दोनों ही समितियों से कुछ बड़े चेहरों की छुट्टी कर दी गई है तो कुछ नए नेताओं की जगह दी है। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को हटाकर भाजपा ने सिर्फ खाली पदों को नहीं भरा है बल्कि उससे आगे बढ़कर काम किया है। इस तरह भाजपा ने नई टीम से पांच बड़े सियासी संदेश देने की कोशिश की है?

भाजपा ने पार्टी संसदीय बोर्ड का ऐलान किया और साथ ही नई केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन किया है। पार्टी की यह दोनों ही कमेटियां सबसे अहम मानी जाती हैं। भाजपा के संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष को जगह मिली है। वहीं, भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति का भी ऐलान किया गया है, जिसमें संसदीय बोर्ड के सदस्यों के अलावा भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, वनथी श्रीनिवास को भी जगह मिली है। इस तरह केंद्रीय चुनाव समिति से शाहनवाज हुसैन, जोएल ओराम को भी नई समिति में जगह नहीं मिली है जबकि संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह की छुट्टी कर दी है।

भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में फेरबदल कर 2024 के चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछा दी है। भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन, एम वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति और थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बनाए जाने से खाली पड़े पदों को सिर्फ नहीं भरा है बल्कि 2024 के चुनाव को देखते हुए उससे आगे बढ़कर काम किया है। दोनों ही समिति में ऐसे नेताओं को जगह दी गई है, जिनके जरिए सियासी संदेश देने के साथ-साथ सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन भी बनाने की कोशिश की गई है। भाजपा में संगठन के लिहाज से दोनों ही पावरफुल कमेटियां मानी जाती हैं, जो संगठन ही नहीं बल्कि भाजपा के चुनाव और सत्ता में आने पर मंत्रिमंडल के गठन में अहम भूमिका होती है। भाजपा में 8 साल के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक डेढ़ साल पहले दोनों कमेटियों का गठन किया गया है ताकि समय रहते रणनीति बनाई जा सके और जमीनी स्तर पर भी संदेश दिया जा सके।

भाजपा ने संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के जरिए अपने सियासी आधार को मजबूत करने का दांव चला है। 2014 के बाद से भाजपा का पूरा फोकस उच्च जातियों के साथ-साथ ओबीसी और दलित मतदाताओं पर है। भाजपा अपने ओबीसी वोटबैंक को और भी मजबूत करने के लिए संसदीय बोर्ड में तीन नेताओं को जगह दी है। संसदीय बोर्ड में प्रधानमंत्री मोदी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण, भाजपा ओबीसी मोर्चा की पूर्व प्रभारी सुधा यादव को शामिल किया गया है। पार्टी की चुनाव समिति में भूपेंद्र यादव को रखा गया है। भाजपा ने अपनी हाई प्रोफाइल कमेटियों में दो यादव समुदाय के नेताओं को एंट्री देकर साफ संकेत दिए हैं कि उसकी नजर हरियाणा और राजस्थान के यादव समुदाय को नहीं बल्कि उप्र की सपा और बिहार की आरजेडी के कोर वोटबैंक को अपने पाले में लाने की रणनीति है। ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी यादव समाज की है, जिन्हें भाजपा अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रही है। इसी मद्देनजर यादव को जगह दी गई है तो साथ ही ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण को जगह दी गई, जो तेलंगाना से आते हैं और उप्र से राज्यसभा सदस्य हैं।

भाजपा ने अपनी दोनों कमेटियों में पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम और दक्षिण भारत तक साधने की कवायद की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से भाजपा का पूरा फोकस पूर्वोत्तर के राज्यों पर रहा है। यही वजह है कि भाजपा के संसदीय बोर्ड में असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को जगह मिली है। वहीं, दक्षिण भारत से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, तेलंगाना से के लक्ष्मण और तमिलनाडु से वनथी श्रीनिवास को जगह मिली है। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्र से देखें तो महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय चुनाव समिति में रखा गया है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद आते हैं। पूर्वोत्तर और हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में मजबूती से अपने पैर जमाने के बाद भाजपा का फोकस अब नए इलाकों पर है। ऐसे में भाजपा की कोशिश दक्षिण भारत के राज्यों में अपने सियासी आधार को मजबूत करने की है। कर्नाटक में भाजपा का दबदबा कायम है तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु पर नजर है। भाजपा ने अपनी हाई प्रोफाइल कमेटियों में दक्षिण भारत के लोगों को जगह देकर एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी लगातार दक्षिण का दौरा कर रहे हैं।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

# अतिक्रमण की चपेट में जंगल

## 20 फीसदी से ज्यादा वन रक्षकों के पद खाली

वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने में वन रक्षकों की कमी बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। वन विभाग के पास वन रक्षक के स्वीकृत पद 20670 हैं। इनमें से 16281 वन रक्षक ही मैदान में हैं। करीब 20 फीसदी यानी 4 हजार से ज्यादा वन रक्षकों के पद अब भी खाली हैं। वहीं वन क्षेत्रों में हो रही अवैध कटाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले साल वन विभाग ने अवैध कटाई के 40 हजार से ज्यादा मामले सामने आए थे। अतिक्रमण के ढाई हजार से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। वर्ष 2009-10 में मप्र में अति सघन, सघन और खुला वनक्षेत्र 77700 वर्ग किमी था, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 77493 वर्ग किमी रह गया है। यानी 12 साल में 207 वर्ग किमी जंगल घट गया। ऐसा तब है, जब हर साल पौधारोपण होने का दावा किया जाता है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2009 में 7 लाख 47 हजार, वर्ष 2010 में 6 लाख 60 हजार और वर्ष 2011 में 7 लाख 4 हजार पौधे रोपे गए। साल 2020-21 में वन विभाग ने 3 करोड़ 86 लाख से ज्यादा और साल 2021-22 में 3 करोड़ 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए। मप्र सरकार द्वारा पौधारोपण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बाद भी जंगल घट रहा है। वर्ष 2019-20 में मध्यम घना जंगल 34341 वर्ग किमी था, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 34209 वर्ग किमी रह गया। यही नहीं, बहुत घने जंगल का रकबा भी दो किमी घटा ही है। वर्ष 2019-20 में ये आंकड़ा 6667 वर्ग किमी था, जो वर्ष 2021-22 में घटकर 6665 वर्ग किमी पर आ गया। दूसरी तरफ वर्ष 2019 में ओपन फॉरेस्ट का दायरा 36465 वर्ग किमी था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 36618 वर्ग किमी हो गया है। ओपन फॉरेस्ट का दायरा 153 वर्ग किमी तक बढ़ गया है। यानी जंगलों में अतिक्रमण और अवैध कटाई खूब हो रही है।

देश को सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर देने वाले मप्र में जंगलों की 54 हजार 173 हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण का शिकार है। इसमें ज्यादातर पर कब्जेधारियों ने पट्टा हासिल कर लिया है। चौंकाने वाली यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में दी है। यह कुल फॉरेस्ट कवर का 6-7 फीसदी है। मप्र के वन विभाग का कहना है कि यह साल-दर-साल बढ़ रहा है और इसके पीछे बड़ी वजह वनाधिकार पट्टों का वितरण है।

मप्र में 2008 के बाद से वनाधिकार पट्टे जारी हो रहे हैं। अब तक 3.14 लाख हेक्टेयर जमीन पट्टे पर जा चुकी है। इसमें से 80 फीसदी पर अतिक्रमण है। सर्वाधिक मामले बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और देवास के साथ गुना जिले के हैं। मप्र में जितना अतिक्रमण है, वह असम के बाद देश में सर्वाधिक है। असम में 3.77 लाख हेक्टेयर से अधिक वनभूमि अतिक्रमण के दायरे में हैं। अतिक्रमण को रोकने या हटाने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिनियम 1980 में प्रावधान हैं। राज्यों के पास अधिकार भी हैं, लेकिन लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है। वहीं सिंचाई, सड़क, बांध के डूब क्षेत्र, रक्षा, रेलवे और अन्य विकास कामों के लिए तीन दशकों में 2.80 लाख हेक्टेयर भूमि डी-नोटिफाई हो चुकी है। वन विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि इसके बदले में जो जमीन मिली, वह पूरी तरह फॉरेस्ट कवर हासिल नहीं कर पाई।

देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य मप्र की राजधानी भोपाल समेत बड़े शहरों से सटे जंगल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अधिकारियों और रसूखदारों की मिलीभगत से वन क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। अवैध कटाई और अतिक्रमण ने जंगल की सीमाओं को सिकोड़कर रख दिया है। बीते चार सालों में वन और भू-माफिया ने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों से सटे जंगल को वन और राजस्व महकमे के अफसरों की मिलीभगत से अपना निशाना बनाया और सैकड़ों हरे भरे वृक्ष काटकर फार्म हाउस काट दिए।

आलम यह है कि चार सालों में ढाई हजार हेक्टेयर से अधिक जंगल अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। एक तरफ पढ़ा-लिखा माना जाने वाला शहरी तबका जंगल को बेरहमी से खत्म कर रहा है तो दूसरी ओर आदिवासी अंचल में जंगल लगातार पल्लवित हो रहे हैं। जंगल से अपनी आजीविका चलाने वाला यह समाज इन्हें सहेज रहा है। आदिवासी अचंल में जंगल अतिक्रमण से भी मुक्त हैं। प्रदेश के जंगल अब वन माफियाओं के निशाने पर हैं। वनों की अवैध कटाई, अवैध उत्खनन और अवैध अतिक्रमण से जंगल साफ हो रहा है। हर साल करोड़ों की संख्या में हो रहे पौधारोपण के बाद भी हर साल वनक्षेत्र कम होता जा रहा है। प्रदेश के जंगल को शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जंगल के बड़े हिस्से पर अवैध आरी चलाकर कॉलोनियां डेवलप की जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों से सटे जंगल में अतिक्रमण भी जमकर हो रहा है। पिछले चार साल में प्रदेश के पांच शहरी क्षेत्रों से सटे 2735 हेक्टेयर वन क्षेत्र में अतिक्रमण हो चुका है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर जैसे शहरी क्षेत्रों के जंगल में अतिक्रमण सबसे ज्यादा हो रहा है। वनों की अवैध कटाई भी और अवैध उत्खनन के मामले भी शहरी क्षेत्रों में ही बढ़ रहे हैं।

एक तरफ प्रदेश के शहरी क्षेत्र में आसपास वन क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं, वहीं इसके उलट अदिवासी बाहुल्य वन क्षेत्र में आदिवासी जंगलों की आज भी सहेज रहे हैं। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामले बहुत कम हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैतूल में साल 2018 से नवंबर 2021 तक महज 12 हेक्टेयर वन क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ। इधर, साल 2018 से नवंबर 2021 तक भोपाल से सटे 476 वन क्षेत्र में अतिक्रमण हो गया। यही हाल दूसरे बड़े शहरों का है। ग्वालियर में तो पिछले चार साल में 899 हेक्टेयर वन क्षेत्र में अतिक्रमण हो गया है। उधर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र छिंदवाड़ा में बीते चार साल में सिर्फ 4 हेक्टेयर वनक्षेत्र में अतिक्रमण हुआ था।

● **विकास दुबे**

# जैविक खेती में घोटाला...

## कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

पूरे मंडला जिले में रेन्डम तरीके से ज्यादा से ज्यादा गांवों की जांच कराई जाए। यह योजना प्रदेश के 20 आदिवासी बाहुल्य जिलों में संचालित की गई थी जांच में मंडला जिले में जिस तरीके का भ्रष्टाचार सामने आया, उसी तरह दूसरे 19 जिलों की भी जांच कराई जाए। योजना में बदलाव करने वाले जिम्मेदारों पर एफआईआर की जाए। योजना में आदिवासी जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग कर बेचने की बात कही गई थी, लेकिन एक भी उपज की ब्रांडिंग नहीं की गई। करीब 110 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है, इसकी एफआईआर कराई जाए। आयोग के निर्देश पर जो जांच हुई है, उसमें मिली गड़बड़ियों पर एफआईआर कराई जाए।

म प्र के आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय को जैविक खेती से जोड़ने के लिए चलाई गई योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने साल 2016-17 में प्रदेश के आदिवासियों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 54 करोड़ स्वीकृत किए। इसी प्रकार विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया, सहरिया) के लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। इसके अलावा राज्य मद से 36 करोड़ दिए गए हैं।

केंद्र सरकार को भेजे गए प्रोजेक्ट में सेसबानिया बीज की जगह सेसबानिया रोस्ट्रेट नामक बीज का नाम शामिल किया गया, जबकि सेसबानिया रोस्ट्रेट नामक बीज भारत में जैविक खेती के लिए केंद्र सरकार की परम्परागत कृषि विकास योजना की गाइडलाइन में शामिल नहीं है। मप्र कांग्रेस आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन और कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री एवं प्रकोष्ठों के प्रभारी जेपी धनोपिया कहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए संचालित जैविक खेती योजना में 100 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पार्टी के विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया था।

कांग्रेस आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन का कहना है कि केंद्र सरकार से सेसबनिया रोस्ट्रेटा (टेंडर दर 114 रुपए प्रति किलो) मंजूर कराया गया, जबकि वितरण के समय मंडला जिले में 25 से 30 रुपए किलो मिलने वाला बीज बांटा गया। केंद्र सरकार से दो अलग-अलग राशियां 54 करोड़ आदिवासियों के लिए और 20 करोड़ विशेष पिछड़े (बैगा, भारिया, सहरिया) आदिवासियों के लिए मिली थी, इसका उपयोग अलग-अलग हितग्राहियों के लिए होना था। इसमें 36 करोड़ की राशि राज्य मद से भी जोड़ी गई थी, लेकिन आरटीआई में मिली किसानों की सूची में डिंडौरी, अनूपपुर और मंडला में दोनों मदों की राशि में एक ही सूची मिली, जिससे आशंका है कि एक आदिवासी को फायदा देने के नाम पर दो जगह भुगतान किया गया है।

मप्र कांग्रेस कमेटी के आरटीआई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत की थी। आयोग ने फर्जी सूची के मामले को संज्ञान में लेने के बाद जांच के लिए मप्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया था। कलेक्टर मंडला ने इस मामले में जांच कराई और इसमें पाया गया है कि कई गांवों के लाभांवितों की सूची में ब्राह्मण, कुर्मी, लोहार, मेहरा इत्यादि जातियों के व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। योजना में ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गाइडलाइन बदली गई, जिसके लिए कृषि विभाग के मुख्यालय के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार से स्वीकृति के बाद ठेकेदारों को मदद कर भ्रष्टाचार करने के लिए वर्मी कम्पोस्ट यूनिट के स्थान पर प्रोम खाद और जैविक कीटनाशक प्रदाय की स्वीकृति गलत तरीके से दी गई ताकि वैरीफिकेशन न हो सके।

हितग्राहियों को जैविक सामग्री का फायदा नहीं मिला और इनको यह भी नहीं मालूम कि इनके नाम लाभांवित की सूची में कैसे आए। इससे स्पष्ट है कि झूठी हितग्राही सूची बनाकर राशि का गबन किया गया है। बाद में एक अन्य काल्पनिक सूची बनाकर गड़बड़ी की गई है। सरकारी दस्तावेज तैयार करने में बड़ी गड़बड़ी की गई है। जांच दल ने कृषि और आत्मा परियोजना मंडला के उपसंचालक कार्यालय में जो सूची उपलब्ध हैं, उनके हितग्राहियों को जैविक सामग्री देने की जांच नहीं की। 165 हितग्राहियों के नाम पर दो राशियों का आहरण किया जाना सिद्ध पाया गया है। जांच रिपोर्ट में दोहरा भुगतान होने के बावजूद दोषियों पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है।

पिछले विधानसभा सत्र में इस घोटाले की गूंज सुनाई दी थी। उस समय भी कांग्रेस के ही विधायकों ने जांच की मांग उठाई थी। विधानसभा सत्र के दौरान यह मामला चर्चा में आया था। अब शिकायत ईओडब्ल्यू के पास है। उसने एक अलग टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है शिकायत से जुड़े तमाम दस्तावेज संबंधित विभाग से जुटाए जा रहे हैं। जैसे-जैसे सबूत आते जाएंगे, कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सबूत जुटाने के लिए विभाग के कई अधिकारियों को तलब किया गया। जैविक खेती के नाम पर किया गया ये घोटाला 2017-18 का है। आदिम जाति कल्याण विभाग ने 20 जिलों के आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया के साथ भारिया किसानों को कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा के उत्पादन में सहयोग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के लिए करीब 100 करोड़ रुपए कृषि विभाग को दिए थे। विभाग का मकसद जैविक खेती करने वाले आदिवासी किसानों को बढ़ावा दिया जाना था। यह पैसा आदिवासी किसानों के लिए केंद्र से मिला था। विभाग को इससे खाद-बीज खरीदना थे और फिर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए किसानों को देना थे।

प्लान ये था कि रासायनिक खाद के बजाय जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने पैसा तो दे दिया, लेकिन अफसरों ने उसका फायदा किसानों को नहीं पहुंचाया। सितंबर 2018 में जैविक खेती के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। मप्र एग्रो को खाद सहित बाकी सामान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। एग्रो ने निजी कंपनियों को ठेका दिया। आरोप है कि जो सामग्री दी गई वो बेहद घटिया थी। खाद में राख और मिट्टी मिली थी और तरल पदार्थ में पानी भरा था। इस योजना को मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और छिंदवाड़ा में लागू किया जाना था।

● **अरविंद नारद**

# स्मगलर कॉन्स्टेबल

## तबादले के बाद भी रहा बाबू के संपर्क में

19 नवंबर 2020 को कॉन्स्टेबल पंकज का देवास ट्रांसफर कर दिया गया। यहां उसे थाने पर पदस्थ नहीं करते हुए लाइन में ही रखा गया। इसके बावजूद वह बाबू के कॉन्टैक्ट में रहा। ट्रांसफर से पहले पंकज ने बाबू के साथ मिलकर चंगेरा में जमीन खरीदी तो बाबू ने बरखेड़ा स्थित फार्म हाउस पंकज के नाम कर दिया। यहां डोडा चूरा पीसने की आधुनिक मशीनें लगाई गई थीं। इसी तरह नयागांव बॉर्डर पर राजस्थान सीमा में फैक्टरी डाली थी। वहां भी डोडा चूरा पीसकर गाड़ियों में भर तस्करी की जाती थी। देवास एसपी शिवदयाल सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि पंकज कुमावत को अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाने, ड्यूटी से गैर हाजिर रहने के कारण और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए बर्खास्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पंकज एक महीने से डोडा चूरा की अवैध तस्करी के मामले में जावद जेल में बंद है। बाबू सिंधी भी जेल में है। अब उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने की तैयारी है।

15 साल की उम्र में एक लड़का कॉन्स्टेबल बना। उसने कमाई का ऐसा शॉर्टकट निकाला कि 13 साल की नौकरी में 50 करोड़ से ज्यादा की उगाही कर डाली। अब एक महीने से जेल में है। नौकरी से भी निकाल दिया गया है। ये कहानी है नीमच के डोडा चूरा तस्कर और बर्खास्त कॉन्स्टेबल पंकज कुमावत की। देवास एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह ने उसे बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। पंकज ने कुख्यात डोडा चूरा तस्कर जयकुमार सिंधी उर्फ बाबू सिंधी के साथ अघोषित पार्टनर बनकर बेशकीमती संपत्ति बनाई है। पुलिस पड़ताल में उसके पास फार्म हाउस, वेयर हाउस, मकान और गाड़ियां होने का पता चला है, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है।

बात वर्ष 2009 की है। दयाराम कुमावत नीमच में पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल थे। ईमानदार और ड्यूटी के प्रति सजग और संवदेनशील। 2009 में ही रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। बेटे पंकज को अनुकंपा नौकरी मिल गई। महज 15 साल में उसे बाल आरक्षक के तौर पर पुलिस महकमे का हिस्सा बना लिया गया। पंकज ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। जैसे-तैसे 12वीं तक ही पढ़ सका। उसके करीबी बताते हैं कि पंकज का मन पढ़ाई से ज्यादा कमाई के शॉर्टकट तरीकों पर लगा रहता था। उसकी वर्दी पर 'देशभक्ति जनसेवा' लिखा था, लेकिन वो काली कमाई से रातों-रात करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहा था।

पंकज की उम्र बढ़ी तो बाल आरक्षक से कॉन्स्टेबल बन गया। इसी बीच, वह नीमच में जयकुमार उर्फ बाबू सिंधी के संपर्क में आया। बाबू अफीम से निकलने वाले डोडा चूरा का बड़ा तस्कर है। कुछ महीने पहले ही जब बाबू के ठिकानों पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की टीम ने दबिश दी तो पता चला बाबू की संपत्ति 200 करोड़ से भी ज्यादा की है।

बाबू के माल की आवाजाही और पुलिस केस को रफा-दफा कराने या उसके गुर्गों के खिलाफ कमजोर केस बनाकर उनकी रिहाई जैसे सरकारी काम पंकज ही संभालता था। जांच के बाद पंकज को भी बाबू का अघोषित पार्टनर माना गया। इसके एवज में पंकज को जो रकम मिली, उससे वो भी करोड़पति हो गया। पंकज कुमावत ने एक बार तस्कर बाबू सिंधी के जन्मदिन पर नोटों की गड्डियां लुटाकर आका का स्वागत किया था। तस्कर के ऊपर इस तरह पुलिस वाले का दौलत लुटाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, तभी से बाबू और पंकज के बारे में बातें सामने आईं। जांच में पाया गया कि पंकज का रसूख भी कम नहीं था। उसके पास 8 गाड़ियां हैं। एक वेयर हाउस भी है।

पंकज कुमावत व बाबू सिंधी की अवैध करोड़ों रुपए की संपत्ति पर सफेमा की कार्रवाई को लेकर नोटिस जारी किए जाने की भी सूचना सामने आ रही है। देवास पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया कि पंकज कुमावत बाल आरक्षक से नव आरक्षक के पद पर संविलियन हुआ। आरक्षक 29 अगस्त 2021 से गैरहाजिर होने पर निलंबित चल रहा है। उस पर प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पंकज कुमावत को सेवा से प्रथक किया जाता है। पत्र में एसपी ने बताया कि पंकज कुमावत को सेवाकाल में अब तक 44 ईनाम, अनुपस्थित रहने पर चार बार निंदा, 1 बार अनुशासनहीनता करने पर निंदा की कार्रवाई की है। 4 बार पीटीएस तिगरा में गैरहाजिर रहने पर एलआर 24 के तहत निराकरण किया गया है। उन्होंने लिखा है कि पंकज कुमावत, पुलिस लाइन देवास को प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर देने के उपरांत भी जांच की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हुआ।

गौरतलब है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने अगस्त माह में औद्योगिक क्षेत्र स्थित हितांशी ट्रेडिंग कंपनी पर दबिश देकर वहां जांच के दौरान गेंहू की बोरी में डोडाचूरा मिक्स कर बाहर भेजना पाया गया है। आईआरएस अधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में बाबू सिंधी उर्फ जय सबनानी के गोदाम पर जांच शुरू हुई। करीब 400 गेंहू की बोरी गिनी जा चुकी थी, जिसमें डोडाचूरा पीसकर मिलाया गया हुआ था। इस कार्यवाही में मप्र और राजस्थान के एक दर्जन अधिकारी शामिल थे। वहीं बाबू सिंधी से जुड़े कई पोस्तादाना व्यापारी में हडकंप मच चुका है, कब किससे पूछताछ हो जाए। गोदाम में कई दस्तावेज टीम के हाथ लगे हैं, जिनमें अफीम, डोडाचूरा, धोलापाली ओर कालेदाने की तस्करी से जुड़े हुए है। पोस्ते की छनाई के बाद निकले धोलापाली और कालेदाने को कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी खरीदता था, बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी बाबू सिंधी कर रहा था। स्थानीय स्तर पर कुछेक पुलिसकर्मियों से सांठगांठ होने के कारण उस पर स्थानीय पुलिस की कार्यवाही अब तक नहीं हो पा रही थी, नीमच में वह बड़े पैमाने पर तस्करी का गिरोह संचालित कर रहा था। तस्करी से अर्जित करोड़ों रुपए से बाबू सिंधी ने नीमच व आसपास जमीनें खरीदी हैं। वह प्रापर्टी में ब्लैकमनी खपा रहा था।

● **बृजेश साहू**

# बुंदेलखंड में सूखे का डर

मानसूनी सीजन के खत्म होने के कगार पर पहुंचने के बावजूद बुंदेलखंड में बारिश नदारद है। देश के बड़े हिस्से, पूर्वोत्तर में असम से लेकर पश्चिमी भारत में राजस्थान और गुजरात तक और प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्य अत्यधिक भारी वर्षा के कारण बाढ़ का सामना कर रहे हैं, उप्र, बिहार और झारखंड के किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अब तक इस दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में 1 जून से 25 जुलाई तक, पन्ना जिले में माइनस 21 प्रतिशत वर्षा की कमी है। सतना और रीवा के पड़ोसी जिलों में, वर्षा की कमी शून्य से 34 प्रतिशत और शून्य से 43 प्रतिशत कम है। मप्र में सबसे ज्यादा बारिश सीधी जिले में माइनस 51 फीसदी है। हालांकि, मप्र राज्य में कुल मिलाकर 23 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। पड़ोसी राज्य उप्र में स्थिति गंभीर है, जहां शून्य से 54 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में क्रमशः माइनस 45 फीसदी, माइनस 49 फीसदी और माइनस 26 फीसदी बारिश हुई है। बुंदेलखंड में स्थिति समान है। अब तक हुई बारिश बहुत कम है। अकेले पन्ना में लगभग 100,000 हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती की जाती है। पन्ना में कृषि विज्ञान केंद्र (कृषि विज्ञान केंद्र) के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक पीएन त्रिपाठी का कहना है कि धान के अलावा, किसान यहां दलहन और तिल उगाते हैं, लेकिन वे फसलें भी नहीं कर रही हैं इस साल ठीक है। उप्र के ललितपुर जिले में, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है, धान का रकबा घट रहा है, जैसा कि राज्य के कृषि विभाग के आंकड़ों से पता चलता है।

प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल (वित्त वर्ष 2021-22) 309,078 हेक्टेयर के लक्ष्य बुवाई क्षेत्र के विपरीत, केवल 300,285 हेक्टेयर में ही बुवाई हुई थी। साथ ही इस वर्ष अब तक 335,405 हेक्टेयर के लक्ष्य रकबे में से 239,132 हेक्टेयर में से खरीफ सीजन में बुवाई की जा चुकी है, लेकिन प्रतिकूल मौसम की स्थिति ने किसानों की धान और दलहन दोनों की बुवाई की उम्मीदों को हतोत्साहित कर दिया है। दलहन की फसल भी प्रभावित धान के अलावा दलहन उगाने वाले किसान भी इस मानसून के मौसम में कम बारिश के कारण प्रभावित हुए हैं। कृषि वैज्ञानिक त्रिपाठी का कहना है कि राज्य के किसान कल्याण एवं कृषि विभाग ने किसानों से दलहन जैसी कम पानी वाली फसलों की बुवाई करने की अपील की है। हालांकि, जिले में दलहन की बुवाई करने वाले किसान भी घाटे में चल रहे हैं। धान के विपरीत, दालों के फसल चरण तक पहुंचने की अधिक संभावना होती है क्योंकि उन्हें कम पानी की जरूरत होती है। लेकिन ये फसलें भी नष्ट होने के कगार पर हैं। इसे जल्द से जल्द बारिश की जरूरत है। स्थिति अन्य जिलों छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, रीवा और सिंगरौली की तरह समान है, स्वयंसेवी संस्था समर्थन के क्षेत्रीय समन्वयक ज्ञानेंद्र तिवारी, एक गैर सरकारी संगठन जो पन्ना जिले के 24 से अधिक गांवों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। उनके अनुसार उड़द, मूंग और अरहर जैसी दलहन की खेती करने वाले किसान सूखे जैसी स्थिति से प्रभावित हैं।

बुंदेलखंड भारत में सबसे अधिक सूखा प्रवण क्षेत्रों में से एक है। 2014 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा प्रकाशित एक शोध अध्ययन के अनुसार, बुंदेलखंड के निवासियों को कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। बुंदेलखंड सूखा पूर्वव्यापी विश्लेषण और शीर्षक वाले शोध अध्ययन में कहा गया है, अधिकांश कृषि एकल-फसल किस्म की होती है और यहां लोग कुओं पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह बड़ी संख्या में किसान इन कुओं को रिचार्ज करने के लिए मानसून की बारिश पर अत्यधिक निर्भर हैं। बुंदेलखंड में सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए अपनी सिफारिशों के हिस्से के रूप में, अध्ययन में कहा गया है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की पुरानी समस्या के रूप में आवर्ती सूखे के बावजूद, कुछ हद तक सिंचाई के माध्यम से राहत, पेयजल और कृषि प्रोत्साहन के रूप में वैकल्पिक रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

धान की स्वदेशी किस्मों को बढ़ावा दें धान की लगभग 200 देशी किस्मों का संरक्षण करने वाले पद्मश्री बाबूलाल दहिया के अनुसार, जिन किसानों ने धान की स्वदेशी किस्मों की बुवाई की है, उन पर कम वर्षा का प्रभाव बहुत कम होगा। उन्होंने कहा, वर्तमान मौसम की स्थिति में धान की आधुनिक, संकर किस्मों को नुकसान होना तय है। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में धान की पारंपरिक किस्मों की खेती करना सबसे अच्छा है। धान विशेषज्ञ ने बताया कि धान की स्वदेशी किस्में कम पानी में पैदावार देती हैं, जबकि संकर किस्मों से पैदावार के लिए अच्छी बारिश के साथ ही सिंचाई की भी जरूरत होती है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

## बुंदेलखंड के 9 बांध नहीं भर सके

बुंदेलखंड के 9 बांध इस वर्ष भी नहीं भरे जा सके। वहीं मऊरानीपुर स्थित सपरार बांध लगातार छठे वर्ष खाली रह गया। बांध न भर पाने से इन इलाकों में रबी की फसल को सिंचाई का पानी नहीं मिल सकेगा। तमाम इलाकों में पीने का पानी का संकट भी खड़ा होगा। उप्र में सर्वाधिक 33 बांध बुंदेलखंड में हैं। इनमें 12 बांध झांसी, 7 ललितपुर, 2 छतरपुर, 1 पन्ना, 4 चित्रकूट, 6 महोबा एवं 1 बांध हमीरपुर में है। बुंदेलखंड के कई इलाकों में पिछले कई वर्ष से सामान्य बारिश भी नहीं हो रही। इस वजह से छोटी नदियों पर बने बांध नहीं भर पाते सिर्फ बेतवा, धसान, केन जैसी बड़ी नदी पर बने बांध ही भर पाते हैं। इस वर्ष भी सपरार, पथरई, सिजार, उर्मिल जैसी छोटी बरसाती नदियों पर बने बांध नहीं भरे जा सके हैं। मऊरानीपुर स्थित सपरार बांध पिछले 6 साल से नहीं भर सका। सिंचाई अभियंताओं के मुताबिक आखिरी बार वर्ष 2017 में भरा गया था। इसके बाद से यह अभी तक नहीं भरा जा सका। बांध की क्षमता 2692 मिलियन घन फुट पानी स्टोर करने की है, लेकिन इस दफा महज 498 मिलियन घन फुट पानी ही भर सका। जबकि पिछले वर्ष 807 मिलियन घन फुट पानी भरा गया था।

# चेहरा भी बदलेगी भाजपा!

## 2023 में बदल सकता है चेहरा

छत्तीसगढ़ भाजपा में लगातार हो रहे परिवर्तन को लेकर कयास लग रहे हैं। 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे डॉ. रमन सिंह छत्तीसगढ़ में भाजपा के इकलौते बड़े चेहरे हैं। उनके मंत्रिमंडल में उनके गुडविल में शामिल होने वाले नेता ही इन 15 सालों में मंत्री रहे। 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वह ओबीसी वर्ग से आते हैं। छत्तीसगढ़ में ओबसी की आबादी सबसे ज्यादा है। ऐसे में भाजपा इसी वर्ग को साधने में जुटी है। इसी आधार पर उन कयासों को बल मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा चेहरा बदल सकती है। ओबीसी वर्ग को साधने के लिए भाजपा ने अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही नारायण चंदेल भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। दोनों ओबीसी वर्ग में अच्छी पकड़ रखते हैं। मगर पार्टी इन चेहरों के जरिए प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुटी है।

भाजपा हाईकमान ने सत्ता में वापसी के लिए अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को बदलकर चुनावी मैदान में उतरने की ताल ठोंक दी है। वहीं अब जिला मंडल, प्रकोष्ठ, महिला मोर्चा के अध्यक्ष बदलने की शुरुआत जल्द होने वाली है। जो काम प्रदेश अध्यक्ष रहते साय नहीं कर पाए वह काम अरूण साव को कमान देकर दिल्ली से शुरू कर दी है। दोनों ही नेता का चयन दिल्ली से हुआ है, प्रदेश भाजपा कार्यालय में तो मात्र हाथ उठाकर समर्थन दिया गया। भाजपा लगातार 15 साल तक सत्ता में रही 2018 की चुनावी हार के सदमे से निकलने के लिए अपने ही सेकंड लाइन के नेताओं को फ्रंट लाइन में लाने की कवायद के साथ पूरे घर की लाइट बदलने की ठान ली है। भाजपा को मिली हार से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी थी। हार के बाद यह नाराजगी नेताओं के सामने भी फूटकर आ रही थी। 17 दिसंबर 2018 को नई सरकार का गठन हो गया। भाजपा विधायक दल का नेता नहीं तय कर पा रही थी। लगातार नेताओं के दिल्ली दौरे हो रहे थे। दिसंबर के आखिर में विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तय होना था, लेकिन विवाद की वजह से इसे टाल दिया गया। कहा गया, केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं हो पाए थे। जनवरी 2019 के पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और डॉ. अनिल जैन पर्यवेक्षक बनकर आए और धरमलाल कौशिक को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उनके नाम का प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह लाए थे। अब उनके मंत्रिमंडल में रहने वाले और करीबी लोगों को ही फ्रंट लाइन में जगह नहीं मिल रही है। जनता में खुसुर-फुसुर है कि यदि यही सब सत्ता वापसी का हिस्सा था, तो इतना इंतजार क्यों किया गया। साव और चंदेल को पहले ही कमान सौंपना था।

छत्तीसगढ़ में पुराने नेताओं के गुटीय प्रबंधन को राष्ट्रीय नेतृत्व में ध्वस्त कर दिया है। क्षेत्रीय प्रभारी अजय जामवाल के आने के बाद से छत्तीसगढ़ में प्रयोग और परिवर्तन शुरू हो गया है। इन्हीं प्रयोग के साथ भाजपा में अलग-अलग नेताओं के गुटों को तोड़ते हुए नए चेहरे को जनता के बीच सामने लाया गया। एक सप्ताह के अंदर पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया है। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 में भाजपा छत्तीसगढ़ में चेहरा भी बदल सकता है। हाल में हुए बदलाव से यही संकेत मिल रहे हैं।

दरअसल, छत्तीसगढ़ में भाजपा तीन टर्म लगातार सत्ता में रही है। चेहरा रमन सिंह थे। 2018 के विधानसभा चुनाव भी पार्टी रमन सिंह के नाम पर ही लड़ी थी। पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई। इसके कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी को अच्छी सफलता मिली। इसके बाद पार्टी के प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ। निकाय चुनाव से लेकर उपचुनाव तक में पार्टी हार गई। बताया जाता है कि एंटी इनकंबेंसी और गुटबाजी की वजह से पार्टी राज्य में कमजोर होती जा रही है। भाजपा को अब प्रदेश में एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो मैदानी इलाके से हो। साथ ही उसकी छवि साफ हो। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से विष्णुदेव साय को हटा दिया। उनकी जगह पर बिलासपुर सांसद अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। साव ने अपने सियासी कैरियर की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से की थी। पहली बार ही वह सांसद बने हैं। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव की कमान अरुण साव के हाथ में ही होगी।

छत्तीसगढ़ में साहू समाज भाजपा के परंपरागत वोटर थे लेकिन कांग्रेस के आने के बाद यह वोट शिफ्ट कर गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में ओबीसी वोटर ज्यादा हैं। उन वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने अरुण साव को मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में गद्दी पर कौन बैठेगा, यह ओबीसी वोटर ही तय करते हैं। इसके साथ ही कथित रूप से छत्तीसगढ़ संगठन में गुटबाजी ज्यादा बढ़ गई थी। अब अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष और नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष बने हैं। दोनों न तो रमन सिंह के गुट से आते हैं और न ही बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर जैसे नेताओं के गुट से ताल्लुक रखते हैं। इन दोनों लोगों से भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी नाराजगी नहीं है।

2018 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा काफी कमजोर दिखने लगी थी। इस करारी हार के बाद लगातार चार उपचुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव में भी भाजपा कुछ खास नहीं कर पाई। राज्य के सभी 14 नगर निगम में कांग्रेस के महापौर जीतकर चुने गए। इन्हीं हार के बाद लगातार भाजपा में नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगा था। राजनीतिक गलियारों में भी संगठन में बड़े फेरबदल को लेकर चर्चाएं जोर-शोर से चल रही थी।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

# मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की जमावट

## सत्ता और संगठन में बदलाव करेगी भाजपा | कांग्रेस भी संगठन में कसावट की तैयारी में

***पंचायत और निकाय चुनाव निपटने के बाद मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चौसर बिछने लगी है। भाजपा और कांग्रेस की कोशिश है कि 2023 में उनकी सरकार बने। ऐसे में मिशन 2023 के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस में जमावट शुरू हो गई है। भाजपा में सत्ता और संगठन में बदलाव की तैयारी चल रही है, वहीं कांग्रेस भी संगठन में कसावट करने में जुटी हुई है। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ मिशन 2023 की रणनीति पर काम कर रहे हैं।***

● राजेंद्र आगाल

मप्र में विधानसभा चुनाव के लिए अभी लगभग सवा साल का अरसा बाकी है। लेकिन प्रदेश में अभी से सत्ता का संग्राम छिड़ गया है। 2018 में विधानसभा हारने के बाद 2020 में सत्ता पलट के बाद सरकार बनाने में सफल हुई भाजपा की कोशिश है कि 2023 में 51 फीसदी वोट के साथ सरकार बनाए। वहीं 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस 15 माह बाद ही सत्ता से बेदखल होने के बाद 2023 में फिर से अपनी सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। इसके लिए दोनों पार्टियां संगठन को मजबूत करने के साथ ही सारे समीकरणों को साधने की जमावट कर रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कई रणनीतियों पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। चुनावी रणनीति के तहत दोनों पार्टियां अपने-अपने संगठन में बदलाव की तैयारी कर रही हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार में भी कई बदलाव होने की संभावना दिख रही है।

भाजपा और कांग्रेस का फोकस इस बात पर है कि 2023 में उनकी सरकार बने। अभी हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल का दौरा कर 20 घंटे में 200 सीटों का खाका तैयार किया है। वहीं आगामी दिनों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत मप्र भी आएंगे और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए जनाधार जुटाएंगे।

## सत्ता-संगठन में होंगे बड़े बदलाव!

मप्र में कांग्रेस को सत्ता से हटाकर भाजपा जब से सत्ता में आई है सरकार और संगठन में शह-मात का खेल चल रहा है। इस कारण भाजपा में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर आए थे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने आए गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश के टॉप लीडर्स के साथ वन टू वन मीटिंग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खुलकर सराहना की है। शिवराज की तारीफ को लेकर प्रदेश में सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर अमित शाह ने टॉप लीडर्स से वन टू वन मीटिंग क्यों की है।

शिवराज सिंह चौहान को हाल ही में भाजपा संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह पर मप्र से दलित नेता सत्यनारायण जटिया को जगह मिली है। इसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है। इन अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सिमी जैसे आतंकी संगठन को मप्र की धरती से शिवराज सिंह चौहान ने उखाड़ फेंका है। उन्होंने नक्सलवाद, माफिया के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती है। वहीं, लगातार दो डिजिट में कृषि के क्षेत्र में जीडीपी का होना चौहान के परिश्रम की पराकाष्ठा को दर्शाता है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने मप्र सरकार के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा है कि नक्सलवाद को समाप्त किया है। कानून-व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का कार्य शिवराज सरकार ने किया है। एक जमाने में मालवा सिमी का गढ़ था। सिमी को समूल उखाड़ फेंकने का कार्य किया है। वहीं, अपने भोपाल दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश भाजपा के टॉप लीडर्स के साथ वन टू वन मीटिंग की है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ लगभग आधे घंटे तक उन्होंने मीटिंग की है। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा से भी अलग से बात की है।

## क्या हैं इस मीटिंग के मायने

दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद प्रदेश में कई तरह की अटकलें चल रही हैं। साथ ही यह भी चर्चा है कि 2023 में भाजपा किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की है। इसके साथ ही उन्होंने अभी बदलाव के अटकलों पर विराम लगा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने सरकार और संगठन के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया है। पहली बार अमित शाह भोपाल में 20 घंटे तक रुके हैं। गौरतलब है कि मप्र में आने वाले दिनों में संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। इसके साथ ही निगम मंडलों में कुछ नियुक्तियां लटकी हैं, उसे लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। निकाय चुनाव में हार के कारणों पर भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं से चर्चा की है।

## शाह ने टटोली नब्ज

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के बाद से ही मप्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। शाह ने जहां राजधानी में मुख्यमंत्री चौहान से लेकर संघ के पदाधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा कर प्रदेश की सियासी नब्ज टटोली। वहीं कैलाश-सिंधिया की मुलाकात को नए प्रदेश की सियासत में नए समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह के भोपाल दौरे के पहले से ही माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश में कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। शाह के दौरे के ठीक पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत भी भोपाल आए थे। जानकार इसे भी सियासत से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इन दौरों के बाद ही संसदीय बोर्ड में 9 साल से जमे एकमात्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को हटा दिया गया था। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश के सभी बड़े नेताओं के साथ वन टू वन चर्चा की। पहले उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ लगभग आधे घंटे तक मीटिंग की। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी चर्चा की। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा से भी अलग से बात की। शाह ने राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी अलग से समय दिया। इस दौरान शाह ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए फीडबैक लिया। इसके पहले भी शाह जब अप्रैल में भोपाल आए थे, तब उन्होंने संगठन की बजाय सत्ता में शामिल नेताओं से बात की थी। इस बार उन्होंने सिर्फ प्रदेश के चार बड़े नेताओं से ही मुलाकात की है। पहली बार अमित शाह भोपाल में 20 घंटे तक रुके हैं। प्रदेश में आने वाले दिनों संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। इसके साथ ही निगम मंडलों में कुछ नियुक्तियां लटकी हैं, उसे लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। निकाय चुनाव में हार के कारणों पर भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं से चर्चा की है।

## आदिवासियों पर पूरा फोकस

भाजपा का आदिवासियों पर भी पूरा फोकस है। आदिवासी बहुल सीटों के लिए भाजपा हर कदम फूंक-फूंक कर रख रही है। ऐसे माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सुलोचना रावत को मौका दिया जा सकता है। क्योंकि वह आदिवासी बहुल जोबट सीट से उपचुनाव जीती हैं, जबकि यह सीट 2018 में कांग्रेस को मिली थी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने के प्रयास किए जाएंगे। शिवराज मंत्रिमंडल में अभी 4 पद खाली हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही शिवराज कैबिनेट में दो से तीन मंत्रियों को और बढ़ाया जाएगा। वहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसी मंत्री को बाहर करने की संभावना फिलहाल नहीं है। इन सभी विषयों पर शाह से चर्चा हुई। पार्टी से जुड़े सूत्रों की मानें तो पिछले दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों से जीत दर्ज कर जिस तरह से ग्राम पंचायतों से लेकर जनपद और जिला पंचायत के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष जैसे पद हासिल किए है, उसे राजनीति के जानकार भाजपा के बढ़े जनाधार से जोड़ रहे

## सिंधिया-विजयवर्गीय की मुलाकात से नई हवा

गृहमंत्री के भोपाल दौरे के बीच इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मुलाकात ने भी हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस में रहने के दौरान सिंधिया और कैलाश की सियासी दुश्मनी से सभी वाकिफ रहे हैं। भाजपा में आने के बाद सिंधिया और कैलाश के संबंध ज्यादा ही गहरे दिखने लगे है। इंदौर में सिंधिया ने यह संकेत दिए कि हम कैलाश विजयवर्गीय के साथ कदमताल के लिए तैयार है। इससे प्रदेश की राजनीति में एक नए गठजोड़ की चर्चा हो रही है। साथ ही बदलाव की बातों को और बल मिलने लगा है। मप्र के सियासी गलियारों में फिर हलचल है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में प्रदेश की टॉप लीडरशिप से वन टू वन बात की है, जिसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उधर, इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में काम करने की बात करके सबको चौंका दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह के भोपाल दौरे से पहले माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रदेश में कोई बड़ा कदम उठाने वाली है।

है। शाह के सामने यह पूरा विश्लेषण किया गया।

माना जा रहा है निकाय चुनाव के बाद शाह नए तरीके से रणनीति बनवाएंगे। क्योंकि इन चुनावों के बाद भाजपा में फिर से समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। पिछली बार सभी 16 नगर निगमों में क्लीन स्वीप करने वाली भाजपा को इस बार 9 नगर निगमों में ही मेयर के चुनाव में सफलता मिली है। जीत का शेयर उसका प्रदेश में भले ही ज्यादा हो पर जहां हारे वहां हार के कारणों की समीक्षा में संगठन के आला नेता जुट गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा किसी भी चुनाव में उतरने से पहले ही हर काम पर बारीक नजर रखती है। अमित शाह की नजर में भी 2018 में भाजपा के लिए आया यह गैप होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा अब इस गैप को भरने की कवायद में जुटी है। दरअसल, भाजपा में अमित शाह संगठन को चलाने में सबसे मजबूत माने जाते हैं, यही वजह है कि भाजपा ने उनके जरिए ही मप्र में फिर से 2013 का कमाल दोहराना चाहती है, क्योंकि अमित शाह इस मामले में माहिर है।

## नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मप्र दौरे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि ये मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से नियमित मुलाकात थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भोपाल के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामों की तारीफ की। वहीं गृहमंत्री शाह ने संगठन और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की। इस दौरान अमित शाह ने संगठन को आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने मप्र दौरे पर आदिवासियों के एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। वहीं मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। राज्य में नेतृत्व को लेकर कुछ महीनों की अनिश्चितता और भ्रम के बाद हाल के घटनाक्रम से संकेत मिल रहा है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व अपनी सरकार के काम करने के तरीके से काफी संतुष्ट है। भोपाल में अपने आधिकारिक दौरे के

## शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द!

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बार फिर दिल्ली का दौरा किया और 30 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि सितंबर के पहले सप्ताह में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय, सामाजिक, जातिगत फॉर्मूले के अनुसार विस्तार करेगी। ऐसे में कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, वहीं कुछ का कद बढ़ाया जा सकता है। वहीं कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण है। शिवराज के इस दौरे पर सभी की निगाहें लगी हुई थीं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद मंत्री पद के दावेदारों ने भी सक्रियता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश मंत्रिमंडल में अभी चार पद रिक्त हैं। इन चार पदों के लिए करीब एक दर्जन विधायक दावेदार हैं। इनमें कई वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री तक शामिल हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा संगठन व सत्ता दोनों ही इन रिक्त पदों को भरने के पक्ष में बताए जाते हैं। अभी शिवराज कैबिनेट में 30 मंत्री हैं जिनमें से 23 कैबिनेट और 7 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में फिलहाल क्षेत्रीय संतुलन कम है। विंध्य अंचल से सर्वाधिक विधायक आते हैं, वहां से सबसे कम मंत्री हैं। यही हाल महाकौशल अंचल में बना हुआ है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्य, महाकौशल के अलावा मालवा से भी एक-एक विधायक को जगह दी जा सकती है। इसमें भी एक मंत्री अनुसूचित जाति को जाना तय है। फिलहाल मंत्री पद के दावेदारों में अजय विश्नोई, संजय पाठक, राजेंद्र शुक्ला, केदार शुक्ला, रमेश मेंदोला, नागेंद्र सिंह, यशपाल सिंह सिसोदिया और सुलोचना रावत के नाम शामिल हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि इसके साथ ही कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया जा सकता है। यह वे मंत्री हैं, जिन्हें अब तक सत्ता व संगठन नॉन परफॉर्मिंग मान रहा है। इसके पीछे ठोस वजह भी है। हाल ही में हुए पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन मनमाफिक नहीं रहा। लिहाजा आलाकमान की नाराजगी की बातें भी सामने आ रही हैं। सत्ता और संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 10 मंत्रियों की परफॉर्मेंस खराब है। इनमें वे मंत्री शामिल हैं, जिनके पास भारी भरकम विभाग हैं। खबर तो यह भी है कि दो से तीन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री चुनाव के पहले रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, ऐसे में मंत्री पद से किसे हटाया जाएगा, यह फैसला केंद्रीय हाईकमान को लेना है।

दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की और कहा कि जिस तरह से सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को लागू कर रही है, वह काबिले तारीफ है। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। पार्टी सूत्रों ने बताया कि यह मुलाकात नियमित है। ऐसा लगता है कि नए घटनाक्रम ने शीर्ष पद के लिए शिवराज सिंह चौहान की जगह लेने के इच्छुक लोगों को निराश किया है। गृहमंत्री शाह ने भोपाल में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने महज 12 मिनट में अपना ढाई किलोमीटर लंबा रोड शो खत्म किया और फिर भाजपा कार्यालय पहुंच गए जहां उन्होंने संगठन के नेताओं के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे तक अमित शाह ने संगठन के नेताओं के साथ बैठक की और सरकार के कामों पर प्रसन्नता व्यक्त की।

## नरोत्तम-वीडी के चेहरे पर मुस्कान

शिवराज सिंह चौहान के संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने के बाद मप्र में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सियासी पंडित तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भोपाल में 20 घंटे तक रुककर अलग ही संदेश दे गए हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शिवराज का जमकर गुणगान किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में केंद्रीय गृहमंत्री के सामने मप्र के तीन पॉवरफुल नेता एकसाथ खड़े हैं। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा,

प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और वीडी शर्मा तस्वीर में मुस्करा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री कथित रूप से तस्वीर में मायूस दिख रहे हैं। शिवराज के बॉडी लैंग्वेज पर कांग्रेस ने मजे लिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया कि तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। मामाजी को छोड़ वीडी भाई, नरोत्तम मिश्रा बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मामाजी के सर पर छतरी भी नहीं, लगता है सब मिलकर भिगोकर ही रहेंगे।

दरअसल हाल ही में भाजपा के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से शिवराज को हटा दिया गया है। उनकी जगह 76 वर्षीय प्रदेश के सत्यनारायण जटिया को शामिल किया गया है। भाजपा के सबसे पॉवरफुल बोर्ड से शिवराज को हटाने के बाद तरह-तरह के कयास लग रहे हैं। इस 2023 के पहले मप्र की सियासत में बदलाव के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। अब केंद्रीय गृहमंत्री के दौरे के बाद उनके प्रदेश के टॉप लीडर्स से वन टू वन चर्चा के बाद फिर कयासों का दौर शुरू हो गया है।

## तीनों की तारीफ के क्या मायने

भोपाल में एक पुलिस के कार्यक्रम में उन्होंने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। वहीं, विधानसभा सभागार में कुशाभाऊ जन्मशताब्दी पर नई शिक्षा नीति सेमिनार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तारीफ की। गृहमंत्री की तारीफ से तीनों को लेकर जारी कयासों पर कुछ दिन के लिए विराम लग गए हैं। मप्र में हाल में संपन्न हुए निकाय चुनाव में भाजपा को 16 में से 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। यह चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज के चेहरे पर लड़ा जा रहा था। ऐसे में उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद संसदीय बोर्ड से उनका बाहर जाना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही 2023 में चेहरे बदलने की बात को इसके बाद से और बल मिला है।

## मिशन 2023 के पहले पिछड़ा बनाम ब्राह्मण की सियासत में फंसी भाजपा, ओबीसी वोट बैंक हो सकता है गेमचेंजर

मप्र में विधानसभा चुनाव होने में एक साल से भी कम का वक्त बचा है और भाजपा ओबीसी बनाम ब्राह्मण की सियासत में फंसती दिख रही है। सागर जिले में लगभग एक साल पहले ब्राह्मण समुदाय की एक लड़की और ओबीसी समुदाय के एक व्यक्ति का अफेयर सामने आया था। इस घटना के बाद ओबीसी परिवार के घर को तोड़ा गया और उसके साथ एक तनाव का माहौल बन गया था। अब ऐसा ही कुछ तनाव भाजपा द्वारा प्रीतम लोधी को बर्खास्त करने के बाद पूरे राज्य में दिख रहा है। दरअसल पूर्व भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने आपत्तिजनक बयान दिया था कि ब्राह्मण और स्वयंभू आध्यात्मिक नेताओं ने महिलाओं को बेवकूफ बनाया और उन्हें पैसे खर्च करने के लिए मजबूर किया। जिसके

बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया। लोधी ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण से हाथ मिलाया और कथित अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। इस बीच, शिवपुरी के चित्रापुर गांव में मुख्य रूप से लोधी समुदाय के स्थानीय लोगों ने किसी भी ब्राह्मण को किसी भी काम के लिए आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने इस नियम को तोड़ने पर 2100 रुपए के जुर्माने का भी ऐलान किया है। ऐसे में अब ओबीसी महासभा राज्य सरकार के खिलाफ 4 सितंबर को बांदा सागर में महापंचायत करने जा रही है। बता दें कि मप्र में लगभग 52 फीसदी आबादी वाले ओबीसी अब भाजपा की चिंता बढ़ा रहे हैं। भाजपा 2003 में ओबीसी वोटों के समर्थन से सत्ता में आई थी खासकर लोधी के समर्थन से, जिसका मप्र की 40 सीटों पर मजबूत प्रभाव है। जिसकी मदद से उमा भारती मुख्यमंत्री बनीं। बाद में उनकी जगह एक अन्य ओबीसी नेता बाबूलाल गौर को लाया गया और गौर की जगह शिवराज सिंह चौहान को लिया गया। लगातार तीन बार भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में ओबीसी मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई। जानकारों का कहना है कि भाजपा को इस मुद्दे से निपटने के लिए मजबूत रणनीति बनानी होगी क्योंकि यह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खतरनाक हो सकता है। इस बीच भाजपा ने नुकसान को नियंत्रित करने के लिए ग्वालियर से पूर्व विधायक नारायण सिंह कुशवाहा को पार्टी के ओबीसी विंग के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। सितंबर 2021 में सेमरा लहरिया गांव के 25 वर्षीय राहुल यादव को 16 सितंबर को 23 वर्षीय चंचल शर्मा के परिवार द्वारा कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था और छत से धक्का दे दिया गया था जब वह उससे मिलने गया था। सेमरा लहरिया गांव में यादव की मौत के बाद पुलिस ने चार लोगों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया और जिला प्रशासन ने ब्राह्मण समाज के सदस्यों के घर को ढहा दिया था। मप्र में पहली बार ब्राह्मण समुदाय ने राज्य सरकार के खिलाफ एक महापंचायत आयोजित करने की घोषणा की थी और इसके चलते बाद में पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर का तबादला कर दिया गया।

# घर दुरुस्त करने में जुटे कमलनाथ

15 साल बाद मिली सत्ता 15 महीने में ही खोने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अब पूरी तरह मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वे अपना घर (मप्र कांग्रेस) दुरुस्त करने में जुट गए हैं। इसके लिए सर्वे कराकर पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसी संदर्भ में गत दिनों पीसीसी में बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायकों, विधानसभा, लोकसभा, मेयर के पूर्व प्रत्याशी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी के अलावा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी शामिल हुए। कमलनाथ ने जिला प्रभारियों, सह प्रभारियों और जिलाध्याक्षों से स्पष्ट कहा कि यदि आपके पास पार्टी और संगठन के लिए समय नहीं है तो अभी बता दो। ऐसे पदों पर हम आने दूसरे मेहनती लोगों को मौका देंगे। बैठक में कमलनाथ ने कहा कि दो सौ गाड़ियों का काफिला लेकर भोपाल आने वाले नेताओं को जमीन पर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। कारों के काफिले से नहीं जमीन पर काम करने से जीत मिलेगी। अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं ऐसे में हवाबाजी के बजाय जमीन पर काम करने से ही कामयाबी मिलेगी। बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायकों को भी संगठन के कामों पर ध्यान देने की नसीहत दी। इसके कुछ देर बाद दो विधायक बैठक से बाहर निकल गए। हालांकि जब जीतू पटवारी से मीटिंग में पीसीसी चीफ द्वारा फटकारने की वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई फटकार नहीं लगाई।

मप्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने तैयारियां तेज कर दी हैं। हाल ही में हुए नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस को 5 नगर निगमों में मिली कामयाबी के बाद अब जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती के प्रयास तेज हो गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जमीनी स्तर पर कांग्रेस के संगठन को खड़ा करने की कमान अपने हाथ में ली है। वे विधायकों और व्यक्ति विशेष के बजाय संगठन की कमान जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों के हाथों में सौंपने की तैयारी में हैं। विधायकों से जिलाध्यक्षों का प्रभार वापस लेकर फुल टाइम वर्कर को जिला कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी जा रही है।

पीसीसी चीफ कमलनाथ से जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में नाम चलने का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा- मैंने साफ कर दिया है कि मैं मप्र नहीं छोड़ूंगा। मप्र में ही रहूंगा। कई विधायक ऐसे थे जिनके पास एक से अधिक पद थे। उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन जिलों में हम नए जिलाध्यक्ष बनाएंगे। धार में मिट्टी का डैम बनाया था, वह टूट गया। मुआवजा कब मिलेगा प्रभावितों को कुछ पता नहीं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शिवराज सिंह का हवाई सर्वे भी हवाई है, मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं। शिवराजजी मीडिया इवेंट करने में माहिर हैं।

जानकारी के अनुसार निकाय चुनाव में गड़बड़ी करने वाले और निष्क्रिय जिलाध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। पीसीसी से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 10 जिलों के जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। प्रदेश स्तर से जारी होने वाले संगठन के कामों में ढ़ील बरतने वाले जिलाध्यक्षों को बदलकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा सकता है। बैठक के बाद पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि भाजपा के नेता ही अपनी पार्टी के फैसलों से खुश नहीं हैं। अभी जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उनमें भाजपा के कई नेताओं ने कांग्रेस की मदद की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भाजपा की अंर्तकलह का फायदा मिलेगा। जबलपुर नगर निगम के चुनाव के बाद नाराज चल रहे बरगी विधायक संजय यादव ने कहा परिवार में ऐसा होता रहता है। कमलनाथ के नेतृत्व में अगले विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतेंगे। जबलपुर को लेकर जो शिकायतें थीं उनके संबंध में आज सारी बातें हो गई हैं। हम कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहे थे।

दरअसल, 2018 में करीब 15 साल बाद मप्र में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया था। दलबदल के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस को कई क्षेत्रों में करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के संगठन की कमान व्यक्ति विशेष के बजाय विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं के हाथ में देने के लिए कमलनाथ बदलाव कर रहे हैं। पीसीसी के एक पदाधिकारी ने बताया कि यदि किसी नेता विशेष के हिसाब से संगठन में नियुक्तियां होती हैं यदि नेता पार्टी छोड़ देता है तो उस इलाके में संगठन का काम कमजोर पड़ जाता है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब कमलनाथ चाहते हैं कि संगठन का काम कांग्रेस की विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं को दिया जाए और बूथ से लेकर ब्लॉक, जिला स्तर के संगठन की कमान जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों के हाथ में हो। पीसीसी को मिली रिपोर्ट के मुताबिक कई कांग्रेस के नेताओं ने नगर पालिका, नगर परिषद और जनपद अध्यक्ष बनने के लिए अघोषित रूप से भाजपा को समर्थन दे दिया। ऐसे नेताओं की रिपोर्ट भी पीसीसी को मिली है जो भाजपा नेताओं से करीबियां बढ़ा रहे हैं और भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। पीसीसी ने दो नावों की सवारी कर रहे ऐसे नेताओं की भी जानकारी मंगाई है।

## कांग्रेस में होगी जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति

मप्र में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस की हर बैठक में कमलनाथ ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि भाजपा के संगठन से है। भाजपा के संगठन का मुकाबला करने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ अब कांग्रेस के संगठन को भी उसी हिसाब से तैयार करने में जुटे हैं। भाजपा के संगठन मंत्रियों की तरह कांग्रेस में भी जिला संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ये महामंत्री बूथ लेवल से लेकर मंडलम्, सेक्टर तक के संगठन की गतिविधियों को क्रियान्वित करेंगे और सीधे पीसीसी चीफ को रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही ऐसे सर्वमान्य नेताओं के नाम पर विचार किया जा रहा है जिन्हें स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान हो। हालांकि भाजपा ने विभाग संगठन मंत्रियों और संभागीय संगठन मंत्रियों की छुट्टी कर उन्हें सत्ता और पार्टी में एडजस्ट कर दिया है। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कमलनाथ अब दलबदल से निपटने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। भाजपा सहित दूसरे दलों से आकर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं को टिकट देने के बजाय कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी दी जाएगी।

# राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव

राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से उथल-पुथल के संकेत मिल रहे है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राज्य सरकार जल्द ही अपने केबिनेट में फेरबदल की तैयारियों में है। माना जा रहा है कि, राजस्थान में अगले साल 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य की गहलोत सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है। मुख्यमंत्री ने आलाकमान के निर्देश पर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अगले महीने छह मंत्रियों को बदला जा सकता है। यह मंत्रिमंडल बदलाव दो मुख्य आधार पर होना तय किया गया है, उनमें पहला आधार है परफॉर्मेंस और दूसरा है जातिगत समीकरण। इन दोनों आधारों पर ही अब राजस्थान में अगले डेढ़ साल की राजनीति चलने वाली है।

राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी 2 साल का समय पूरा हो चुका है। हाल ही में डोटासरा ने 2 साल का समय पूरा होने के बाद अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने के मद्देनजर एक बड़ी जनसभा की थी। हालांकि उसके बाद अभी तक मुख्यमंत्री की ओर से या आलाकमान की ओर से बदलाव के संकेत नहीं दिए गए हैं। लेकिन यह माना जा रहा है कि अगस्त के महीने में गोविंद सिंह डोटासरा को बदलने के बाद किसी बड़े नेता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान दी जा सकती है। 2 साल के दौरान अपने भाषणों के चलते डोटासरा कई बार मीडिया के निशाने पर रह चुके हैं।

राजस्थान में ब्लॉक स्तर से लेकर जिलों के कांग्रेस अध्यक्ष तक के कई पद खाली पड़े हैं। इन पदों को पहले भी भरने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय नेताओं के असंतोष के कारण सूचियों पर आखिरी मुहर नहीं लग सकी। इस असंतोष को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने चुनिंदा मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी। बताया जा रहा है कि मंत्रियों ने यह जिम्मेदारी पूरी करते हुए आपसी खींचतान और तनातनी के माहौल को खत्म कर दिया है। जो नाम फाइनल किए गए है वह सभी की सहमति से फाइनल है। इन लिस्टों के आधार पर ही अब ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर जिलों के अध्यक्षों तक को बदला भी जाएगा और नए अध्यक्षों को जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। यूआईटी एवं अनेक बोर्डों में इसी महीने राजनीतिक नियुक्तियों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। जिन सीनियर नेताओं को मंत्री पद की कुर्सी नहीं मिल पाएगी उन नेताओं को निगम एवं बोर्ड के अध्यक्षों के तौर पर राज्यमंत्री का जिम्मा दिया जाएगा। आपसी खींचतान और सभी पक्षों में सहमति नहीं बनने के कारण राजस्थान में ज्यादातर राजनीतिक पद कई समय से खाली ही पड़े हैं। संभावना जताई जा रही थी कि 15 अगस्त से पहले राजस्थान के मंत्रिमंडल से लेकर राजस्थान में कांग्रेस के कई पदों पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आने वाले समय में यह संभव हो सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के पास दिल्ली भी जाने की तैयारी कर रहे हैं।

राजस्थान की राजनीति में भाजपा नेताओं का पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर प्रेम किसी से छुपा नहीं है। हर कुछ महीनों बाद किसी ना किसी भाजपा नेता के मुखारविंद से पायलट की तारीफों में सुर फूटते हैं। इस फेहरिस्त में ताजा नाम राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का जुड़ा है जिन्होंने हाल में मुक्तकंठ से सचिन पायलट की जमकर तारीफ की है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के बाद भाजपा नेता की पूर्व उपमुख्यमंत्री पायलट की तारीफ करने के कई सियासी मायने हैं। कटारिया के बयान के बाद सियासी गलियारों में कई अटकलों को हवा मिली है। मालूम हो कि पायलट को लेकर भाजपा नेताओं की यह हमदर्दी ताजा नहीं है। राज्य के कई भाजपा नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट की 2020 की खींचतान के बाद से लगातार पायलट की तारीफ करते रहे हैं। वहीं एक बार फिर गुलाब चंद कटारिया के पायलट की तारीफ करने को आने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।

बता दें कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने हाल में कहा कि राजस्थान में मरी हुई कांग्रेस पार्टी को उस व्यक्ति (सचिन पायलट) ने अपने परिश्रम से जिंदा किया जिसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है की भाजपा गहलोत-पायलट की तकरार को चुनावी हथियार बनाते हुए कांग्रेस को घेरना चाहती है। कटारिया ने दौसा में कहा कि सचिन पायलट ने मरी हुई कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने का काम किया है। उन्होंने कहा, पायलट को मुख्यमंत्री गहलोत नाकारा कहते हैं, उनके लिए निकम्मा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन पायलट की मेहनत को कोई नकार नहीं सकता है। कटारिया ने कहा कि जो पार्टी 21 विधायकों पर सिमट गई थी उसकी पायलट ने राज्य में सरकार बनाने का काम किया है। वहीं गहलोत का नाम लिए बिना कटारिया ने कहा वह अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

## केंद्रीय चुनाव समिति में राजस्थान का दबदबा

भाजपा ने हाल में केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया जिसके 15 सदस्यों में राजस्थान के दो वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता ओमप्रकाश माथुर और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य नियुक्त किया है। मालूम हो कि भाजपा में चुनावों के लिहाज से तैयारियों और स्ट्रेटेजी को देखते हुए केंद्रीय चुनाव समिति का रोल अहम माना जाता है। वहीं समिति में राजस्थान से दो भाजपा नेताओं के नियुक्त करने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव अमित शाह और ओमप्रकाश माथुर प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते रहे हैं। भाजपा में इन दो नेताओं की नियुक्तियों के बाद केंद्र में राजस्थान का दखल और दमखम बढ़ गया है। वहीं 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में उससे पहले इन नियुक्तियों को चुनावी लिहाज से काफी अहम तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले हाल में सुनील बंसल को भाजपा ने राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया था। इधर केंद्रीय चुनाव समिति में राजस्थान से 2 नेता शामिल होने के बाद राजस्थान का रोल केंद्र में बढ़ गया है। बता दें कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा भी राजस्थान के ही नेता ओम बिरला और जगदीप धनखड़ संभाल रहे हैं। इसके अलावा मोदी मंत्रिपरिषद में राजस्थान से 4 मंत्री हैं और पार्टी के एक राष्ट्रीय महामंत्री भी राजस्थान से आते हैं। बता दें कि ओम माथुर के समिति में शामिल होने के बाद लंबे समय से चल रहा उनका सियासी वनवास अब खत्म हो गया है।

*बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने भाजपा खेमा छोड़कर महागठबंधन में एंट्री कर ली है। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है, जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। इस तरह मोदी के विकल्प के रूप में विपक्ष को एक और नेता मिल गया है। जबकि पहले राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक विपक्ष के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे।*

# मोदी की टक्कर में कौन-कौन?

नीतीश कुमार भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में लौट आए। नीतीश पूरा मन बनाकर भाजपा से अलग हुए हैं और जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद अपने तेवर दिखाए हैं, वो एक तरह से भाजपा और मोदी को सीधे चुनौती है। उन्होंने 2022 में ही 2024 के युद्ध का ऐलान कर हवा दे दी है जो संकेत देती है कि वह भी विपक्ष का चेहरा बनने का लिए तैयार हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खुद को विपक्ष की पिक्चर में लीड रोल के लिए पहले से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बेताब हैं। दिल्ली दरबार का रास्ता तय करने और विपक्ष का चेहरा बनने की चाह रखने वाले इन चारों ही नेताओं की अपनी-अपनी सियासी ताकत हैं।

## नीतीश कुमार की ताकत

दिल्ली के सत्ता का रास्ता हिंदी बेल्ट वाले राज्यों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को भी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए गुजरात के बजाय उप्र को अपनी कर्मभूमि बनाना पड़ा था। नीतीश कुमार की यही सबसे बड़ी ताकत है कि वो बिहार से आते हैं। बिहार ही नहीं बल्कि हिंदी पट्टी वाले राज्यों में नीतीश कुमार की अपनी एक पहचान है।

नीतीश कुमार के पास शासन चलाने का अच्छा खासा अनुभव है। चार दशक के लंबे सियासी सफर में नीतीश ने सफलता के कितने पड़ाव पार किए हैं। केंद्र में मंत्री के तौर पर काम करने से लेकर पिछले 17 सालों से बिहार की सत्ता के नीतीश कुमार धुरी बने हुए हैं। आठवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। सत्ता का ये लंबा अनुभव उनके लिए 2024 में एक तरह से सियासी संजीवनी साबित हो सकता है।

नीतीश कुमार ओबीसी समुदाय के कुर्मी जाति से आते हैं, जो उनके लिए एक बड़ी ताकत बन सकता है। मौजूदा दौर में देश की राजनीति ओबीसी केंद्रित हो गई है। भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया था तो उन्हें ओबीसी नेता के तौर पर पेश किया था। वहीं, नीतीश कुमार की पहचान एक ओबीसी नेता के तौर पर रही है। नीतीश का कुर्मी समाज बिहार से लेकर उप्र, मप्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अच्छी खासी संख्या में है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ओबीसी का होना एक ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है।

नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी छवि रही है और खासकर महिलाओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। नीतीश कुमार महिला वोटरों का सहारे लगातार जीत का परचम फहरा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी, साइकिल बांटना और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने जैसे तमाम कदम नीतीश ने उठाए हैं। 2020 के चुनाव में अंतिम समय में महिला वोटरों ने बचा लिया।

नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में 17 सालों से काबिज हैं। ऐसे में विकास करने वाले, अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाले साफ-स्वच्छ छवि के नेता बनकर उभरे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का दाग सीधे तौर पर नहीं लगा है। ऐसे में उनकी साफ छवि उन्हें विपक्षी चेहरे के तौर पर खड़े होने में काफी मददगार साबित हो सकती है। नीतीश कुमार आपातकाल के दौर से निकले हैं, लेकिन सियासी बुलंदी उन्हें मंडल के दौर में मिली है। मंडल युग के दिग्गज नेताओं में नीतीश कुमार गिने जाते हैं। जातिगत जनगणना

## राहुल गांधी की ताकत

भाजपा के बाद आज भी देश की दूसरी सबसे बड़ी कांग्रेस है। राहुल गांधी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता है। संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष में सबसे ज्यादा सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। भाजपा के खिलाफ देश में विपक्षी एकता कांग्रेस के बिना संभव नहीं है। राहुल गांधी की यही सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आधार पर पार्टी उन्हें 2024 में मोदी के सामने विकल्प के तौर पर स्थापित करना चाहती है। कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है, जिसका सियासी आधार किसी एक-दो राज्य में नहीं बल्कि देशभर के राज्यों में है। राहुल गांधी की पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपने दम पर सरकार चला रही है तो तमिलनाडु और बिहार में सहयोगी दल के तौर पर शामिल है। इसके अलावा कई राज्यों में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही है। ऐसे में कांग्रेस का व्यापक आधार ही उसे भाजपा के सामने मजबूती से खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को लेकर खुलकर निशाना साधते रहते हैं। जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क से संसद तक भाजपा के खिलाफ कांग्रेस लड़ती नजर आती है। कांग्रेस नेताओं की ओर से बार-बार यह बात कही भी जाती है कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ही इकलौती पार्टी है, जो जमीनी स्तर पर लड़ सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनकी पार्टी का एकमात्र सपना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस राहुल गांधी को एक मजबूत विकल्प के रूप मे पेश करती रही है। कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है, जिसके जरिए भाजपा के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को स्थापित करने की रणनीति है।

## ममता बनर्जी की ताकत

बंगाल की राजनीति में अपने दम पर लेफ्ट का किला ध्वस्त कर बड़ा सियासी बदलाव करने वाली ममता बनर्जी इस समय देश में इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं। ममता की महिला वोटरों के बीच अच्छी खासी पकड़ है। यही वजह रही कि भाजपा ममता के दुर्ग को नहीं भेद सकी। ममता बनर्जी की यही सबसे बड़ी ताकत है। ममता महिलाओं में लोकप्रिय हैं और ममता इस लोकप्रियता को चुनावों में भुनाना भी जानती हैं। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में मजबूत पकड़ है। बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा सीटें अभी भी टीएमसी के पास है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ममता बनर्जी जिस तरह से अपना किला मजबूत करने में जुटी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के मूड में है ताकि 2024 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर सकें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि बंगाल में एक जननेता और गरीबों के हमदर्द के तौर पर मानी जाती है। ममता की छवि सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है बल्कि देश के दूसरे राज्यों के लोग भी मानते हैं कि ममता गरीबों की हितैषी हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और जनता से कनेक्ट करती है। ममता बनर्जी ने संघर्ष कर जमीनी नेता के तौर पर खुद को स्थापित किया है। ममता ने अपनी सियासी राह खुद टेढे-मेढ़े रास्ते पर चलकर बनाई है। नंदीग्राम और सिंगूर में उनके संघर्ष को बंगाल ही नहीं बल्कि देश ने देखा, जिसके चलते उनकी सियासी कामयाबी का रास्ता खुला और आज बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर बैठी हैं।

को नीतीश कुमार एक सियासी हथियार के तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं।

## अरविंद केजरीवाल की ताकत

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस समय जोश से भरी हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर अपने पैर पसार रही है। दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता पर काबिज हो चुकी है और गुजरात से लेकर दक्षिण तक अपना सियासी आधार बढ़ा रही है। ऐसे में 2024 के चुनाव में केजरीवाल एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के विकास मॉडल के सहारे मिडिल क्लास समाज पर मजबूत पकड़ बनाई है तो शहरी युवाओं के बीच गहरा जुड़ाव भी देखने को मिला है। केजरीवाल का फ्री बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा समाज के माध्यम वर्ग को प्रभावित कर रही है।

आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर जबर्दस्त तरीके से मजबूत पकड़ रखते हैं। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के आधार पर केजरीवाल हिंदी पट्टी वाले राज्यों से लेकर दक्षिण भारत तक के लोगों से सीधे कनेक्ट करते हैं। विपक्ष के आरोपों का उसी भाषा में तुरंत जवाब देने के लिए माहिर है। अन्ना हजारे के एंट्री करप्शन आंदोलन से निकलकर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। केजरीवाल ने अपनी पार्टी की छवि को भ्रष्टाचार विरोधी बनाए रखा है, जिसके चलते उन्होंने दिल्ली से लेकर पंजाब तक में जिस भी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसे सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया। केजरीवाल साफ कहते हैं कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस नीति पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी कमजोरी है कि उनकी आम आदमी पार्टी चंद लोगों के हाथों तक ही सीमित है। संगठन में उन्हीं नेताओं को जिम्मेदारी मिली हुई है, जो केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा बाकी नेता किसी तरह के कोई अहम रोल में नहीं हैं।

अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी पर वर्चस्व कायम है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के संयोजक भी है। आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर अभी तक केजरीवाल पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में पार्टी के जिस भी नेता ने उन्हें चुनौती देने की कोशिश की, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आम आदमी पार्टी के गठन करने वाले तमाम नेता एक-एक कर दूर हो गए। आम आदमी पार्टी में वन मैन शो वाली पार्टी है और उसके कर्ताधर्ता केजरीवाल हैं।

अरविंद केजरीवाल की राजनीति दरअसल एनजीओ मॉडल की राजनीति है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के पास कोई कमिटमेंट वाली अपनी विचाराधारा नहीं है। केजरीवाल विचारधारा से परे की राजनीति करते हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि ये विचार-शून्यता की राजनीति है। ऐसे में मुसलमानों की लिंचिंग, दिल्ली दंगों और मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी थी, जिसके आम आदमी पार्टी के धर्मनिरपेक्ष छवि को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। केजरीवाल खुद को हनुमान भक्त बताते हैं तो मंदिर-मंदिर माथा टेकते नजर आते हैं।

## ये भी कतार में

**के चंद्रशेखर राव**- टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी दावेदारों में शामिल हैं। केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। वह अब तेलंगाना से इतर जहां भी जाते हैं हिंदी में ही भाषण देते हैं। उनकी आक्रामक भाषण शैली लोगों को पसंद आती है। राव ने तेलंगाना के विकास कार्यों का प्रचार-प्रसार भी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दिया है।

**अखिलेश यादव**- समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार बताते हैं। हालांकि, जमीनी हकीकत देखी जाए तो अखिलेश अभी उप्र में ही अपने पांव मजबूत करने में जुटे हैं। हां, ये जरूर है कि उनका समर्थन जिसे मिलेगा उसकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी।

● **विपिन कंधारी**

# सदन की घटती प्रासंगिकता

*देश का सर्वोच्च सदन लोकसभा हो या राज्यों की विधानसभा उनकी प्रासंगिकता दिन पर दिन घटती जा रही है। स्थिति यह है कि अब तो नियत समय तक कोई भी सदन नहीं चल रहा है। सदन में चर्चा करने की बजाय सत्तापक्ष और विपक्ष सत्र के दौरान हर मुद्दे पर हंगामा करने को तैयार रहता है, जिससे जनता से लिए गए टैक्स से चल रहे सदन की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाती है। आलम यह है कि वर्तमान समय में देश में कोई भी बिल बिना चर्चा के हंगामे के लिए पारित किए जा रहे हैं। उससे न तो सत्तापक्ष और न ही विपक्ष को कोई मतलब है।*

संसद का जो मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलना था, वह चार दिन पहले ही समाप्त हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी संसद के कई सत्रों का समय से पहले समापन हुआ है। आमतौर पर जब भी ऐसा हुआ, तो यही कहा गया कि आवश्यक विधायी कामकाज पूरे हो गए थे, लेकिन सच यह है कि संसद को सही तरह चलाना कठिन हो गया था। मानसून सत्र में भी यही हुआ। भले ही आधिकारिक रूप से यह कहा गया हो कि चार दिन पहले सत्र का समापन आने वाले त्योहारों के कारण किया जा रहा है, लेकिन सच यही है कि इस सत्र को इसलिए समय से पूर्व समाप्त करना पड़ा, क्योंकि हंगामे और हल्ले का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। नि:संदेह सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती थी कि 8 अगस्त के बाद कुछ त्योहार होंगे?

मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में पहले दो हफ्ते तो कोई विशेष काम ही नहीं हुआ, क्योंकि पक्ष-विपक्ष में इस पर सहमति नहीं बन पाई कि महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे अन्य विषयों पर कब एवं कैसे बहस हो? अंतत: दो सप्ताह बाद महंगाई पर बहस हुई, लेकिन जो कांग्रेस इस मसले पर चर्चा को लेकर सबसे अधिक बल दे रही थी, उसके सांसद उस समय सदन से बाहर निकल गए, जब वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अपना जवाब देने के लिए खड़ी हुईं। स्पष्ट है कि कांग्रेस की रुचि इसमें थी ही नहीं कि संसद में महंगाई और दूसरे अन्य विषयों पर कोई सार्थक चर्चा हो। कुछ ऐसी ही भाव-भंगिमा से अन्य विपक्षी दल भी लैस थे। सत्तापक्ष भी ऐसी कोई पहल करते हुए नहीं दिखा कि पहले उन विषयों पर चर्चा हो जाए, जिन पर विपक्षी दल जोर दे रहे हैं। संभवत: इसका कारण यह आशंका रही हो कि ऐसा होने पर भी विपक्ष संसद नहीं चलने देगा। जो भी हो, तथ्य यही है कि संसदीय कामकाज की दृष्टि से संसद का यह सत्र सबसे खराब रहा। इस सत्र में लोकसभा से केवल छह विधेयक पास हुए और राज्यसभा से मात्र पांच।

संसद और विधानसभाओं के संचालन के मामले में इस उक्ति का खूब प्रयोग होता है कि

## नए भवन में हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र

नए संसद भवन के शेष काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि संसद का आगामी शीतकालीन सत्र वहां आयोजित किया जा सके। एक अधिकारी ने बताया कि नए भवन में मिर्जापुर के हाथ से बुने गद्दीदार कालीन, मप्र और राजस्थान के पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र से टीकवुड फर्नीचर आ गया है। अंदरूनी सज्जा और फर्श पर काम शुरू हो गया है। पिछले सप्ताह सरकार ने लोकसभा को बताया था कि नए संसद भवन की परियोजना की भौतिक प्रगति का 70 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है और इसके पूरा होने की लक्षित तिथि नवंबर 2022 है। सूत्रों ने कहा कि इस परियोजना के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए समय सीमा बढ़ाने की अभी कोई योजना नहीं है। अधिकारियों ने बताया, हम संसद के नए भवन में शीतकालीन सत्र सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि नए संसद भवन के कुछ हिस्से 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के आसपास कार्यात्मक हो सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि संसद का शीतकालीन सत्र नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बन रहे नए भवन में होगा।

सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्तापक्ष की होती है। यह सही तो है, लेकिन एक हद तक ही। यदि विपक्षी दल यह ठान लें कि सदन नहीं चलने देना है तो फिर सत्तापक्ष की तमाम सकारात्मकता के बाद भी वह नहीं चल सकता। समस्या यह है कि अब विपक्षी दल अक्सर पहले ही तय कर लेते हैं कि सदन नहीं चलने देना है। संसद और विधानसभाओं के सत्र के पहले जो सर्वदलीय बैठकें बुलाई जाती हैं, वे न केवल निरर्थक साबित होती हैं, बल्कि समय और संसाधन की बर्बादी का कारण भी बनती हैं। आमतौर पर इन बैठकों में जहां सत्तापक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि वह सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्षी दलों की ओर से यह वादा किया जाता है कि वे रचनात्मक सहयोग देंगे।

सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। करीब-करीब हर बार संसद और विधानसभाओं के सत्र की शुरुआत विपक्षी नेताओं की नारेबाजी के साथ होती है। वे बैनर और तख्तियां लेकर सदन में पहुंचते हैं और वहां इसके लिए हरसंभव कोशिश करते हैं कि वे टीवी के कैमरों में कैद हो जाएं। सदन में नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने के लिए बाकायदा तैयारी भी होती है। नेतागण सदन में किस विषय पर क्या कहना है, इसकी तैयारी करने के बजाय इसके लिए परिश्रम करते हैं कि तख्तियों पर क्या नारे लिखे जाएं? जब सदस्य सदन में अपने असंसदीय-अभद्र आचरण के लिए निलंबित किए जाते हैं तो वे इसे भी एक मुद्दा बना लेते हैं और देश-प्रदेश में तानाशाही लागू हो जाने की घोषणा करने के साथ यह भी कहने लगते हैं कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है।

संसद के मानसून सत्र में लोकसभा के चार सदस्य निलंबित किए गए। इसके बाद राज्यसभा के एक के बाद एक कई सदस्य निलंबित किए गए। एक विपक्षी सांसद इससे खिन्न हो गए कि हंगामा खड़ा करने के बाद भी उन्हें क्यों नहीं निलंबित किया गया तो अगले दिन उन्होंने और ज्यादा हंगामा किया। आखिरकार वह निलंबित हो गए। वास्तव में वह यही चाहते थे। जब यह स्थिति हो, तब इस पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि संसद और विधानसभाओं की प्रतिष्ठा और महत्ता लगातार कम क्यों होती जा रही है? सच तो यह है कि विधानसभाओं की स्थिति और भी दयनीय है। विधानसभाओं के चलने के दिन लगातार कम होते जा रहे हैं। कई बार तो विधानसभाओं के सत्र दो-तीन दिन और यहां तक कि एक दिन के लिए भी बुलाए जाने लगे हैं। जब ऐसा होता है तो उस दौर की राशन की वे दुकानें याद आने लगती हैं, जो एकाध दिन के लिए ही खुलती थीं और फिर हड़बड़ी, अव्यवस्था और आपाधापी के बीच राशन बांटकर बंद हो जाती थीं। विधानसभाओं के सत्र एक-दो दिन के लिए बुलाकर जैसे-तैसे आवश्यक विधेयकों को पारित करा लिया जाता है और फिर यह कह दिया जाता है कि विधायी एजेंडा पूरा हो गया।

ऐसे भी अवसर आए हैं, जब विधानसभाओं के सत्र केवल इसलिए बुलाए गए, ताकि विपक्षी दलों अथवा केंद्र सरकार को खरी-खोटी सुनाई जा सके या फिर ऐसा कुछ कहा जा सके, जिसे सदन के बाहर कहना मुश्किल हो। ज्ञात हो कि संसद या विधानसभा के अंदर कही गई किसी बात के लिए संबंधित जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। यह एक विशेषाधिकार है और यह बना रहना चाहिए, लेकिन यह ठीक नहीं कि इसका इस्तेमाल जनता को बरगलाने-उकसाने के लिए हो। एक लंबे समय से संसद और विधानसभाओं की गरिमा में गिरावट को लेकर चिंता जताई जा रही है, लेकिन वैसे उपाय कहीं भी नहीं हो रहे कि उनकी प्रासंगिकता और महत्ता बढ़ सके।

देश में संसद सबसे बड़ी पंचायत है। उसके निर्णय पूरे देश पर बाध्यकारी हैं। वह लोकतंत्र की धुरी है, जो कार्यपालिका अर्थात् प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को जन्म देती है। कार्यपालिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। संविधान ने संसदीय व्यवस्था में संसद को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। संघीय व्यवस्था के चलते यही बात राज्यों में विधानसभाओं पर भी लागू होती है, लेकिन आज संसद और विधानसभाओं के मूल चरित्र में नकारात्मक बदलाव देखे जा रहे हैं। इससे उनकी प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह लगने लगा है।

ये संस्थाएं शोर-शराबे, तर्कहीन वाद-विवादों, आरोप-प्रत्यारोप और धरने-प्रदर्शन का मंच बनती जा रही हैं। कभी-कभी वहां हिंसा के भी दर्शन होने लगे हैं। विरोध, धरना, प्रदर्शन के लिए तो हर शहर में स्थान चिन्हित हैं। आखिर सांसद संसद में जाकर अपने विरोध को विचारों में क्यों नहीं व्यक्त करते? संसद और विधानसभाओं के अंदर और बाहर बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर सांसद और विधायक अपना विरोध दर्ज क्यों करा रहे हैं? क्या उन्हें बोलना नहीं आता या उनके पास विरोध का कारण नहीं होता? अक्सर विदेशी शिष्टमंडल **संसद की दीर्घाओं** में बैठकर हमारे लोकतंत्र को समझने आते हैं। क्या छवि लेकर जाते होंगे वे? संसद की कार्यवाही का सजीव प्रसारण होने से जनता सांसदों के विचार, भाषा और व्यवहार को देखकर हतप्रभ और आहत होती है। राजनीतिक संस्कृति में गिरावट इसका बड़ा कारण है। यह गांधीवादी संस्कृति पर नेहरूवादी संस्कृति के वर्चस्व का परिणाम है। इसी के चलते राजनीति में अहिंसा पर हिंसा भारी पड़ गई और देश में राजनीति पर अपराधियों की पकड़ बढ़ती गई, जिससे ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक आम आदमी हाशिये पर आ गया।

● **इन्द्र कुमार**

## संविधान संशोधन भी जिम्मेदार

संसद और विधानसभाओं की गिरती साख के पीछे केवल राजनीतिक संस्कृति की गिरावट ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका के निर्णय और संविधान के संशोधन भी जिम्मेदार हैं। जबसे सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1973) में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया तबसे संसद और विधानसभाओं के बनाए कानूनों पर न्यायपालिका की अदृश्य तलवार लटकती रहती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं बताया कि मूल ढांचा अंतिम रूप से है क्या? संविधान के 52वें संशोधन अर्थात् दलबदल निरोधक कानून, 1985 ने जनप्रतिनिधियों को अपनी-अपनी पार्टी का बंधक सा बना दिया है। इतना ही नहीं, दलबदल पर संसद और विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अधिकार की पुनर्स्थापना कर उन पर न्यायपालिका के प्रभुत्व की स्थापना कर दी है। स्वयं कार्यपालिका ने भी व्यवस्थापिका पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है।

# योगी से नाराजगी!

## क्या 2024 में भारी नहीं पड़ेगी योगी की नाराजगी

उप्र विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में लोगों से मोदी के नाम पर ही वोट मांगा करते थे। अमित शाह लोगों से कहते कि वे 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री जरूर बनाएं। लोगों ने अमित शाह की बात मानी और योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। क्या योगी आदित्यनाथ की भूमिका अब खत्म हो गई? क्या भाजपा नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ के मन से सहयोग के बगैर ही 2024 में उप्र की 80 सीटों में से ज्यादातर पर जीत मिल जाएगी? भाजपा नेतृत्व के ताजा रुख से तो योगी आदित्यनाथ को भी लग रहा होगा कि 2024 के आम चुनाव में उम्मीदवारों के टिकट तय करते वक्त भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार हो सकता है। अगर ऐसा ही वास्तव में हुआ तो क्या नेतृत्व ने नतीजों की कल्पना की है?

योगी आदित्यनाथ उप्र के दो बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन दिल्ली का भरोसा अब तक नहीं जीत पाए। भाजपा संसदीय बोर्ड में योगी आदित्यनाथ को एंट्री न दिया जाना और उसके पीछे सामने आ रही दलील तो यही कहती है। योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड में शामिल न किए जाने को लेकर तर्क दिया जा रहा है कि इस बार बोर्ड में किसी भी मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी गई है। 13 दिन वाली वाजपेयी सरकार को छोड़ दें तो 1998 में जब एनडीए की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ अभी लोकसभा पहुंचे ही थे, लेकिन 2014 में जब भाजपा की अगुवाई में दूसरी बार एनडीए की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ लगातार पांचवीं बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके थे। तब भी योगी आदित्यनाथ को कैबिनेट के लायक नहीं समझा गया। वाजपेयी सरकार के दौरान तो बहुत सारे सीनियर भाजपा नेता थे, लेकिन मोदी सरकार आते-आते तो योगी आदित्यनाथ जैसे लगातार पांच बार संसद पहुंचने वाले कम ही सांसद रहे होंगे।

यहां तक कि तीन साल बाद भी जब 2017 में उप्र में भाजपा सरकार बनाने जा रही थी, तब भी नेतृत्व के दिमाग में योगी आदित्यनाथ का कहीं नामोनिशान रहा हो, ऐसा तो बिलकुल नहीं लगा। फिर भी योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ही ली और डंके की चोट पर, अपनी शर्तों पर, मनमानी करते हुए सत्ता में वापसी करने में भी सफल रहे। और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा ही हुआ है, भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल न किया जाना, लगता तो ऐसा ही है। शिवराज सिंह चौहान का अपना पक्ष तो कमजोर हो ही चुका है, संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के पीछे बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ ही लगते हैं।

अगर शिवराज सिंह चौहान को भाजपा संसदीय बोर्ड से नहीं हटाया जाता और योगी आदित्यनाथ को शामिल नहीं किया जाता तो स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़ा हो जाता। क्या ऐसा नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ को रोकने के लिए किसी की भी कुर्बानी दी जा सकती है? ये तो ऐसा लगता है जैसे योगी आदित्यनाथ और भाजपा न तो अब तक एक-दूसरे को स्वीकार कर पाए हैं, न ही नजदीकी भविष्य में ऐसा करते प्रतीत हो रहे हैं। अब तक भाजपा और योगी आदित्यनाथ एक गठबंधन सहयोगी की तरह एक दूसरे का साथ निभाते आ रहे हैं। तकनीकी तौर पर या कागजी तौर पर, जैसे भी समझा जाए योगी आदित्यनाथ भाजपा के नेता तो हैं, लेकिन हर वक्त टकराव की स्थिति बनी रहती है।

वैसे भी भाजपा शासित राज्यों में ऐसा कोई मुख्यमंत्री तो है नहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की बात को नजरअंदाज कर सके। उप्र विधानसभा चुनाव से पहले तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ही किया था। मोदी के भरोसेमंद नौकरशाह अरविंद शर्मा को मंत्री बनाने से इनकार करके। हो सकता है, 2014 में मोदी कैबिनेट में शामिल न किए जाने के बदले के रूप में वो अपने कलेजे को शांत करने की कोशिश कर रहे हों। योगी आदित्यनाथ जानते थे कि मोदी-शाह ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि उप्र जैसा राज्य भाजपा के हाथ से निकल जाए। 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी-शाह हर हाल में भाजपा की सत्ता में वापसी के लिए जी जान लगाएंगे ही, योगी आदित्यनाथ कमजोर नस पकड़ चुके थे और हुआ भी वैसा ही। वो अपनी शर्तों पर कायम रहे, लेकिन जैसे ही नेतृत्व को मौका मिला योगी आदित्यनाथ की राह में रोड़ा खड़ा कर दिया।

योगी आदित्यनाथ से मोदी-शाह की नाराजगी की ताजा वजह तो सुनील बंसल का उप्र से हटाया जाना ही लगती है। ये तो सबको मालूम था कि सुनील बंसल को योगी आदित्यनाथ ने कभी पसंद नहीं किया और दोनों के रिश्ते इसी वजह से हमेशा ही खराब रहे। सुनील बंसल को हाल ही में पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। ये दोनों ही भाजपा की दिलचस्पी के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण राज्य हैं। तेलंगाना में जहां 2023 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 2024 में ज्यादा नहीं तो कम से कम 2019 जितनी सीटें जीतना तो भाजपा नेतृत्व को सुनिश्चित करना ही है। सुनील बंसल के कंधों पर एक बार फिर ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।

सुनील बंसल उप्र के प्रभारी रहे और समझा जाता है कि राजनीतिक मामलों में तो वो योगी आदित्यनाथ के समानांतर पावर सेंटर बने रहे। भाजपा के सभी विधायक नियमित तौर पर सुनील बंसल के संपर्क में रहा करते थे। और सबसे बड़ी बात दिल्ली और लखनऊ के बीच भी वो सूत्रधार थे। ऐसा समझा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की वजह से ही सुनील बंसल को उप्र से शिफ्ट करना पड़ा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ का रिश्ता भी जगजाहिर ही है, फिर भी सुनील बंसल को लेकर केशव मौर्य ने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उप्र के उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल की तारीफ में जो कुछ कहा है, वो ध्यान से सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा- उप्र में भाजपा को शून्य से शिखर तक ले जाने का श्रेय भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को जाता है... अध्यक्ष तो मैं भी रहा हूं... मेरे समय हुए चुनाव में जीत का मुकुट भले सिर बंधा हो... मगर उस जीत का कोई सही अधिकारी है, तो वो सुनील बंसल ही हैं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

# कांटे भी बिछ गए हैं राह में!

भाजपा ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कमेटियों में से एक चुनाव समिति में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बतौर सदस्य शामिल किया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यही है कि संभव है कि देवेंद्र फडणवीस को देर-सबेर केंद्र में लाने और महाराष्ट्र में एक नए और बड़े पावर सेंटर के तौर पर तैयार किया जा रहा हो। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को जिस चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है, वहां उनके लिए सब कुछ बहुत आसान नहीं है। क्योंकि यह समिति टिकटों के फैसले लेने वाली भाजपा की सबसे बड़ी कमेटी है। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा के चुनावों में टिकटों के हुए बंटवारे में बड़े-बड़े नेताओं के टिकट कटने से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नाराजगी भी हुई थी।

भाजपा की दो सबसे महत्वपूर्ण कमेटियों में सदस्यों की घोषणा के साथ ही अलग-अलग तरह के राजनीतिक कयासों की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि देवेंद्र फडणवीस को महत्वपूर्ण कमेटी में शामिल करने से भाजपा ने एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि अब महाराष्ट्र में एक और नया बड़ा पावर सेंटर तैयार किया जा रहा है। यह तब और ज्यादा पुख्ता हो जाता है जब केंद्र में महाराष्ट्र से ही मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को पार्टी अपने सबसे महत्वपूर्ण कमेटी से बाहर कर देती है। महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू से चर्चा रही है कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही महाराष्ट्र में भाजपा का दूसरा पावर सेंटर बनने लगा था। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कई राजनीतिक गलतियों के चलते न सिर्फ उनके विरोधियों को मौका मिला, बल्कि उन्हें इसी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में किनारे भी किया जाने लगा। हालांकि अब जब फडणवीस को चुनाव समिति में शामिल किया गया है, तब भी राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में देवेंद्र फडणवीस के लिए यहां पर भी चुनौतियां बहुत आने वाली हैं।

महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले राजनीतिक विश्लेषक अभिमन्यु शितोले कहते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से पिछले चुनाव में कई बड़े नेताओं के टिकट काटे थे, उस समय देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ पार्टी के लोगों में नाराजगी थी। महाराष्ट्र के नेताओं का कहना था कि देवेंद्र फडणवीस के चलते ही बड़े नेताओं के टिकट कटे हैं। लेकिन तब देवेंद्र फडणवीस ने ऐसे आरोपों पर केंद्रीय चुनाव समिति के पाले में गेंद डाल दी थी। शितोले कहते हैं क्योंकि अब खुद देवेंद्र फडणवीस चुनाव समिति के सदस्य हैं ऐसे में आने वाले चुनावों में मिलने वाले टिकट में लोगों की नाराजगी या लोगों की पसंद को सीधे देवेंद्र फडणवीस से जोड़कर ही देखा जाएगा। ऐसे में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि देवेंद्र फडणवीस को इस कमेटी में शामिल कर एक संदेश तो जरूर दिया गया है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन कांटों भरी राह भी इस समिति के सदस्य होने के चलते उनके सामने बिछ गई है।

भाजपा के एक नेता कहते हैं कि बीते चुनावों में भाजपा के दो बड़े नेता विनोद तावड़े और चंद्रशेखर बावनकुले को टिकट नहीं मिला था। दोनों नेता महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा के लिए बड़े चेहरे रहे हैं। इन दोनों नेताओं को टिकट न मिलने का सारा ठीकरा देवेंद्र फडणवीस के ऊपर फोड़ा गया था। हालांकि बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर देवेंद्र फडणवीस को संदेश भी दिया था। पार्टी के उक्त नेता का कहना है कि पार्टी मराठों और ओबीसी को भी महाराष्ट्र में नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए दोनों नेताओं का बेहतर तरीके से न फिर समायोजन किया, बल्कि उनको सम्मानजनक स्थान भी दिलाया। चर्चा उस वक्त यही थी कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दोनों खास नेताओं को देवेंद्र फडणवीस ने किनारे कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उसी वक्त से यह खुलकर सामने आने लगा था कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के बीच में सब कुछ उतना सामान्य नहीं है जितना दिखता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दिनों में चुनावों के दौरान मिलने वाले टिकटों से देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतियां भी होंगी। राजनीतिक विश्लेषक सोमेश पाटिल कहते हैं कि इस बार टिकट कटने पर देवेंद्र फडणवीस यह कहकर नहीं बच सकेंगे की टिकटों का फैसला केंद्र की चुनाव समिति में किया है, क्योंकि वह खुद इस कमेटी का हिस्सा हैं इसलिए नाराजगी और बेहतर सामंजस्य सब उनके हिस्से में आएगा। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस का इस कमेटी के सदस्य होने के नाते कहा जा रहा है उनके लिए महाराष्ट्र के नेताओं में परशेप्शन भी बनेगा। अब यह परसेप्शन फडणवीस के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस दौरान राष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस की ताकत को न सिर्फ कम किया गया बल्कि उन्हें उपमुख्यमंत्री भी बनाया गया। राजनीतिक विश्लेषक संजय वाड़वालकर कहते हैं कि क्योंकि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के वोट बैंक की भी बड़ी संख्या है। इसलिए जातिगत समीकरणों को साधते हुए पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस को केंद्र की एक महत्वपूर्ण समिति में जगह देकर संदेश तो दिया ही है। वाड़वालकर कहते हैं कि चूंकि सबको बैलेंस करते हुए चलना भाजपा की रणनीति का हिस्सा है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को तमाम उतार-चढ़ाव के बीच केंद्र की महत्वपूर्ण समिति का हिस्सा बनाया गया है।

● **बिन्दु माथुर**

## देवेंद्र को प्रमोशन, नितिन को डिमोशन

संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भाजपा ने केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया है। इस फैसले को महाराष्ट्र और केंद्र में बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ अनुभवी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाना उनके डिमोशन के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, देवेंद्र फडणवीस का चुनाव समिति में आना पदोन्नति या उनके बढ़ते कद के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस को बढ़ावा दिया है, जो गोवा और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लेकिन, अब केंद्रीय चुनाव समिति में जगह देकर साफ कर दिया गया है कि फडणवीस का दायरा अब महाराष्ट्र से बाहर है और भाजपा में भी उनका राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ा है। इतना ही नहीं, फडणवीस को आज महाराष्ट्र विधान परिषद का नेता भी घोषित किया गया है। वहीं, नितिन गडकरी के साथ ऐसा नहीं है और वह अब केवल केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री भर बनकर रह गए हैं। वह भाजपा में कोई पद नहीं रखते हैं और न ही किसी राज्य के प्रभारी हैं। साफ है कि नितिन गडकरी का राजनीतिक दबदबा पहले जैसा नहीं रहा।

# नीतीश के मुकाबले अभी से तेजस्वी को बेहतर

तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बताने वाले सर्वे ने पिछली बार उनको मिले शादी के हजारों प्रस्तावों की याद दिला दी है। फिर से बिहार के उपमुख्यमंत्री बन चुके तेजस्वी यादव को एक सर्वे में लोगों ने नीतीश कुमार के मुकाबले अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री बताया है। तेजस्वी यादव की अब शादी हो चुकी है और शादी होने के सालभर के भीतर ही वो फिर से खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर चुके हैं, जिसके लिए उनकी पत्नी राजश्री को लकी चार्म बताया जाने लगा है। तेजस्वी यादव ने दिसंबर, 2021 में शादी रचाई थी।

महागठबंधन की पिछली सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव ने टूटी सड़कों की तस्वीर शेयर करने के लिए एक व्हाट्सऐप नबंर शेयर किया था, ताकि ऐसी सड़कों की सरकार मरम्मत करा सके। लोगों ने सड़कों में बने गड्ढ़ों की तस्वीरें तो तेजस्वी यादव को भेजे ही, हजारों की संख्या में उनको शादी के प्रस्ताव भी मिले थे। हालांकि, तब उनकी ये लोकप्रियता मोस्ट एलिजिबल बैचलर कैटेगरी में दर्ज हुई थी। तभी बताया गया था कि तेजस्वी यादव की तरफ से शेयर किए गए व्हाट्सऐप नंबर पर 47,000 संदेश मिले थे, लेकिन 44,000 तो तेजस्वी यादव से शादी के प्रस्ताव रहे।

लेकिन करीब डेढ़ साल के कार्यकाल के बाद ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और नीतीश कुमार चाहते थे कि वो इस्तीफा दे दें। जब तेजस्वी यादव ने ऐसा नहीं किया तो वो मुख्यमंत्री पद से खुद ही इस्तीफा दे दिए। मुख्यमंत्री के इस्तीफे को पूरी कैबिनेट का इस्तीफा मान लिया जाता है, तेजस्वी यादव की कुर्सी अपने-आप चली गई। एक बार फिर बिहार की राजनीति में ऐसी उलटफेर हुई कि तेजस्वी यादव को फिर से उपमुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। वो तो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते थे, लेकिन मौजूदा हालत में ये संभव नहीं हो सका। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी थे। अब एक सर्वे से मालूम हुआ है कि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही ज्यादातर लोग मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार पर तरजीह देते नजर आ रहे हैं। बिहार की घोर जातीय राजनीति में तेजस्वी यादव आखिर मुख्यमंत्री की पहली पसंद कैसे बन गए हैं? बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बीच ही सर्वे एजेंसी सी-वोटर ने एक ओपिनियन पोल कराया है। सर्वे के मुताबिक पोल में शामिल बिहार के 43 फीसदी लोगों को लगता है कि तेजस्वी यादव बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं। नीतीश कुमार को सर्वे में शामिल महज 24 फीसदी लोग ही बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं, जबकि उनके सामने विकल्प के तौर पर तेजस्वी यादव और भाजपा की तरफ से कोई नेता पेश किया गया है। भाजपा के किसी नेता को सिर्फ 19 फीसदी लोगों ने ही मुख्यमंत्री की पसंद बताया है। इसकी एक वजह अब तक भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री लायक कोई चेहरा पेश नहीं किया जाना ही लगता है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद भाजपा नेतृत्व ने सुशील मोदी को राज्यसभा भेज दिया था और नीतीश कुमार के साथ अपने दो उपमुख्यमंत्री लगा दिए थे, लेकिन न तो तब उनकी कोई खास पहचान रही, न ही कार्यकाल के दौरान वे कोई करिश्मा दिखा सके। भाजपा ने वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे सैय्यद शाहनवाज हुसैन को भी नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल कराया था और वो अपने कामकाज को लेकर चर्चित भी रहे।

2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव जिस महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे उसमें आरजेडी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल थीं। लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन कांग्रेस से अच्छा भी रहा, जिसके लिए तब आरजेडी नेताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को टारगेट भी किया था। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के ही मुस्लिम-यादव फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़े थे और चुनावों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी थी। तब भाजपा दूसरे और जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। संयोग से तमाम उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर वही स्थिति हो चुकी है और सभी की सीटें बढ़ चुकी हैं। तेजस्वी यादव की राजनीति से जुड़े एम-वाय फैक्टर को देखते हुए सर्वे में भी दोनों वर्गों की राय ली गई। ओबीसी कैटेगरी के लोगों में 44.6 फीसदी ने तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के मुकाबले अपनी पहली पसंद बताया, जबकि इस मामले में भी 18.4 फीसदी लोगों की पसंद के साथ तीसरे स्थान पर रही। नीतीश कुमार को ओबीसी वर्ग के 24.7 फीसदी लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद बताया और ध्यान देने वाली बात है कि मुस्लिम समुदाय की राय भी ओबीसी तबके के करीब ही लगती है।

● **विनोद बक्सरी**

## आधी आबादी का पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन?

2015 में ही नहीं, 2020 में भी नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी में महिला वोटर की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई थी, लेकिन हैरानी की बात ये है कि नीतीश कुमार अब महिलाओं की पहली पसंद नहीं रह गए हैं। सर्वे में शामिल महिलाएं तो ऐसा ही मानती हैं। ऐसा भी नहीं कि महिलाओं की ही ये राय है, पुरुषों की राय भी मिलती जुलती ही है। बिहार के 41.8 फीसदी पुरुष मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव को ही पहली पसंद बता रहे हैं और 44 फीसदी महिलाओं ने भी तेजस्वी यादव को ही अपनी पहली पसंद बताया है। नीतीश कुमार को सिर्फ 23.3 फीसदी महिलाएं और करीब-करीब उतने ही 23.8 फीसदी पुरुष अब भी मुख्यमंत्री की पहली पसंद बता रहे हैं। रही बात भाजपा के मुख्यमंत्री की तो 19.6 फीसदी पुरुष और 17.5 फीसदी महिलाएं पक्ष में जरूर हैं। नीतीश कुमार को महिलाओं के वोट जिन वजहों से मिले थे, एक बड़ी वजह शराबबंदी रही, लेकिन धीरे-धीरे ये धारणा बनती जा रही है कि नीतीश की शराबबंदी फेल हो चुकी है। इसका असली कारण तो जहरीली शराब से होने वाली मौतें हैं। साथ ही कुछ अन्य विवाद भी हैं, जैसे शिक्षकों को शराबबंदी लागू करने की ड्यूटी में लगाना। हालांकि, विधानसभा में सवाल उठने पर तत्कालीन मंत्री ने ऐसी चीजों को खारिज कर दिया था।

# चीन की अकड़ ढीली करने का समय

अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर चीन ने पूर्वी एशिया में जिस तरह सैन्य तनाव को जन्म दे दिया है, वह यही दर्शाता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी बहाने की तलाश थी। वैसे तो चीन का सरकारी मीडिया पहले से ही धमकी दे रहा था कि अगर नैंसी ने ताइवान आने का प्रयास किया, तो वह उनके विमान को निशाना बनाएगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति को फोन पर आग से न खेलने की चेतावनी भी दी थी, पर नैंसी अमेरिकी और ताइवानी वायुसेना के सुरक्षा घेरे में ताइपे पहुंचीं। इस दौरान चीनी सेना ने न तो कोई मिसाइल दागी और न नैंसी के हवाई काफिले के पास भटकने की कोशिश की।

नैंसी के ताइपे जाने के पहले चीनी सेना ने ताइवान के चारों ओर सैन्य अभ्यास की घोषणा भी की, पर उसके आरंभ होने से पहले ही नैंसी अपना दौरा पूरा कर चुकी थीं। इसके बाद चीनी सेना ने कई मिसाइलें इस प्रकार दागीं कि वे ताइवान की वायु सीमा से होकर जापान के इकोनामिक जोन में जाकर गिरीं। ध्यान रहे कि ताइवान पर दावा करने के साथ ही चीन जापान के भी कई द्वीपों को अपना बताता है।

नैंसी पेलोसी ने चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान जाकर चीनी दादागीरी की सीमाएं स्पष्ट करने के साथ यह भी सिद्ध किया कि शी जिनपिंग की ओर से खुद को दूसरे माओ त्से तुंग के रूप में स्थापित करने का प्रयास इतना आसान नहीं। यदि अमेरिका चीनी धमकियों के चलते नैंसी का दौरा रद्द करता तो चीन कल को ऐसी ही धमकियां भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों के दौरे को लेकर दे सकता था। नैंसी के दौरे के बाद चीन जिस प्रकार ताइवान स्ट्रेट और दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ा रहा है, उसमें कुछ भी नया नहीं है।

चीन की दादागीरी के चलते ताइवान इसी तरह के संकट का सामना 1954-55, 1958, 1995-96 में भी कर चुका है। 1954-55 और 1958 में तो चीनी सेना ने ताइवान के कई द्वीपों पर कब्जा करने की असफल कोशिश भी की थी। दूसरे संकट के समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने ताइपे का दौरा किया था तो चीनी सेना ने ताइवान के किनमेन द्वीप पर एक लाख से अधिक गोले बरसाए थे। तब ताइवान के साथ हवाई झड़पों में चीनी वायुसेना को 51 लड़ाकू विमान गंवाने पड़े थे। पहले के दोनों ही संकटों के दौरान अमेरिकी सेना ने चीन के विरुद्ध परमाणु हथियारों के प्रयोग की सिफारिश तक कर दी थी। इसके चलते माओ को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। 1995-96 के दौरान ताइवान को लेकर चीन ने इसी तरह का हंगामा इसलिए खड़ा किया था, क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति को एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए वीजा दे दिया गया था। तब भी चीन ने मिसाइलें दाग कर खूब सैन्य तनाव बढ़ाया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने अपने सातवें नौसैनिक बेड़े को ताइवान स्ट्रेट में भेज दिया था। बाद में पता चला कि चीन द्वारा दागी गईं मिसाइलें बिना किसी विस्फोटक के थीं। इस बार भी इसी सबकी पुनरावृत्ति होती दिखाई दे रही है।

ताइवान चीन के उस भौगोलिक अभिशाप का हिस्सा है, जो उसे एक नौसैनिक शक्ति के रूप में पैर नहीं फैलाने देता। तमाम भौगोलिक विस्तार के बावजूद चीन के पूर्व में ही समुद्र है और तट से कुछ दूरी पर ही ताइवान है, जिसे अमेरिका स्थायी विमान वाहक पोत की तरह उपयोग कर रहा है। ताइवान के आगे जापान है, जहां अमेरिकी सेना तैनात है और जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के सदमे से उबर रहा है। चीन की आक्रामक नीतियों के चलते जापान में राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय हो रहा है, जो देश के शस्त्रीकरण के पक्ष में है। यह भारत के हित में ही है, क्योंकि चीन कितनी भी बड़ी नौसेना बनाए, वह इस चक्रव्यूह में फंसी रहेगी। अभी तक चीन का दागा हुआ एक गोला भी ताइवान की भूमि पर नहीं गिरा है, लेकिन अमेरिका ने इस समुद्री क्षेत्र में व्यापक नौसैनिक शक्ति के प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। ऐसे में खतरा यह है कि शी जिनपिंग या तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ताइवान के कुछ छोटे द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे या फिर भारतीय मोर्चे पर ध्यान लगाएंगे। ध्यान रहे कि जून से ही चीनी लड़ाकू विमान लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बहुत पास उड़ान भर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत को इस क्षेत्र में एस-400 मिसाइल प्रणाली की दूसरी बटालियन को भी तैनात करना पड़ रहा है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

## भारतीय मोर्चे पर किसी चीनी शरारत की आशंका!

ताइवान के खिलाफ कुछ न कर पाने की स्थिति में भारतीय मोर्चे पर किसी चीनी शरारत की आशंका को इसलिए नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि चीन के लोग इंटरनेट मीडिया पर अपनी सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। इस सबके बीच नई दिल्ली में चीनी दूतावास अति सक्रिय है। वह ताइवान को लेकर बयान पर बयान जारी कर रहा है और भारत को याद दिला रहा है कि किस तरह वह शुरू से ही 'वन चाइना' नीति के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि 'वन चाइना' नीति का अर्थ चीन में एकदलीय कम्युनिस्ट व्यवस्था का समर्थन नहीं है। एक समय ताइवान के लोग चीन का ही हिस्सा थे। उन्हें माओ ने बंदूक के दम पर देश से निकाला था, क्योंकि वे लोकतंत्र में यकीन करते थे। दूसरी अहम बात यह है कि जब नेहरू सरकार ने 'वन चाइना' नीति का समर्थन किया था, तब से लेकर आज तक भारत के तमाम भूभाग पर चीनी दावे और कब्जे बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही दक्षिण चीन सागर के देशों और जापान के साथ भी हो रहा है। क्या चीन जिस-जिस क्षेत्र पर दावा जताता रहेगा, उसे 'वन चाइना' नीति के तहत उसका हिस्सा मान लिया जाएगा? प्रश्न यह भी है कि क्या चीन ने 'वन इंडिया' की नीति में विश्वास जताया है? वह कश्मीर के मामले में न केवल पाकिस्तान के साथ है, बल्कि उसका एक हिस्सा उससे हासिल कर चुका है। दोनों भारतीय जमीन पर आर्थिक गलियारा भी बना रहे हैं। भारत यह भी नहीं भूल सकता कि पाकिस्तान के कई आतंकी सरगनाओं पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने में चीन किस तरह रोड़े अटकाता रहा है। ऐसे में इसका कोई औचित्य नहीं कि भारत 'वन चाइना' नीति को लेकर प्रतिबद्धता जताए।

# टूट रहा है अल-कायदा

आज से 11 साल पहले ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सील कमांडो के हाथों मारे जाने के बाद अब अल-कायदा में उसके उत्तराधिकारी आयमान अल जवाहिरी का भी अमेरिका ने काबुल में खात्मा कर दिया। यह माना जाता है कि लादेन के समय अल-कायदा जितना मजबूत था, उतना जवाहिरी के समय नहीं रहा। वो कुछ देशों में गुटों में भी बंटा है। सैफ-अल-अदेल अल-कायदा का नया सरगना हो सकता है, जो कभी लादेन का सुरक्षा प्रमुख रहा है। लेकिन अमेरिका को अल-कायदा के इन दो दुर्दांत आतंकियों को खत्म करने में 20 साल लग गए। अल-कायदा को खत्म करने के लिए ही अमेरिका अफगानिस्तान गया और उसने नाटो सेनाओं को युद्ध में झोंका। एक अनुमान के मुताबिक, उसे इन सालों में करीब 180 लाख करोड़ रुपए फूंकने पड़े। हजारों सैनिकों और नागरिकों की जान गई वो अलग। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि क्या लादेन और जवाहिरी जैसे योजनाकारों के अभाव में अल-कायदा खत्म हो जाएगा? इसका जवाब मुश्किल है। लेकिन यह सच है कि अल-कायदा समय के साथ कमजोर हो रहा है और उस पर दबाव जारी रहता है, तो उसके बिखरने की संभावना है। भले इस दौरान वह अपने मजबूत होने का संदेश देने के लिए इक्का-दुक्का बड़े हमले कर दुनिया को थर्राने की कोशिश करे।

अल-कायदा भारत को निशाने पर लेने की बहुत कोशिश करता रहा है। कश्मीर में उसने हाल के दशकों में अपने पैर जमाने की बड़ी कोशिश की लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जवाहिरी ने एक समय कश्मीर की स्थिति की तुलना फिलस्तीन से की थी। जवाहिरी भारत में कश्मीर मुद्दे को लेकर जेहाद की भी बात करता था। हाल ही में उसने कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद पर भी बयान देकर उसका समर्थन किया था। उसने भारत के समर्थन के लिए सऊदी अरब जैसे देशों की आलोचना भी की थी। जवाहिरी के अफगानिस्तान में मारे जाने से यह तो पता चल गया है कि अल-कायदा तालिबान की सत्ता वाले इस देश को फिलहाल अपने लिए सुरक्षित ठिकाना मान रहा है और वह भारत सहित एशिया क्षेत्र के देशों के खिलाफ अपनी गतिविधियां वहां से चला रहा है। हाल में भारत ने तालिबान नेतृत्व के साथ संपर्क साधा है और अपना दूतावास भी काबुल में सक्रिय किया है। भारत का मकसद अफगानिस्तान की जमीन को अल-कायदा जैसे गुटों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना ही है। पूर्वोत्तर राज्य असम में 29 जुलाई को अल-कायदा से जुड़े एक्यूआईएस और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था। मोरीगांव, बारपेटा, गुवाहाटी और गोलपारा जिलों से इन लोगों के पकड़े जाने से जाहिर होता है कि अल-कायदा भारत में पैर जमाने की कोशिश में है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय एजेंसियों की सक्रियता के चलते उसे उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है।

अल जवाहिरी के अमेरिका के हाथों मारे जाने से निश्चित ही अल-कायदा को बड़ा झटका लगा है। सन् 2019 में फ्लोरिडा में तीन अमेरिकी नौ सैनिकों की हत्या में जवाहिरी की भूमिका रही। हालांकि छिटपुट आतंकी घटनाओं को छोड़ जवाहिरी के मुखिया रहते अल-कायदा कमजोर हुआ है। अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जवाहिरी ने इस बीच आईएसआईएस जैसी इस्लामिक स्टेट बनने के सपने से दूर सीरिया, यमन, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में सहयोगी संगठनों के जरिये विस्तार किया। उसने अल-कायदा को आतंकी संगठनों का सांकेतिक नेतृत्व के लायक बनाए रखा। हालांकि जवाहिरी की मौत के बाद अल-कायदा मिटने की कगार पर आ खड़ा हुआ है, ऐसा बहुत से रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं। सीरिया में उसकी एक शाखा को इसी साल जून में एक प्रतिद्वंद्वी गुट ने ही खत्म कर दिया। यमन में उसे अपने नेता के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने के कुछ ही समय बाद विद्रोहियों के हाथों हारना पड़ा। इसी साल माली में फ्रांस के एक हमले में उसके नेता की मौत के बाद अभी तक उसका उत्तराधिकारी तक अल-कायदा नहीं चुन पाया है। भले ही अफ्रीकी देशों सोमालिया और माली में अल-कायदा की शाखाएं अब भी मजबूत हैं। अल-कायदा का सबसे ताकतवर और खतरनाक गुट अल-शबाब है। सोमालिया के मध्य और दक्षिणी हिस्से के अधिकतर ग्रामीण इलाके आज भी अल-शबाब के कब्जे में हैं, जहां उनकी सत्ता चलती है। सीरिया में अल-कायदा की नुमाइंदगी उसका अघोषित गुट हुर्रास अल-दीन करता है; लेकिन वह अपनी पैठ बनाने में नाकाम रहा है। कारण अमेरिका का लगातार दबाव और आपसी अनबन है। सीरिया के लोग अल-कायदा को एक खतरा मानते हैं। हुर्रास अल-दीन को उनका ही एक प्रभावशाली विरोधी गुट चुनौती दे रहा है।

उधर यमन में इसकी शाखा अल-कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला (एक्यूएपी) एक जमाने में अल-कायदा का बहुत खूंखार गुट था। आज वह अल-कायदा के सबसे कम सक्रिय गुटों में शामिल है। जनवरी में एक्यूएपी के प्रमुख को अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। यही नहीं, हाल ही में बाकायदा सूबे में हूथी विद्रोहियों ने एक्यूएपी का एक मजबूत गढ़ उससे छीन लिया। यह माना जाता है कि एक्यूएपी में जासूसों की सेंध ने उसकी बड़ी तबाही की है। अल-कायदा के कमजोर होने की एक बड़ी वजह सामान्य मुस्लिमों में पहुंच बना पाने में उसकी नाकामी है। अल जवाहिरी के समय में भी इस दिशा में कुछ नहीं हुआ। वह खुद को आधुनिक बनाने में भी नाकाम रहा है। इसका कारण यह है कि वह खुद की कट्टर जिहादी संगठन की छवि नहीं बदलना चाहता। उसका नेतृत्व महसूस करता है कि रास्ता बदलने से उसके अस्तित्व पर ही संकट आ सकता है। हालांकि अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए अल-कायदा ने हाल के वर्षों में कई हमले भी किए हैं।

● **कुमार विनोद**

## अमेरिका ने ही पाला था अल-कायदा को!

आज भले अमेरिका अल-कायदा का दुश्मन हो, लेकिन एक जमाने में अमेरिका ने ही उसे पाला-पोसा। आज जो तालिबान अफगानिस्तान में शासक है, उसके अल-कायदा से पुराने रिश्ते हैं। याद करें, तो पता चलता है कि 80 के दशक में जब तत्कालीन सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जे की जंग लड़ी उस समय सोवियत संघ को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए जो संगठन बने उनमें अल-कायदा एक था। ओसामा बिन लादेन ने इसका गठन किया था। उसे सोवियत संघ के खिलाफ लड़ रहे मुजाहिदीनों का भी समर्थन था। लेकिन हैरानी यह है कि अल-कायदा को अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का भरपूर समर्थन था। समय के साथ अल-कायदा अमेरिका के लिए ही सांप बनकर आ खड़ा हुआ और नौबत यह आ गई कि इसी अमेरिका ने इस आतंकी संगठन के दो प्रमुखों को मारने का काम किया।

# आर्थिक मोर्चे पर महिलाएं

आत्मनिर्भर भारत का विचार पुरातन संस्कृति और संस्कार का वह प्रस्फुटन था, जिसने भारत को संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था का चालक और नियंत्रक बनाया था। विभिन्न कालखंडों में अनेकानेक आक्रांत विचारधाराओं ने आत्मनिर्भर भारत के भाव को धूमिल अवश्य कर दिया था, परंतु अपने अथक प्रयासों के उपरांत भी उसे नष्ट नहीं कर पाए। आत्मनिर्भरता का वास्तविक अर्थ गैर-भावनात्मक निर्भरता से है। स्पष्ट है यह वह स्वरूप है जहां हमारी आंतरिक प्रसन्नता बाह्य उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती। आज ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यमिता न केवल उनके आर्थिक संबल को विस्तार दे रही है, बल्कि उनके व्यक्तित्व को भी सशक्त कर रही है।

इन प्रयासों में तीव्रता लाई जाती है तो 2030 तक महिलाओं के स्वामित्व वाले 3.15 करोड़ उद्यम हो सकते हैं। देश में अगर बहुतायत संख्या में महिलाओं ने उद्यमिता को अपनाया तो इस समय सीमा के भीतर लगभग 15 से 17 करोड़ रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। यदि अधिक महिलाएं कार्यबल का हिस्सा बनती हैं तो यह 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 0.7 ट्रिलियन डालर की वृद्धि करेगा। मुद्रा योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी अनेक योजनाओं ने महिलाओं के आर्थिक संबलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वस्तुत: अवसरों की उपलब्धता और भागीदारी महिलाओं के लिए सशक्तीकरण की असीम संभावनाएं बनाती है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण राष्ट्र और आत्मनिर्भर भारत के विकास लक्ष्यों के साथ महिलाओं को एकीकृत करने का सबसे व्यावहारिक समाधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं, सामाजिक-आर्थिक उन्नति और डिजिटल माध्यमों का प्रभावी रूप से प्रयोग कर अपने समुदाय के भीतर अपने लिए विश्वसनीयता और नेतृत्व क्षमता को स्थापित किया है। ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने न केवल धन अर्जन में अपनी भूमिका दर्ज कराई है, अपितु भावी संगठनों का निर्माण करते हुए अभिकर्ताओं का स्वरूप भी परिवर्तित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएं कृषि कार्य, डेयरी उद्योग, पशुपालन, मत्स्य पालन और कुटीर उद्योगों सहित आर्थिक गतिविधियों के विस्तृत दायरे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

बचत, उपभोग-अभिवृत्ति और पुनर्चक्रण-प्रवृत्ति के संदर्भ में किंचित संदेह नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था महिला केंद्रित है। वे भूमि की तैयारी से लेकर विपणन तक कृषि से संबंधित सभी गतिविधियों में संलग्न हैं। पशुधन एक प्रथम आजीविका गतिविधि तो है ही साथ ही इसका उपयोग घरेलू खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। मत्स्य पालन में प्रसंस्करण महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये वे महिलाएं हैं, जिन्होंने तमाम मिथकों को ध्वस्त करते हुए अपना नया अस्तित्व गढ़ा है। साथ ही स्थानीकरण और विकेंद्रीकरण को मजबूती देते हुए उस धारणा को भी गलत सिद्ध किया है, जो इस सोच के साथ उभरती है कि अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण उद्योगीकरण से ही हो सकता है।

आज आत्मनिर्भर भारत की स्वप्निल छवि भारत के उन गांवों में प्रतिबिंबित हो रही है, जहां गांव के नाम, उसकी पहचान वहां की महिलाओं के नाम से हो रही है। वे न केवल स्वयं को सशक्त कर रही हैं, अपितु अपने समुदाय को भी सुदृढ़ कर रही हैं। कृषि मित्र, आजीविका पशु मित्र, वीसी सखी जैसी उपमाओं से विभूषित महिलाएं 'स्वायत्तता' के वास्तविक अर्थ को उद्घाटित करने में अनवरत प्रयास कर रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और धीरे-धीरे इसकी कमान महिलाओं के हाथ में आ गई है।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत सरकार महिला सशक्तीकरण परियोजना चला रही है। इस परियोजना के अंतर्गत महिला किसानों को कृषि के आधुनिक तौर-तरीके सिखाए जा रहे हैं। यहां स्वायत्तता का अर्थ किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता से भी है। ग्रामीण महिला उद्यमियों में उच्च स्वायत्तता उनकी रुचि के व्यवसाय को चुनने की उनकी क्षमता प्रकट करती है। वहीं महिला उद्यमियों में व्यक्तिगत विकास उनके विकास के तरीके को निर्धारित करता है। ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में स्थानीय समुदायों और राष्ट्र को समग्र रूप से बदलने की क्षमता है। उप्र की महिलाएं इसकी एक मिसाल के रूप में उभरी हैं, जिन्होंने मिशन शक्ति के तहत गाय के गोबर से दीये एवं गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति बनाकर स्वयं के लिए आत्मनिर्भरता का नया मार्ग प्रशस्त किया है। इसका उन्हें बहुत लाभ मिला है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

## महिला स्वायत्तता अर्थव्यवस्था का प्रमुख कारक

कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत का विशाल दृष्टिकोण उस केंद्रीय भाव और विचारधारा पर आधारित है जहां मिट्टी, पेड़, तालाब, नदी, पहाड़ हमारी अर्थव्यवस्था को संवारने के बीज मंत्र बने हैं। महिला स्वायत्तता देश की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का महत्वपूर्ण स्तंभ होने के साथ ही महिलाओं की प्रसन्नता एवं संतुष्टि का भी एक प्रमुख कारक है। यह उन चीजों को करने का विकल्प है, जो एक व्यक्ति स्वयं की संतुष्टि के लिए चुनता है और बिना किसी सामाजिक और पारिवारिक दबाव के मनोनुकूल परिवेश में कार्य करता है। हाल में भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के बीच खुशी का आंकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। उसके परिणाम बताते हैं कि स्वायत्तता, व्यक्तिगत विकास, आत्म-स्वीकृति, जीवन में उद्देश्य, प्रामाणिकता, क्षमता और निपुणता वे कारक हैं, जो खुशी के स्तर को बढ़ाते हैं। यह बताने के लिए काफी है कि महिला स्वायत्तता को लेकर केंद्र सरकार के अथक प्रयास न केवल आत्मनिर्भर भारत की नींव के पत्थर बनेंगे, बल्कि खुशहाल भारत के सुदृढ़ स्तंभ का आधार भी होंगे।

# ANU SALES CORPORATION

## We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

# मोहिं कपट छल छिद्र न भावा

तुलसीदास प्रकृत्या एक क्रांतदर्शी कवि थे, इस युग दृष्टा ने कालजयी रचना 'रामचरितमानस' में अपनी लोक व्यापिनी बुद्धि से व्यापक सहृदयता के साथ काव्य के सभी रसों के सूक्ष्मतम स्वरूपों को उकेरा है। रामचरितमानस अब तक या यूं कहें कि 'न भूतो-न भविष्यति' की सबसे लोकप्रिय, हृदयग्राही, सुबोध व सुगम्य कृति है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। लोगों को आज भी यही मिसाल देते सुना जाता है - कि पुत्र हो तो राम सा। रावण, कैकेयी, मन्थरा, ताड़िका - पहले भी थे और आज भी हैं। इन नकारात्मक शक्तियों के दमन के लिए ही समय-समय पर राम रूपी आदर्श व लोक मर्यादित चरित्र को समाज के बीच स्थापित करने की आवश्यकता रहती है। परंतु इस रचना के पीछे 'राम' के मर्यादा पुरुषोत्तम वाले रूप को केंद्र में रख मानव मात्र को यह संदेश देने का एक सफल प्रयास था कि - 'जहां सुमति तहां संपति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना।' देव, मानव, वानर व राक्षस जाति के उत्थान-पतन को चित्रित करती हुई यह कृति इसी भाव को उद्धृत करती है, सर्वोच्च मर्यादाओं की स्थापना का प्रयास करती है।

निरमल मन जन सो मोहिं पावा।
मोहिं कपट छल छिद्र न भावा।

श्री रामचरितमानस की यह चौपाई यह संकेत कर रही हैं, कि ईश्वर या उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए मन की निर्मलता परमावश्यक है। ईश्वर को छल-कपट आदि दोष नहीं भाता क्योंकि जो सर्वज्ञ है उससे छिपाव अर्थात् अभी तो आप ईश्वर को ईश्वर समझ ही नहीं रहे। इस संदर्भ में प्रभु से मारुति मिलन प्रसंग की चर्चा करना चाहूंगा।

सर्वप्रथम महाराज सुग्रीव के आदेश पर हनुमान जी विप्रवेष में प्रभु के पास गए। आदेश यही था-

धरि बटु रूप देखु तैं जाई।

इस कारण विप्रवेष में प्रभु के पास गए

विप्ररूप धरि कपि तहं गयऊ।
माथ नाइ पूछत अस भयऊ।

यहां पर विप्र का एक क्षत्रिय के सामने शीश झुकाना असंगत लगता है। सच्चाई तो छुपती ही नहीं। हनुमान जी विप्र तो हैं नहीं, कपट वेष के कारण उन्हें यह खयाल ही नहीं रहा कि एक विप्र क्षत्रिय के समक्ष शीश नहीं झुकाता। दूसरी बात सच्चे भक्त हनुमान जी जो ईश्वरावतार हेतु प्रतीक्षारत हैं, उन्हें आभास हो रहा है, कहीं वे यही तो नहीं? उनके प्रश्न से भी यही झलकता है 'छत्री रूप फिरहु बन वीरा।' आप क्षत्रिय के रूप में हैं, अर्थात् क्षत्रिय नहीं है। या फिर आप-

की तुम्ह तीनि देव महं कोऊ।
नर नारायण की तुम्ह दोऊ।
की तुम्ह अखिल भुवनपति,
लीन्ह मनुज अवतार।

इस कारण भी हनुमान जी का शीश झुकाना स्वाभाविक लगता है। श्रीराम जी ने अपना समयानुसार परिचय देते हुए हनुमान जी का परिचय पूछा। इस पर परम भक्त, परम योगी हनुमान जी प्रभु को पहचान उनके चरणों में गिर गए और परमानंद का अनुभव किया-

प्रभु पहिचानि परेउ गहि चरना।
सो सुख उमा जाइ नहीं बरना।

और नाना स्तुति करने लगे। तत्पश्चात तीन चौपाई और एक दोहे के सोलह पदों में अपनी शरणागति निवेदन की और इस बीच चार बार ऐसा समय आया जब प्रभु को उनकी शरणागति स्वीकार कर ही लेनी थी पर श्रीराम खड़े मुस्कुराते रहे क्योंकि अभी तो हनुमान जी ने अपना कपट (वेष) त्यागा ही नहीं, परंतु ज्योंहीं हनुमान जी ने कपट वेष त्यागा, प्रभु ने गले से लगाकर उन्हें अपना लिया। यथा

अस कहि परेउ चरन अकुलाई।
निजतनु पगटि प्रीति उर छाई।
तब-तब रघुपति उठाई उर लावा।
निज लोचन जल सींचि जुड़ावा।

इस प्रकार प्रभु ने हनुमान को अपनी शरण में ले लिया। मारीच बध प्रसंग में भी मारीच के कपट वेष त्यागने पर ही प्रभु ने अपने शरण का आश्रय प्रदान किया। यथा-

प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा।
सुमेरिसि राम समेत सनेहा।
अन्तर प्रेम तासु पहिचाना।
मुनि दुर्लभ गति दीन्ह सुजाना।

दोनों ही जब मन वचन और कर्म से निष्कपट समर्पित हुए तभी शरणागति स्वीकार की गई। श्री हनुमान जी के 'अस कहि' (बचन) परेउ चरन (कर्म) और 'प्रीति उर छाई' (मन) तथा मारीच के- सुमिरेसि (वचन और कर्म) 'समेत सनेहा' (मन) पूर्ण निष्कपट समर्पण ही स्वीकार हुआ-

निरमल मन जन सो मोहि पावा।
मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
खलन्ह हृदयं अति ताप बिसेषी।
जरहिं सदा पर संपति देखी॥
जहं कहुं निंदा सुनहिं पराई।
हरषहिं मनहुं परी निधि पाई॥

यानी दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे दूसरों की संपत्ति (सुख) देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुनते हैं, वहां ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे कोई रास्ते में पड़े खजाने को पाकर खुश होता है।

एक आदर्श भाई के रूप में भरत के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए राम कहते हैं:- 'भरत सरिस प्रिय को जग माहिं, इहईं सगुन फल दूसर नाहि।' लोक मर्यादा कहती है कि प्रसन्नता में कभी वचन न दो और क्रोध में प्रण न करो। राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में कैकेयी द्वारा उनकी विपत्ति में की गई सहायता की खुशी में वचन दे दिए और जिसका दुष्परिणाम उन्हें राम के वनगमन के रूप में देखना पड़ा। किसी के जरा से भी किए गए एहसान को सज्जन कभी खाली नहीं रखते, बल्कि बदले में इतना लौटा देते हैं, जिसकी एहसान करने वाले ने कभी कल्पना भी न की हो। नाव उतराई के कवेट प्रसंग को ही लें:- 'मनि मुंदरी मन मुदित उतारी, कहेऊ कृपाल लेऊ उतराई।'

राम एक ऐसे चरित्र के रूप में रामचरितमानस में चित्रित किए गए हैं, जिनके बिना जीने का आनंद नहीं। वह दीन, दु:खी व जरूरतमंदों के संबल हैं:- 'हा रघुनंदन प्रान परीते, तुम्ह बिन जिअत बहुत दिन बीते, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनि न जाए।' काम, क्रोध, लोभ, मोह से त्रस्त हृदयों के लिए राम रूपी शीतलता एक औषधि की तरह है। लंका विजय के समय भालू, बंदर आदि की सहायता लेना, इस बात का द्योतक है कि राम ने अपनी प्रभुता सिद्ध करने का नहीं, अपितु छोटे से छोटे जीव को भी साथ लेकर एक लक्ष्य को साधने का प्रयास किया, ताकि अधर्म व अन्याय रूपी रावण को समाज से हटाया जा सके व मानवीय मूल्यों की स्थापना हो। विभीषण ने भले ही अपने भाई को किसी कारण से त्यागा हो और जब वह शरण मांगने राम के पास गया तो उन्हें शत्रुपक्ष के इस व्यक्ति को शरणागति देने से रोका गया, परंतु राम ने किसी की परवाह न करते हुए अपनी विशालता व सद्हृदयता का परिचय दिया:- 'जौं नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय सरन तकि मोहि, तजि मद मोह कपट छल नाना, करहुं सद्य तेहि साधु समाना।' राम ने अपने सच्चरित्र से विभीषण को भी पारस बना दिया। सेवक को उचित सम्मान देने का महान गुण राम ने दिखाया। हनुमान मिलन पर रघुनाथ ने उन्हें हृदय से लगाया व लक्ष्मण से भी अधिक स्नेह दिया। रामचरितमानस में इन चरित्रों के माध्यम से जीवन दर्शन के संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। इन्हीं दर्शाए गए आदर्शों व मूल्यों का परिणाम है कि प्रतिदिन गांव-गांव, घर-घर, पंसारी की दुकान से लेकर बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं तक राम नाम पर एक सी श्रद्धा है।

● **ओम**

# खुशियों की बारिश

घर में हरियाली तीज की तैयारियां चल रही थीं। बाहर लॉन में झूले को सजाया जा रहा था।

कावेरी अपने पति गिरिश से कहती है, सोच रही हूं इस बार तीज में रितु को बुला लूं। आखिर कब तक उससे नाराजगी रखेंगे! मां हूं मैं... अब उससे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हूं।

बिल्कुल नहीं... वह हमारी बेटी नहीं है। जबसे उसने अपनी मर्जी से दूसरी जाति के लड़के से विवाह किया तभी से मैंने उसे मरा हुआ समझ लिया। गिरीश ने कड़क स्वर में कहा।

कब तक इस अंधी सोच में पड़े रहोगे! क्या हम उससे भी बेहतर लड़का तलाश करते? लड़का गुणी हैं, संस्कारी है, अच्छे पद पर नौकरी करता है। सिर्फ एक जाति के आधार पर बच्चों की खुशियों को कुचलना सही नहीं, कावेरी ने गिरीश को समझाने का प्रयास किया।

कावेरी और गिरीश के बीच काफी बातें हुई और अंत में गिरीश को भी रितु की खुशियों को कुबूल करना पड़ा। कावेरी ने रितु को फोन लगाया और दामाद के साथ घर आने को कहा। फोन पर मां के शब्दों को सुनकर रितु भावुक हो गई। बहुत दिनों के बाद इस सावन रितु का तन-मन खुशियों की बारिश में भींग रहा था।

**- रेखा भारती मिश्रा**

## हंसते रहोगे

हंसते रहोगे जिंदगी
हंसती नजर आएगी।
होंगे उदास तो जिंदगी भी,
उदास चली जाएगी।
सुख-दुख तो जीवन के दो पहलू हैं,
साथ-साथ चलते रहेंगे
राहों में सिर्फ फूल नहीं है,
कांटे भी मिलते रहेंगे।
कांटो से भी दोस्ती की
राह मिल जाएगी
हंसते...
तन्हा सफर भी कट जाएंगे
यादों के सहारे
मंजिलें फिर से
तुझे एक बार पुकारें
छोड़ के पीछे यादें
आगे उम्र निकल जाएगी
हंसते...
बेजान पुतला न बन
किसी के हाथों का
हमसफर यहां मिलता है
एक-दो मुलाकातों का
तेरी खुद की उम्मीदें ही
तुझकों जिताएंगी
हंसते...

**- वीणा चौबे**

## उपहार

जमूरा-उस्ताद! मुझे आज उपहार इनाम चाहिए।

बोल जमूरे! आज जीवन में पहली बार तूने रोटी के अलावा कुछ मांगने के लिए मुंह खोला है, जरूर दूंगा, मांग।

जमूरा मदारी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, उस्ताद! स्वराज की 75वीं सालगिरह पर क्या आप मेरे लिए भारत से कुपोषण को उड़नछू करोगे?

मदारी की आंखें छलछला उठी, उसने धरती माता को प्रणाम किया, माटी को भाल पर लगाया और अपने इष्ट देवता से प्रार्थना की और बिना उत्तर दिए ही उसने सात्विक आक्रोश के साथ, हवा में हाथ लहराया और फिर मुट्ठी खोल दी, उसमें से एक क्षीणकाय पक्षी निकला, जो तेजी से बड़ा होता गया, पूरा आकाश उसके पीछे छिप गया और कुछ ही मिनटों में वह पक्षी बादलों के पार अदृश्य हो गया।

फिर मदारी बोला! जमूरे, जल्दी ही वो दिन आएगा, जब कुपोषण भारत से इसी पक्षी की तरह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा।

**- डॉ. मनोहर लाल भण्डारी**

PRISM®
CEMENT

# प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

**ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.**

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

# पंत के पास अनंत प्रतिभा

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत की शानदार बैटिंग की चर्चा जोरों पर है। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में शानदार शतक लगाकर ऋषभ पंत ने अब तक हो रही आलोचनाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है। वैसे, 24 साल के इस युवा खिलाड़ी के पास अभी बहुत क्रिकेट बची है। और, ऋषभ पंत की हालिया इनिंग ने साबित कर दिया है कि अगर वह शुरुआती कुछ मिनटों तक विकेट पर जमे रहने की कोशिश करें। तो, शायद हर बार उनके बल्ले से एक बेहतरीन पारी देखने की उम्मीद की जा सकती है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो ऋषभ पंत अब वनडे मैचों में मैच विनर के साथ ही मैच फिनिशर खिलाड़ी के तौर पर भी मशहूर होने वाले हैं। वैसे, उम्र के जिस पड़ाव पर ऋषभ पंत खड़े हैं। उनके पास एक बड़ा मौका है। लेकिन, देखना होगा कि वह धोनी बनेंगे या विराट?

पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आईसीसी की सभी ट्रॉफी को अपने कैप्टन कूल अंदाज से टीम इंडिया के खाते में डाला। कैसी भी परिस्थिति रही हो, क्रिकेट फैंस ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना पारा खोते हुए नहीं देखा है। अपने शांत स्वभाव के साथ मैदान पर आने वाले महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए मैच फिनिशर की भूमिका निभाते रहे हैं। आसान शब्दों में कहा जाए, तो कैप्टन कूल का तमगा महेंद्र सिंह धोनी को उनके कूल टेम्प्रामेंट ने दिलाया था।

वहीं, विराट कोहली की बात करें। तो, कोहली भी टीम इंडिया के सफलतम कप्तानों में से एक रहे हैं। विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन, विराट कभी भी टीम इंडिया को कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जिता सके। ऐसा नहीं है कि इस दौरान विराट का बल्ला नहीं बोला। विराट कोहली ने 462 मैचों में 23709 रनों के साथ 70 शतक जड़े। और, टीम इंडिया के लिए मैच विनर की भूमिका निभाते रहे। लेकिन, करीब तीन साल से खराब फॉर्म का शिकार हैं।

इसकी सबसे बड़ी वजह विराट कोहली की आक्रामकता को माना जाता है। दरअसल, विराट कोहली पिच के पास खड़े हों या बाउंड्री लाइन पर उनकी आक्रामकता बाहर आ ही जाती है। अंपायर से लेकर विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से भिड़ंत विराट कोहली की आक्रामकता के कुछ उदाहरण भर हैं। वरना विराट तो दर्शक दीर्घा से आने वाली शब्दों पर भी रिएक्ट करने से नहीं चूकते हैं। जबकि, ऐसी ही जगहों पर महेंद्र सिंह धोनी अपने शांत स्वभाव को बनाए रखते थे। अंपायरों या विपक्षी खिलाड़ियों से बहस के समय भी महेंद्र सिंह धोनी के हाव-भाव बिल्कुल शांत नजर आते थे। दबाव भरे मैचों में भी महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा कभी उनके चेहरे पर महसूस नहीं किया जा सकता था। आसान शब्दों में कहा जाए, तो महेंद्र सिंह धोनी की आक्रामकता उनके बल्ले तक ही सीमित थी। इस मामले में विराट कोहली थोड़ा कमजोर नजर आते हैं।

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में ऋषभ पंत की ओर से खेली गई शतकीय पारी के बाद उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन, इस जश्न में सौम्यता का पुट था। टेस्ट मैचों में कई मैचजिताऊ पारियों के साथ पांच शतक जमा चुके ऋषभ पंत कभी भी उग्र होते दिखाई नहीं पड़ते हैं। वैसे, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में इससे इतर भी कई समानताएं हैं। दोनों ही विकेटकीपर होने के साथ आक्रामक बल्लेबाज हैं। महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही ऋषभ पंत भी मैच को पलटने का माद्दा रखते हैं। और, आखिरी ओवरों में विस्फोटक खेल दिखाने से नहीं चूकते हैं। कई बार क्रिकेट के मैदान पर ऋषभ पंत को महेंद्र सिंह धोनी की नकल करते हुए स्टंपिंग या रन आउट करने की कोशिश करते हुए भी देखा जा चुका है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो पंत कहीं न कहीं धोनी की राह पर ही चल रहे हैं। लेकिन, अभी तक कप्तानी में उनके जैसे साबित नहीं हो सके हैं। वैसे भी ऋषभ पंत को बीसीसीआई की ओर से एक प्रयोग के तौर पर ही कप्तान बनाया गया है। लेकिन, अगर वह अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखते हैं। तो, उन्हें मौका मिलना कोई बड़ी बात नहीं है।

**● आशीष नेमा**

## विवादों से दूर ऋषभ पंत

विराट कोहली के नाम साथ विवादों की एक लंबी लिस्ट जुड़ चुकी है। टीम इंडिया के साथी खिलाड़ियों से विवाद से इतर विराट कोहली सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए भी विवादों में शामिल होने से संकोच नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, विराट कोहली की आलोचना अपने खेल की जगह विज्ञापनों को लेकर भी खूब होती थी। लेकिन, क्या ऐसा कभी महेंद्र सिंह धोनी के लिए सुना गया था? महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी के दौरान बेवजह के विवादों से खुद को दूर ही रखा था। और, ऐसा भी नहीं है कि धोनी उस दौरान बड़ी संख्या में विज्ञापन नहीं करते थे। लेकिन, महेंद्र सिंह धोनी अपनी पारियों से अपने विज्ञापनों को जस्टिफाई करते रहते थे। लेकिन, विराट के मामले में ये चीज गायब नजर आती है। खैर, महेंद्र सिंह धोनी की तरह ही ऋषभ पंत भी विवादों से दूर ही खड़े दिखाई पड़ते हैं। वैसे, ऋषभ पंत एक युवा खिलाड़ी हैं। और, उनके सामने एक लंबा क्रिकेट कैरियर पड़ा है। तो, देखना दिलचस्प होगा कि वह धोनी बनेंगे या विराट?

*बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में शामिल इरफान खान आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनके कुछ खास मौके पर फैंस उन्हें याद कर लेते हैं। इरफान खान पठान परिवार के थे लेकिन फिर भी वे बचपन से शाकाहारी थे। उनके परिवार वाले उन्हें हमेशा ये कहकर चिढ़ाते थे कि पठान परिवार में 'ब्राह्मण लड़का' पैदा हो गया।*

# इरफान खान को सभी लोग क्यों बुलाते थे 'ब्राह्मण का लड़का'?

इरफान खान का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है और जब उन्होंने एनएसडी में प्रवेश लिया तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। परिवार का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने एसी मकेनिक के तौर पर काम किया था और इसी दौरान उनकी मुलाकात राजेश खन्ना से हुई थी क्योंकि वह उनके घर एसी ठीक करने गए थे। राजेश खन्ना की शान-ओ-शौकत देखकर इरफान काफी प्रभावित हुए थे।

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) में पढ़ाई करने के दौरान इरफान खान को मीरा नायर ने सलाम बॉम्बे में बड़े रोल के लिए चुना। मुंबई में आकर वे कई वर्कशॉप में शामिल हुए लेकिन वे फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। एनएसडी के दौरान उन्हें कुछ सीरियल में काम करने का मौका मिला, जिसमें चंद्रकांता, बनेगी अपनी बात, भारत एक खोज, जस्ट मोहब्बत जैसे टीवी शोज में काम किए। साल 1988 में ही मीरा नायर ने उन्हें पहला मौका दिया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में छोटे-मोटे किरदार निभाए। साल 1995 में इरफान खान ने अपनी एनएसडी की दोस्त सुतापा सिकंदर के साथ शादी की। उनके दो बेटे हैं।

इरफान खान ने अपने कैरियर में लगभग 80 फिल्मों में काम किया था और कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इरफान की सफल फिल्मों में अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक पार्क, स्लमडॉग मिलेनियर, द लंचबॉक्स, पीकू, पान सिंह तोमर, मदारी, तलवार, पज्जल, मकबूल, जज्बा, हैदर, रोग, थैंक्यू, लाइफ इन अ मेट्रो, डी-डे, न्यूयॉर्क, सात खून माफ, किस्सा, द किलर, सलाम बॉम्बे, बाजीराव मस्तानी, मुंबई मेरी जान जैसी फिल्मों में काम किया।

# फिल्म के सेट पर 30 रोटियां खा जाते थे सलमान खान

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का आज बॉलीवुड में बोलवाला है। वहीं, सलमान खान को देश ही नहीं दुनिया में भी लोग पहचानते हैं। सलमान खान बीते 32 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लोग सलमान की एक्टिंग के साथ उनकी पर्सनालिटी के भी दीवाने हैं।

सलमान ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में इस फिल्म से जुड़ा किस्सा बताया था। उन्होंने बताया था कि, मैं कैरियर के शुरुआती दिनों में काफी दुबला-पतला था। जिसके कारण मैं बहुत परेशान था, मैं किसी भी तरह से अपना वजन बढ़ाना चाहता था। इसलिए मुझे जो कुछ भी शूटिंग के दौरान मिलता था मैं खा लिया करता था। मैं सेट पर एक बार 30 रोटियां और बहुत सारे केले खा जाया करता था। आपको बता दें कि सूरज बड़जात्या के निर्देशन में फिल्म 'मैंने प्यार किया' सिर्फ 2 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई थी। सलमान खान को उनकी इस पहली फिल्म की कमाई 31 हजार रुपए दी गई थी। रिलीज के बाद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दो करोड़ की लगात से बनी इस फिल्म ने 28 करोड़ की कमाई की थी। इस फिल्म में सलमान खान और एक्ट्रेस भाग्यश्री के साथ ही अभिनेता आलोकनाथ भी अहम रोल में नजर आए थे।

# जब बॉबी देओल के टूटे पैर की वजह से टल गई फिल्म

बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाने वाले बॉबी देओल ने बहुत सी हिट फिल्में दी हैं। लेकिन फिल्म गुप्त को लेकर कई किस्से हैं, जो लोगों को हैरान कर देते हैं। पहले गुप्त को 1996 में रिलीज करने का प्लान था। इस साल जनवरी में शूटिंग भी शुरू हो गई थी। शूटिंग के कुछ दिन बीते ही थे कि बॉबी एक सीन के दौरान बुरी तरह घायल हो गए। उनका पैर टूट गया। हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया उनके चलने-दौड़ने लायक होने में तो, कई महीने लग जाएंगे। इसके बाद गुप्त की शूटिंग पोस्टपोन हो गई।

टीम केरल में रेडी थी। यहां एक गाना शूट होना था। राजीव ने बॉबी से कहा कि अगर वो किसी तरह ये एक गाना अभी शूट कर लें, तो केरल का काम निपट जाएगा। बाकी फिल्म आराम से जब वो ठीक हो जाएंगे, तब कर लेंगे। बॉबी दर्द में थे लेकिन मान गए। ये गाना था मुश्किल बड़ा ये प्यार है। जिसमें मनीषा कोइराला और बॉबी नाच रहे थे। लेकिन पूरे गाने को अब आप अगर दुबारा देखेंगे तो पाएंगे कि बॉबी सिर्फ एक जगह खड़े होकर डांस कर रहे हैं। जिस वजह से कुछ डांस स्टेप्स बड़े वीयर्ड भी लग रहे हैं। इन्हीं स्टेप्स की वजह से बॉबी आजतक ट्रोल भी होते रहते हैं। लेकिन भाई बॉबी का दोष नहीं है। वो दर्द में था।

# कबीर एक चाहिए

परम् सौभाग्य का विषय है कि जब हमने इस दुनिया की धरती पर पदार्पण किया और कुछ करने के योग्य हुए तो हमने पाया कि यह समाज जिसके मध्य रहकर हम निर्विघ्न रूप से सांस ही नहीं ले रहे; वरन रह भी रहे हैं। इस अत्यधिक सुधरे हुए समाज में हमारे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा; अब आप ही बताइए भला कि इस समाज के लिए क्या नया करके हम अपना नाम मुस्कराते हुए फोटो सहित अखबार की सुर्खियों में छपवाएं कि सारा देश और समाज धन्य-धन्य कह उठे कि वाह! 'देश प्रेमी' जी आप तो आप ही हैं; जो आपने समाज को ऊपर उठाकर कहां से कहां पहुंचा दिया। यदि आप नहीं होते तो इस समाज और देश का क्या होता! ये वहीं का वहीं पड़ा रह जाता। पर खेद है कि क्या करें; करने के लिए, अपने समाज सुधारक हाथ दिखाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। सब कुछ पहले से ही ठीक-ठाक मिला है।

साहित्य की किताबों में पढ़ते हैं कि आज से छः-सात सौ वर्ष पहले समाज के विभिन्न धर्मों, मजहबों, जातियों, वर्णों के बीच गहरी खाइयां बनी हुई थीं, जिन्हें पाटने के लिए एक साहसी समाज सुधारक संत कवि कबीर ने अपने दोहों के फावड़े चला-चलाकर देश में घूम-घूमकर दिन-रात पसीना बहाया, पर कह नहीं सकते वे अपने सपनों को साकार करने में कितने सफल हुए। हां, इतना अवश्य हुआ कि उनके सुधार की बात सुनकर ऐसा लगा कि लोगों के कानों में सीसा पिघलाकर डाला जा रहा हो। कबीर न हिंदुओं को अच्छे लगे और न मुसलमानों को। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा वह भले ही सत्य हो, पर करेले जैसा कड़वा ही था। आप जानते हैं कि करेला चाहे कितना ही गुणकारी हो, सबको प्रिय नहीं होता। यही बात कबीर के समय में कबीर वाणी के लिए भी थी। जैसे सुअर को कीचड़, गुबरैले को गोबर, मुर्गे को बांग, मुर्गापसंद को टांग, हालाप्रिय को नाला, मिठाई को लाला, चरित्रहीन को घोटाला, नेताजी को माला-दुशाला, दोस्तों को प्याला, सपेरे को नाग काला; पसंद है। वैसे ही खाइयों के वासियों को कबीर नापसंद थे। पर क्या करें... 'जो आया जेहि काज सों, तासे और न होय।' के अनुसार तो कबीर दास जी जिस काज से आए थे, उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी-

- 'अरे इन दोऊ राह न पाई।
हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुरकन की तुरकाई।
हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई।
वेश्या के पामन तर सोवें, यह देखो हिंदुआई।
मुसलमान के पीर औलिया, मुरगा-मुरगी खाई।।'

आज का समाज खाइयों में नहीं; हिमालय की ऊंचाइयों में निवास कर रहा है। हर वर्ग, वर्ण, जाति के अपने ऊंचे-ऊंचे पहाड़ हैं, जिन पर इधर-उधर उगाए गए सुंदर कैक्टस के झाड़ हैं, कोई किसी से छोटा नहीं है। सब बड़े हैं। अपनी-अपनी तर्क-संहिता पर अड़े हैं। ऊंच-नीच, छुआछूत, भेदभाव, असमानता-कबीर काल से भी ऊंची है। लेकिन हॉस्पिटल की उस टेबिल पर जहां उसे रक्त लेना है, जाति, वर्ण भेद भुलाकर देवता हो जाता है आदमी। भोजन पानी किसी निम्न वर्ण का स्वीकार नहीं, परंतु यहां कोई इनकार नहीं। बस जान! जान!! और जान!!! और किसी से नहीं कोई पहचान। किसी भी तरह बचे जान। चाहे किसी का भी लहू भर दो, पर मरते हुए को जिंदा कर दो। ये भेदभाव, छोट बड़ाई बस चौके से चौकी तक ही है। वास्तव में समाज बहुत ऊंचाई पर आसीन हो चुका है। अब तक तो गधे को बाप बनाने में भी परहेज नहीं था, पर अब तो गधा ही नहीं, सुअर, श्वान या बिना स्नान शूद्र भी चलेगा। जरूरत जब आन पड़ी तो अपनी पवित्र आत्मा को भी छलेगा। मर ही गया तो अपने हाथ भी नहीं मल सकेगा। इसलिए पहले जान, फिर कोई और सामान। सारी हेकड़ी चूर-चूर। समय की मांग है, होना पड़ा मजबूर। अब नहीं कहता दूर-दूर। पता नहीं कहां हो गया परिजन सहित पेशेंट का अहं काफूर।

याद आता है कभी संत कबीर ने सही कहा था। जो तब तो लगता था तमाचा, पर आज समझ में आ रहा है वह था जगाने का बाजा। पर सच की आवाज सुनना ही कौन चाहता है। अपने पैमाने से दुनिया को नापता है। जो समझता है अपने को ऊंचे पहाड़ पर, वह वास्तव में बनाए बैठा है घर आड़ पर। कुएं का मेंढ़क जब कुएं से बाहर आया तो उसे बाहर बड़ा-बड़ा दृश्य भी नजर आया। बेचारा बहुत ही शरमाया। अपने आनंद को स्वयं ही धक्का लगाया। सड़े हुए जल को पिया और पिलाया। कुल मिलाकर बहुत ही भरमाया। समय भी गंवाया। पर आंख जब खुली तो एक नया जगत ही हुआ नुमाया। जब तक पड़ा रहा दिल-दिमाग पर भ्रम का साया, नए युग में समझदार बहुत पछताया। नासमझ कभी पछताते नहीं। क्योंकि अपने को छोड़ किसी को सही बताते नहीं।

मुझे लगता है कि आज भी एक कबीर चाहिए। जो अहंवादियों की आंखें खोले ही नहीं, पुतलियां बाहर लाकर दिखला दे कि देख दुनिया कितनी बड़ी है। तेरी अंहवादिता आज भी इतनी कड़ी है, कि तू आंखें बंदकर दिन में भी अंधा है। तू निशाचरी उलूक है या बंदा है? यहां किसी का खून हरा है, किसी का लाल है। किसी का काला है किसी का दहकता लावा है। वर्ण भी तो खून के अनुसार ही है, आहार का प्रभाव है। तमस, सत्व और राजस का जैसा स्वभाव है, वैसे ही भर देता उसमें बदलते चाव है। कबीर यहां आकर भी क्या करें, या तो वे आएं ही नहीं, या आकर बेमौत मरें। कबीर जैसों का जीना मुहाल है, आदमी की आदमियत पर लग गया सवाल है। जो आदमी आदमियत की बात करे, वहीं उठने लगता बवाल है। सब जगह सियासत का कमाल है। जहां भी देखिए उसी का धमाल है।

झूठों के साथ ही है जमाना। सच्चों का नहीं है कोई कहीं अपना। एक कबीर बेचारा इस युग के कवियों के बीच कबाड़ है। ये चमचों, चापलूसों, चुगलों की चौपाल है। यहां कबीर क्या करेगा, कविता ही निढाल है। कबीर एक साहस का नाम है। पर आज कवियों में वही तो नहीं है। बस जो कह दिया वही सही है। उसी का सम्मान है। उसके हाथ में लेखनी नहीं, व्हाट्सअप की कमान है। जिससे आप सबकी बड़ी अच्छी जान-पहचान है। इतने सबके बाद भी मुझे लगता है कि आज भी एक अदद कबीर चाहिए।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

# SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

## D-10™ Hemoglobin Testing System

### For $HbA_{1c}$, $HbA_2$ and HbF

**Flexible**
to solve more testing needs

**Comprehensive**
B-thalassemia and diabetes testing

**Easy**
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid $HbA_{1c}$ or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है